



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022020-216309
CG-DL-E-22022020-216309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2020/माघ 30, 1941
No. 51]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020/MAGHA 30, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

दिनांक: 19 फरवरी, 2020

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) – आगे सम्मिश्रण (कंपाउंड) में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं” के संबंध में पाटन-रोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठ भूमि

फा.सं 06/03/2019-डीजीटीआर—यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

1. मैसर्स डी सी डब्ल्यू लिमिटेड और मैसर्स केम वन केमप्लास्ट प्रा. लि. (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड - आगे सम्मिश्रण (कंपाउंड) में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन रोधी शुल्क की जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।
2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/3/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई थी, ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।
3. प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए अंतरिम शुल्कों की सिफारिश करना उचित समझा और दिनांक 12 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. 6/3/2019-डीजीटीआर के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए, जिसमें चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल्य की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। तदनुसार केंद्र सरकार ने दिनांक 26 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 33/2019- सीमा शुल्क के तहत चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया, जो 6 माह के लिए वैध है।

ख. क्रिया-विधि

4. प्राधिकारी द्वारा इस जांच के संबंध में निम्नलिखित वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 5 के उप-नियम (5) और द्विपक्षीय वचनबद्धताओं के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही आरंभ करने से पहले पाटन-रोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को अधिसूचित किया है।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध आयातों की पाटन-रोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 28 मार्च, 2018 को प्रकाशित एक अधिसूचना जारी की थी।
 - iii. भारत में स्थित चीन और कोरिया के दूतावासों को नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार जांच शुरू करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वे चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से निर्यातकों/ उत्पादकों को यह परामर्श दें कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें।
 - iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) और 6 (3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदकों द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय भाग की प्रति उपलब्ध कराई गई है।
 - v. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को पाटनरोधी जांच शुरू करने की सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार 40 दिनों के भीतर

निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने और लिखित में अपने विचारों से अवगत करने का अवसर प्रदान किया है।

1.	शानडोंग गाओक्सिन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
2.	हांगझाऊ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
3.	शानडोंग याडा न्यू मेटेरियल कंपनी लिमिटेड
4.	नोविस्टा, चीन जन. गण.
5.	शानडोंग क्यूई न्यू मेटेरियल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
6.	सनडोव पोलीमर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
7.	शानडोंग जियांगशेन्ग न्यू मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
8.	हनवाहा केमिकल कार्पोरेशन, कोरिया

vi. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर भेजे हैं:

1.	शानडोंग गाओक्सिन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
2.	शानडोंग पुजी रबड एंड प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
3.	हांगझाऊ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
4.	वेईफांग संडो केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
5.	शानडोंग क्यूई न्यू मेटेरियल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
6.	शानडोंग जियांगशेन्ग न्यू मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
7.	हनवाहा केमिकल कार्पोरेशन, कोरिया (एच. सी. सी.)
8.	हनवाहा कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य (एच. सी.)

vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं का पत्र भेजे थे :

1.	आला केमिकल्स लिमिटेड
2.	अपोलो पाईप्स लिमिटेड
3.	अजय इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड
4.	अजय पोलीमर्स
5.	बोथारा एग्रो ईक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
6.	डेसाना पोली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
7.	ल्यूब्रीजोल एडवांस्ड मेटेरियल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
8.	बेसिल प्रोम्ट विनायल प्राईवेट लिमिटेड
9.	फ्लोवेकन पोली प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड प्लाट
10.	कनकाई पाईप्स एंड फिटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	हिल लिमिटेड
12.	एचपी इंटरनेशनल
13.	कर्ण पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	केल्विन प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
15.	किसान मोल्लिंग्स लिमिटेड
16.	कृषि पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड

17.	न्योसील एडहेसिव प्राईवेट लिमिटेड
18.	पिडलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
19.	प्रेसिशन प्लास्टिक इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
20.	परम पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	प्रिंस पाईप्स एंड फिटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	प्रिंस सीवर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	पुष्प ग्लोबल कंपनी
24.	आर. सी. प्लास्टो टेक्स एंड पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	रेवा पोली प्लास्ट
26.	सागर पोलीटेक्निक लिमिटेड
27.	स्पेक्ट्रा पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	स्टार इंडस्ट्रीज
29.	स्टार पीवीसी पाईप्स एंड फिटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	सब्रे केटल केम प्राईवेट लिमिटेड
31.	सुधाकर इरीगेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	सुमो पोलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
33.	दि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
34.	सूर्य रोशनी लिमिटेड
35.	वेस्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
36.	वाटरफ्लो पाईपिंग सिस्टम
37.	वाटर टेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
38.	एबक इंडस्ट्रीज
39.	ऐसी पोली प्लास्ट
40.	चेम्पियल कमर्शियल कंपनी लिमिटेड
41.	गौरीशंकर पोलीमर्स
42.	एच सेलिक्स एंड कंपनी
43.	मॉस एडिटाईव्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	मयूर डाईस एंड केमिकल कार्पोरेशन
45.	मीट मार्किटिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
46.	नवयुग केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	ओशो पोलीमर्स
48.	ओवरसीज पालीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	पोलीमान इंडिया लिमिटेड
50.	प्रयाग पोलीमर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
51.	प्रिंस मार्किटिंग
52.	साई एक्विजम
53.	सालासर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	श्रीजी इम्पेक्स
55.	सुशीला परमार इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
56.	सिनर्जी इंडस्ट्रीज
57.	एस्ट्रेल पोलीटेक्निक लिमिटेड

- viii. जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :

1.	सुशीला परमार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2.	एच आई एल लिमिटेड
3.	वीटस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
4.	प्रिंस पाईप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड
5.	बेसिल प्रोम्पट विनाईल प्राइवेट लिमिटेड
6.	गौरीशंकर पोलिमर्स

- ix. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित एसोसिएशनों को भी भेजी थीं और उनसे टिप्पणियां मांगी है:

1.	ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
2.	आर्गेनाइजेशन ऑफ पेपर प्रोसेसर ऑफ इंडिया (ओपीपीएल)
3.	महाराष्ट्र पी वी सी पाईप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
4.	ऑल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
5.	आंध्र प्रदेश प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
6.	टीएन पी वी सी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

- x. उपरोक्त किसी भी एसोसिएशन ने जांच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया। तथापि अल्काली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी पी एम ए) से भारतीय उत्पादकों द्वारा पहले से किए गए निवेशों की संरक्षा करने और उद्योग का विश्वास बहाल करने में मदद के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

- xi. जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :

1.	एच पी इंटरनेशनल
2.	प्रेसिशन प्लास्टिक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
3.	मॉस एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	एस्ट्राल पोलिटेक्निक लिमिटेड
5.	जियांगसू ली एवं मैन केमिकल लि०
6.	चाइना क्लोर – अलकाली इंडस्ट्री एसोसिएशन
7.	कनाडियन स्पेशियलिटी विनाइल

- xii. निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया अथवा इस जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान नहीं की, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

- xiii. दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 30 सितंबर, 2018 तक (18 महीनों) की जांच की अवधि के लिए जांच की गई थी। तथापि, क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और जांच की अवधि शामिल थी। क्षति का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़ों की छोटी लम्बाई को ध्यान में रखते हुए जांच की अवधि को तिमाहियों में विभाजित किया गया है।

- xiv. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) और प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के व्यौरें प्रदान करें।
- xv. आवेदकों ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से प्राप्त सौदा-वार आयात संबंधी डाटा पर भरोसा करके चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन का आरोप लगाया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत करते समय आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर भरोसा किया था। जांच शुरू होने के बाद प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस और डीजी सिस्टम से भी सौदा-वार आयात संबंधी डाटा प्राप्त किए और डीजीसीआई एंड एस की तुलना में डीजी सिस्टम में सूचित की गई अधिक मात्रा को देखते हुए डीजी सिस्टम के डाटा पर भरोसा करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए। तथापि, प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिए कि आवेदन में बताई गई आयातों की मात्रा प्रारंभिक जांच परिणामों में बताए गए आयातों की मात्रा से काफी कम है। विस्तृत जांच के बाद यह पाया गया कि डीजी सिस्टम ने तीन प्रकार के आयातों अर्थात् घरेलू खपत के लिए बिल प्रविष्टि, एक्स बांड बिल प्रविष्टि और वेयर हाउसिंग के लिए बिल प्रविष्टि वाले आंकड़े बताए हैं। यह नोट किया गया है कि वेयर हाउसिंग के लिए दी गई बिल प्रविष्टि और घरेलू खपत के लिए दी गई बिल प्रविष्टि को ही माना जाना चाहिए था ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। यह भी नोट किया गया है कि डीजीसीआई एंड एस केवल घरेलू खपत के लिए बिल प्रविष्टि और वेयर हाउसिंग के लिए बिल प्रविष्टि के आधार पर ही आंकड़े सूचित करता है। इसे देखते हुए अब प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदा-वार डाटा पर वर्तमान जांच परिणामों के प्रयोजन से भरोसा किया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि प्रारंभिक जांच परिणामों में डीजीसीआई एंड एस डाटा पर विचार किया गया होता तो केवल आयातों की मात्रा ही कम होती। तथापि, आयातों की मात्रा में इसके परिणामस्वरूप हुई वृद्धि से प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो वही रहा अर्थात् संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह नोट किया गया है कि डीजीसीआई एंड एस डाटा में सूचित आयात कीमतों और प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों में विचार किए गए आंकड़े लगभग वही हैं।
- xvi. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों/ सूचना का आवश्यकता के अनुसार स्थल पर सत्यापन किया गया था। वर्तमान जांच के प्रयोजन से आवश्यक दोष सुधार करके ऐसी सत्यापित सूचना पर भरोसा किया गया है।
- xvii. चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा भरे गए डाटा के लिए डेस्क सत्यापन किया गया था :-
1. शानडोंग गाओक्सिन केमिकल कं० लि०, चीन जन. गण.
 2. शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कं० लि०, चीन जन. गण.
 3. वाइफांग सुंडो केमिकल्स कं० लि०, चीन जन. गण.
 4. शानडोंग जुयी न्यू मैटेरियल्स कं० लि०, चीन जन. गण.
 5. शानडोंग जियांगशेन्ग न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं० लि०, चीन जन. गण.
- xviii. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बनाने व बेचने की अनुकूल लागत की गणना की गई ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुबंध-II में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के संदर्भ में गैर-क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) का निर्धारण किया गया है।

- xix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 19 अगस्त, 2019 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। इसके अलावा ऑटोमोटिव टायर्स मैनुफैक्चरर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन को देखते हुए दूसरी मौखिक सुनवाई 3 दिसम्बर, 2019 को हुई। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए उन्हें मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित में दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया गया था।
- xx. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय भाग उपलब्ध कराया।
- xxi. जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां संगत पाए गए, प्राधिकारी द्वारा उन्हें इस उचित जांच परिणाम में शामिल किया गया है।
- xxii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों पर आवश्यकता के अनुसार विचार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया था।
- xxiii. जहां कहीं भी हितबद्ध पक्षकार ने सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना वर्तमान जांच के दौरान प्रदान नहीं की अथवा जांच में अवरोध डाला है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणामों में दर्ज किया है।
- xxiv. इस जांच में निहित आवश्यक तथ्यों का एक प्रकटीकरण विवरण, जो वर्तमान जांच परिणामों का आधार होता है, दिनांक 29.01.2020 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था। घरेलू उद्योगों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटीकरण उपरांत के विवरणों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में जहां तक संगत पाया गया, विचार किया गया है।
- xxv. *** हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है जिस पर प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत विचार किया गया है। कोष्ठक () में दी गई सूचना नकारात्मक संख्या/ रेंज को दर्शाती है।
- xxvi. प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच में जांच की अवधि के दौरान प्रचलित औसत विनिमय दर 1 यूएस डालर = 66.61 रूपए को अपनाया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सी पी वी सी) – आगे सम्मिश्रित (कंपाउंड) में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं” है।

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- सीपीवीसी रेसिन और कंपाउंड एक ही वस्तु है और इसे दो अलग-अलग वस्तुओं के रूप में नहीं देखा जा सकता।
 - सीपीवीसी रेसिन को कंपाउंड में बदलने के लिए शामिल उत्पादन प्रक्रिया मात्र वृद्धि की प्रक्रिया है क्योंकि :-

- क. कंपाउंडिंग के लिए अधिक कुशल श्रमिक होना जरूरी नहीं है।
 - ख. कंपाउंडिंग न तो अत्यधिक तकनीकी प्रक्रिया है और न ही अधिक श्रम वाली प्रक्रिया है।
 - ग. कंपाउंडिंग में अधिक मानवीय कार्य की जरूरत नहीं पड़ती।
 - घ. कंपाउंडिंग में निवेश महत्वपूर्ण नहीं है।
 - ङ. कंपाउंडिंग एक पक्षकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके पास यहां तक कि प्रौद्योगिकी भी नहीं है और यह रेसिन उत्पादक द्वारा प्रदान की जा रही है।
 - च. कंपाउंडिंग से बहुत ही कम मूल्य वर्धन होता है।
- iii. मूल्य वर्धन के लिए अतिरिक्त मूल्य/ शामिल अन्य कच्चा माल पूरी तरह से महत्वहीन है।
 - iv. अन्य कच्ची सामग्री शामिल करने के कारण दो उत्पाद टाइप की कीमतों में अंतर से तात्पर्य यह नहीं है कि कंपाउंड उत्पादकों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया है।
 - v. रेसिन एक मध्यवर्ती उत्पाद है, जिसे पाइप बनाने के लिए प्रयुक्त कंपाउंड में परिवर्तित किया जाना होता है।
 - vi. पूरा रेसिन कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किसी अन्य अनुप्रयोगों में खपत नहीं होती।
 - vii. रेसिन को जैसा है वैसे इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसे आगे प्रसंस्कृत करके कंपाउंड में बदला जाता है जिससे पाइप और फिटिंग बनाए जाते हैं।
 - viii. केवल विभिन्न उत्पाद टाइप के उत्पादन की लागत में अंतर होने से उन्हें अलग उत्पाद नहीं माना जा सकता।
 - ix. प्राधिकारी ने विगत जांचों जैसे पेरोक्सो सल्फेट, कास्टिक सोडा, ग्लास फाइबर में जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में अनेक उत्पादों को रखा था।
- ग. **2 सी पी एम ए और आई एम ए आई द्वारा किए गए अनुरोध**
7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी पी एम ए) और अल्काली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आई एम ए आई) द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- i. सी पी वी सी रेसिन को प्रसंस्करण करके कंपाउंड में बदला जा रहा है। अतः प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क के दायरे के तहत संबद्ध देश के मूल की सी पी वी सी रेसिन से बने गैर-संबद्ध देश से निर्यातित कंपाउंड में शामिल कर सकते हैं। ऐसा पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए कदाचार को कम करने के लिए जरूरी है अथवा उसे लगाना अप्रभावी हो जाएगा।
 - ii. रेसिन से कंपाउंड में परिवर्तन एक बड़ा क्रियाकलाप नहीं है और यहां तक कि उत्पाद की कंपाउंडिंग के बाद भी अनिवार्यतः वही रहता है। इसमें कंपाउंड बनाने के लिए कोई महत्वपूर्ण निवेश अथवा तकनीकी विशेषज्ञता शामिल नहीं होती। रेसिन को इस्तेमाल में लाने से पूर्व इसे आवश्यक रूप से कंपाउंड में बदलना होता है। अतः यह प्रक्रिया उत्पाद के अनिवार्य गुणों को नहीं बदलती, केवल संगत अनुप्रयोगों के लिए इसे इस्तेमाल करने योग्य बनाती है।

ग. 3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्यातकों/ आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. विचाराधीन उत्पाद में दो उत्पाद निहित नहीं बल्कि केवल एक ही उत्पाद शामिल होना चाहिए।
- ii. चूंकि सी पी वी सी कंपाउंड की मात्रा न्यूनतम है, इसलिए अलग किए जाने की जरूरत है।
- iii. आवेदक ऐसे उत्पाद को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो संबद्ध देशों से वास्तविक आयातों से काफी अलग है।
- iv. सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड एक दूसरे से भिन्न हैं और दोनों उत्पादों का केवल एक ही जांच में आकलन करना केवल घरेलू उद्योग के आधार, पाटन और क्षति के संबंध में निम्नलिखित कारणों से जोखिम को नजरअंदाज करके किया जा सकता है :
 - क. रेसिन और कंपाउंड विभिन्न स्रोतों और विभिन्न निर्माताओं से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।
 - ख. रेसिन और कंपाउंड की विभिन्न कीमतों के कारण उत्पाद को अलग से आकलित किया जाना चाहिए।
 - ग. विभिन्न उत्पादों को एक में मिलाना कानून के अनुसार नहीं है।
 - घ. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उत्पादों को समेकित नहीं किया जाना चाहिए।
 - ङ. लुब्रिजोल, जो संबद्ध वस्तुओं का एक ही उत्पादक है, उस पर विचार नहीं किया गया। इससे डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के निर्माताओं को केवल इस कारण से जांच से बाहर होना पड़ा कि वे मध्यवर्ती उत्पाद के आयातक हैं।
- v. सी पी वी सी कंपाउंड का निर्माण सी पी वी सी रेसिन से उत्पादन का अगला कदम है और इस कारण से अलग उत्पाद है :
 - क. सी पी वी सी कंपाउंड की उत्पादन प्रक्रिया सी पी वी सी रेसिन से भिन्न है।
 - ख. सी पी वी सी कंपाउंड और सी पी वी सी रेसिन के उत्पादन की लागत में भिन्नता है जो 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक है।
 - ग. सी पी वी सी रेसिन के कई निर्यातक उत्पादक सी पी वी सी कंपाउंड के उत्पादक बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं क्योंकि यह एक उच्च तकनीकी प्रक्रिया है।
 - घ. सी पी वी सी रेसिन सी पी वी सी कंपाउंड का एक विकल्प नहीं है, क्योंकि दोनों का वाणिज्यिक तौर पर व्यापार किया जाता है और उन्हें भिन्न तथा अलग माना जाता है।
 - ङ. रेसिन और कंपाउंड की बिक्री कीमतों में तीन गुणा तक का बड़ा अंतर है। यह तथ्य कि उत्पाद एक 'बढ़त की प्रक्रिया' होती है, उससे ऐसे दो उत्पाद नहीं बनते कि वे एक दूसरे से भिन्न हों।
 - च. रेसिन से कंपाउंड के लिए आवश्यक अतिरिक्त कच्चे माल की कीमत पर मूल्य निर्धारण के प्रयोजन से विचार किया जाना जरूरी है।
 - छ. सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड की कीमतों में काफी अंतर होता है, जो घरेलू उद्योग की आयात कीमतों और एन आई पी से देखा जा सकता है।
 - ज. आयात कीमत में करीब 57 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक का अंतर है और गैर-क्षति कीमतों में करीब 29 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक का अंतर है जबकि ये दोनों ही वस्तुएं एक ही उत्पाद मानी जा रही हैं।
- vi. घरेलू उद्योग ने स्वयं ही इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रेसिन से सी पी वी सी कंपाउंड का उत्पादन एक अत्यंत बढ़त की प्रक्रिया है।

- vii. आन्ध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट (सी ई एस टी ए टी) के अनुसार ऐसे उत्पाद जो किसी देश से भारत में आयात नहीं किए जा रहे हैं, उनसे उद्योग को कोई भी क्षति होना नहीं माना जा सकता और इसीलिए उत्पादों की ऐसी श्रेणी पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जा सकता।
- viii. विगत में भी प्राधिकारी ने मध्यवर्ती और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए व्यक्तिगत और अलग जांचें की हैं।
- ix. आवेदक का सी पी वी सी संयंत्र का यह दावा कि एक पूंजी सघन परियोजना है अ और आधारहीन है। दावा की गई ऐसी उच्च लागत 7-8 वर्षों पहले भी और आज की परिस्थिति में नहीं है।
- x. फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स के लिए हुई जांच में, जो चीन जन. गण. से भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों से संबंधित थी, प्राधिकारी ने “फ्रंट एक्सल बीम” और “स्टीयरिंग नकल” के लिए घरेलू उद्योग के आधार, क्षति मानदंडों और आयात की मात्रा का अलग अलग आकलन किया है।

ग.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 9 घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु से संबंधित मामलों के संबंध में किए गए अनुरोध की निम्नलिखित अनुसार जांच की गई है।
10. वर्तमान जांच के प्रयोजन से विचाराधीन उत्पाद “क्लोरीनेटेड पोलिविनाइल क्लोराइड (सी पी वी सी) – आगे सम्मिश्रण (कंपाउंड) में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं” है।
11. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत है। डीजीसीआई एंड एस और डी जी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह दर्शाया गया है कि इस उत्पाद को इन उप-शीर्षों 39042110, 39042190, 39042210, 39042290 और 39049000 के तहत आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
12. उत्पाद को पोलिविनाइल क्लोराइड रेसिन (सस्पेंशन पी वी सी/मास पी वी सी के फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन रिएक्सन के द्वारा क्लोरिनेशन करके उत्पादित किया जाता है और यह काफी अधिक नरम होता है तथा स्टैंडर्ड पी वी सी से अधिक तापमान सहन कर सकता है। इसमें क्लोरीन की मात्रा निर्माता से निर्माता भिन्न हो सकती है। रेसिन (सी पी वी सी कंपाउंडिंग) में विभिन्न योगिक शामिल किए गए हैं ताकि सामग्री को प्रसंस्करण के योग्य बनाया जा सके। इन योगिक में स्टेबलाइजर्स, लुब्रिकेंट, इम्पैक्ट मोडिफायर्स, प्रोसेसिंग वस्तुएं, पिगमेंट शामिल हो सकती हैं।
13. याचिकाकर्ताओं ने यह बताया है कि सी पी वी सी आदर्श रूप से स्व-समर्थक निर्माणों के लिए उपयुक्त होता है जहां तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट (90 डिग्री सेल्सियस) तक विद्यमान होता है। इसे ज्वलित करना बहुत कठिन होता है और जब यह ज्वाला के सीधे संपर्क में नहीं होता है, तो यह स्वतः बुझ जाता है। इसे आवासीय के साथ-साथ वाणिज्यिक निर्माण कार्यों में जल की पाईपिंग प्रणालियों में सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह 40 °C से 50 °C (104 °F से 122 °F) तक अथवा उससे अधिक के तापमान में जल अपघर्षण प्रतिरोधन कर सकता है। इसे आवासीय के साथ-साथ वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों में गर्म और ठंडे जल प्लंबिंग संवितरण, अग्नि संरक्षण, रिकलेम्ड वाटर पंपिंग (पीले पाईप), चिल्ड वाटर पाईपिंग, हाईड्रोनिक पाईपिंग और संवितरण (रेडिएटर्स, फैन क्वाइल्स आदि) के लिए प्रयुक्त किया जाता है और साथ ही इसका प्रयोग अधिकतर औद्योगिकीय और प्रसंस्करण पाईपिंग अनुप्रयोग के लिए भी किया जाता है।
14. सी पी वी सी काफी डक्टाइल होता है जो अधिक लचीलापन और अपघर्षण प्रतिरोधकता होने देता है। अतिरिक्त रूप से, सी पी वी सी की यांत्रिक शक्ति उसे उन स्थितियों में धात्विक पाइप की कई किस्मों को

बदलने के लिए अर्थक्षम घटक बना देता है जहां धातु की क्षरण के लिए संवेदनशीलता उसके प्रयोग को सीमित करती है। सी पी वी सी को अंत प्रयोक्ता अनुप्रयोगों के आधार पर मुख्यतया दो ग्रेडों में वर्गीकृत किया जाता है, नामतः (क) पाईप ग्रेड और (ख) फिटिंग ग्रेड। इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पाद को दो प्रसंस्करणों नामतः ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस के माध्यम से निर्मित किया जा सकता है। तथापि, किसी भी पक्षकार उत्पादों के इन रूपों में विभिन्न प्रक्रियाओं अथवा विभिन्न ग्रेडों के कारण कोई अंतर न होने की सूचना नहीं दी है।

15. नियमावली के नियम 2 (घ) के तहत समान वस्तु के संबंध में यह प्रावधान है कि :

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

16. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की है कि सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड अलग-अलग उत्पाद हैं, क्योंकि दोनों ही प्रसंस्करण की विभिन्न अवस्थाओं में तैयार किए जाते हैं। आवेदक और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सी पी वी सी रेसिन एक मध्यवर्ती उत्पाद है, जिसे अंततः पाइपों का निर्माण करते समय कंपाउंड में परिवर्तित किया जाता है और सी पी वी सी रेसिन का आय कोई स्वतंत्र उपयोग में नहीं लाया जा सकता और इसे उपयोगी बनाने के लिए कंपाउंड में प्रसंस्कृत करना अनिवार्य होता है, यह तथ्य प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नहीं उठाया गया है। यह नोट किया जाता है कि उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत में अंतर ही केवल एक उत्पाद को दूसरे उत्पाद से भिन्न बताने का मापदंड नहीं है। कंपाउंड उसे उपयोग बनाने के लिए सी पी वी सी रेसिन के रूप में आगे प्रसंस्करण किए बिना कार्य है। यह भी नोट किया जाता है कि कंपाउंड में बुनियादी तौर पर कोई पर्याप्त विनिर्माण क्रियाकलाप किए बिना रेसिन के साथ एडीटिव (यौगिक) को मिलाना शामिल है। अतः सी पी वी सी रेसिन को कंपाउंड में बदलने की प्रक्रिया मात्र एक बढ़त की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में उत्पाद के आवश्यक गुण नहीं बदलते बल्कि इसे उपयोग बनाया जाता है। यह तथ्य कि रेसिन को कंपाउंड में बदलने की प्रक्रिया से टैरिफ कोड नहीं बदलता, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह प्रक्रिया बढ़त की प्रकृति की है। यहां तक कि सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड के बीच के उत्पादन चरण में मूल्य वर्धन की गणना में यदि यौगिक (एडीटिव) पर विचार किया जाए तो सी पी वी सी रेसिन कंपाउंड के निर्माण के लिए प्रयुक्त सबसे अधिक कीमती घटक है।

इसके अलावा सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड के लिए एंड यूज मार्केट भी एक समान है। सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड की एक ही रासायनिक संरचना है और सी पी वी सी रेसिन में कंपाउंड के लिए अनिवार्य गुण होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुरोध में यह स्पष्ट है कि भारत में अधिकतर कंपाउंड निर्माता सी पी वी सी रेसिन का अयात कर रहे हैं और उसे कंपाउंड में बदल रहे हैं। इसे देखते हुए कंपाउंड को पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए क्षेत्राधिकार से बाहर करने का मतलब संबद्ध देशों से भारत को कंपाउंड का सीधे निर्यात करना है, जिससे पाटनरोधी शुल्क लगाने की पूरी कार्रवाई करने का प्रयोजन ही विफल हो जाता है। उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने यह पाया कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में क्लोरिनेटेड पोलिविनाइल क्लोराइड (सी पी वी सी) में रेसिन और कंपाउंड, दोनों एक ही वस्तु के रूप में शामिल हैं।

17. संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। क्लोरिनेटेड पोलिविनाइल क्लोराइड (सी पी वी सी) – चाहे आगे सम्मिश्रण (कंपाउंड) में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं, जो भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित है और जो संबद्ध देशों से आयातित है, दोनों ही वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमतों, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में ला सकते हैं।

निष्कर्ष यह है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. आवेदकों ने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध है।

ख. आवेदन दायर करते समय, भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक ही उत्पादक था।

ग. मै० केम वन कैमप्लास्ट प्रा० लि० ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का पाटन होने से परियोजना पर काफी कार्य करने के बाद भी इसके निवेश पर रोक लगी हुई है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में यह अनुरोध किया है :

क. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक ही उत्पादक नहीं है और इसीलिए वर्तमान याचिका पूर्णतया अप्रयुक्त और अपर्याप्त है।

ख. यह उद्योग नया नहीं है।

ग. सी पी वी सी कंपाउंड के एक प्रमुख उत्पादक लुब्रिजोल इंडिया ने वर्तमान जांच को केवल इस कारण से नजरअंदाज किया है कि यह समिश्रित जांच है। प्राधिकारी ने इसके लिए कोई कारण नहीं दिया है।

घ. मै० केम वन कैमप्लास्ट प्रा० लि० को घरेलू उद्योग के दायरे में तब तक पात्र नहीं माना जा सकता जब तक कि वह समान वस्तु के निर्माण और उत्पादन में शामिल न हो।

ङ. चीन जन. गण. फ्लेक्स यार्न के संबंध में एक पूर्व जांच में प्राधिकारी ने रेमंड लक्जरी कॉटन की स्थिति की जांच नहीं की थी, जो जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा था।

च. आर आई एल ने भी संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है।

छ. प्रतिवादी का प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को "अस्थापित" माना जाए, क्योंकि यह इस आधार पर कार्य करता है कि घरेलू उद्योग की स्थापना संबद्ध आयातों के कारण काफी प्रभावित हो सकती है।

ज. फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल की जांचों के लिए भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आधार को स्पष्ट करने के लिए उल्लेख किया गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

21. यह याचिका मै० डी सी डब्ल्यू लि० और मै० केम वन कैमप्लास्ट प्रा० लि० द्वारा दाखिल की गई है। बाद में आवेदन का मै० मेघमानी फाइनकैम लि० द्वारा भी समर्थन किया गया। तीन संस्थाओं में से मै० डी सी डब्ल्यू लि० ही एकमात्र ऐसी कंपनी है, जो सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड का जांच की अवधि में उत्पादन करने में शामिल है जबकि अन्य दो कंपनियां अर्थात् मै० केम वन कैमप्लास्ट प्रा० लि० और मै० मेघमानी फाइनकैम लि० ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है। मै० मेघमानी फाइनकैम लि० तो केवल बाजार की स्थिति के आधार पर परियोजना की स्थापना करने की शुरुआती अवस्था में है। तथापि, उन्होंने आवेदन की भागी होने की इच्छा व्यक्त की है। जहां तक मै० केम वन कैमप्लास्ट प्रा० लि० का संबंध है, उन्होंने परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है और उन्होंने प्रौद्योगिकी अंतरण सहित संयंत्र की स्थापना के लिए काफी जमीनी कार्य कर लिया है। उसने परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। अतः प्राधिकारी ने मै० डी सी डब्ल्यू लि० और मै० केम वन कैमप्लास्ट प्रा० लि० को जांच शुरू करने और प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में माना है।
22. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मै० केम वन कैमप्लास्ट प्रा० लि० को घरेलू उद्योग के दायरे में तब तक पात्र नहीं माना जा सकता जब तक कि वह समान वस्तु के निर्माण और उत्पादन में शामिल न हो। जबकि यह नोट किया गया है कि मै० केम वन ने परियोजना पूरी कर ली है और प्रौद्योगिकी के उत्पादन सहित संयंत्र की स्थापना के लिए काफी जमीनी कार्य कर लिए हैं और अपनी परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है, यह भी देखा गया है कि कंपनी को अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पूर्व कई कदम अभी उठाने हैं। अतः प्राधिकारी ने यह उपयुक्त समझा कि मै० केम वन कैमप्लास्ट प्रा० लि० को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाए और केवल मै० डी सी डब्ल्यू लि० को ही घरेलू उद्योग माना जाए।
23. सी पी वी सी कंपाउंड के कई उत्पादक हैं, जो या तो डी सी डब्ल्यू से सी पी वी सी रेसिन की खरीद कर रहे हैं या रेसिन का आयात कर रहे हैं और उसे पाइप बनाने के लिए सी पी वी सी कंपाउंड के निर्माण के लिए प्रसंस्कृत कर रहे हैं। जिन कंपनियों के पास सी पी वी सी रेसिन के लिए निर्माण सुविधाएं नहीं हैं लेकिन खरीदे गए सी पी वी सी रेसिन (स्वदेशी और/ या आयातित) से केवल कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, जिनमें लुब्रिजोल इंडिया शामिल है। उन्हें इस कारण से नियम 2 (ख) के तात्पर्य से “घरेलू उद्योग” के रूप में विचार नहीं किया है कि (क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “क्लोरीनेटेड पोलिविनाइल क्लोराइड (सी पी वी सी) – चाहे आगे सम्मिश्रण (कंपाउंड) में प्रसंस्कृत हो अथवा न हो”, है। अतः संबद्ध वस्तु सी पी वी सी रेसिन अथवा सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड (सम्मिश्रण) है। इस प्रकार घरेलू उत्पादकों के लिए यह आवश्यक है कि वे पात्र घरेलू उद्योग बनने के लिए सी पी वी सी रेसिन के एक निर्माता हों, चाहे वे रेसिन के सम्मिश्रण (कंपाउंड) के कारोबार में हों अथवा नहीं, और (ख) कंपाउंड (सम्मिश्रण) से सी पी वी सी रेसिन प्राप्त कर रहे हैं वे इसे केवल डी सी डब्ल्यू लि० से ही घरेलू तौर पर खरीदें क्योंकि यही सी पी वी सी रेसिन का एकमात्र उत्पादक है और इसीलिए उनकी उत्पादन की मात्रा को शामिल करना दोहरी गणना होगी क्योंकि डी सी डब्ल्यू लि० का उत्पादन पहले ही शामिल किया जा चुका है।
24. मै० डी सी डब्ल्यू लि० संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का न तो आयातक है अथवा न ही निर्यातक है और न ही उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। डी सी डब्ल्यू लि० सी पी वी सी के निर्माण के लिए संबद्ध देशों से अन्य देशों से एम पी वी सी का आयात कर रहा है। डी सी डब्ल्यू लि० विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र उत्पादक होने के कारण संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन में बड़े अनुपात में हिस्सा रखता है और नियम 2 (ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में यह अनुरोध किया है :

- क. हनवा केमिकल कारपोरेशन का भारत में एक बिक्री कार्यालय है लेकिन इसके बारे में ई क्यू आर के अगोपनीय पाठ में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
- ख. इस तथ्य के बावजूद कि कैप्टिव कच्चे माल और यूटिलिटीज का विवरण हनवा केमिकल कारपोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उनके नामों के लिए उत्तर के अगोपनीय पाठ में गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- ग. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार, हनवा केमिकल कारपोरेशन कंपनी के भीतर, ग्रुप कंपनियों के साथ और अन्य कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण अनुसंधान व विकास क्रियाकलाप करता है।
- घ. हनवा केमिकल कारपोरेशन पी वी सी और क्लोरीन का सीमित उत्पादन करता है और इस प्रकार से निर्यातक को यह स्थापित करने की जरूरत है कि अंतरण की कीमत में उचित बाजार मूल्य दर्शाया गया है। तथापि, उत्पादक द्वारा उत्तर के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- ङ. प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे वाले आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया है, जिसने अन्य हितबद्ध पक्षकारों की तर्कसंगत समझ का पता चलता है।
- च. रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2006 (202) ईएलटी 23 (एस सी)] का संदर्भ गलत दिया गया है क्योंकि निर्णय में उक्त डाटा प्रदान करने वाले पक्षकार से प्राधिकारी द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे के बारे में कहा गया है।
- छ. आवेदक ने ऐसी सभी सूचना प्रदान की हैं, जिनके लिए उसकी अगोपनीय आधार पर प्रदान करने की जिम्मेदारी थी।
- ज. चूंकि अनेक उत्पादक भारत में क्षमताएं स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, अतः परियोजना रिपोर्ट अत्यधिक गोपनीय है और इसीलिए साझा नहीं की जा सकती।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की गोपनीयता के दावे के संबंध में इस प्रकार तर्क दिए हैं :

- क. जिस सूचना के लिए आवेदक द्वारा गोपनीय होने का दावा नहीं किया गया है, उसके लिए प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने याचिका में उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, इन्वेन्ट्री तथा उपरोक्त क्लोजिंग स्टॉक के संदर्भ में सूचीबद्ध आंकड़ें प्रदान किए हैं, तथापि, प्राधिकारी तो प्रारंभिक जांच परिणामों में ऐसी सभी सूचना को गोपनीय मानकर एक कदम आगे बढ़ गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में स्वयं गोपनीयता का दावा नहीं किया गया था। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2006 (202) ईएलटी 23 (एस सी)] मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय तथा साथ ही भारत संघ बनाम मेघमानी आर्गेनिक्स लि० [2016 (340) ईएलटी 449 (एस सी)] मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की बड़ी बेंच के निर्णय का सीधा उल्लंघन है, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने यह पाया था कि पाटनरोधी नियम निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीयता के दावे का कोई अधिकार प्रदान नहीं करते और प्राधिकारी को अपने आप ही गोपनीय मान लेने की कोई शक्तियां नहीं हैं।
- ख. निर्यात कीमतों में किए गए समायोजन के लिए उत्तर के अगोपनीय पाठ में गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता है।
- ग. आवेदक का अगोपनीय पाठ घरेलू उद्योग के दावे को पर्याप्त रूप से नहीं समझाता।
- घ. आवेदक को परियोजना रिपोर्ट और अन्य दावों की अगोपनीय प्रति प्रदान करने का निदेश दिया जाए।

ड. निवल नियत कीमत में समायोजन के लिए अगोपनीय आवेदन में गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में यह प्रावधान है :

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) (2) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहां कहीं भी जरूरी हुआ स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सार्वजनिक फाइल के रूप में प्रदान किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

च. विविध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :

क. आवेदक द्वारा पहले ही प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए लिखित अनुरोधों में आयात संबंधी डेटा लेने के लिए प्रयुक्त प्रणाली का उल्लेख किया गया है।

ख. प्राधिकारी द्वारा विगत में मैटेरियल रिटार्डेशन के मामले में 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी।

ग. भारत में आयात अन्य संबद्ध देशों से उच्च कीमतों पर आ रहे हैं और अभी भी भारतीय उद्योग खपत में वृद्धि को देख रहा है। यह दर्शाता है कि शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

घ. यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो कोरिया सरकार को भारतीय बाजार में सी पी वी सी की कीमतों में वृद्धि के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए।

ड. ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि उपभोक्ता कच्चे माल को खरीदने और कीमत वृद्धि को समाहित करने में असमर्थ हो रहे हैं।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध इस प्रकार हैं :

- क. प्राधिकारी को भारतीय कानून के तहत ऐसी कोई शक्तियां नहीं हैं कि वह घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए मैटेरियल रिटार्डेशन की स्थिति का समाधान करने के लिए अनंतिम उपाय लागू करने की सिफारिश करे।
- ख. प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ख (1) (ख) (iii) के प्रावधानों के तहत किसी जांच को दर्ज करने में विफल रहे हैं कि जांच के दौरान हुई क्षति को रोकने के लिए शुल्क आवश्यक हैं।
- ग. विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार के तहत, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए मैटेरियल रिटार्डेशन के मामले में अनंतिम शुल्क नहीं लगाए जा सकते।
- घ. प्राधिकारी का "मैटेरियल रिटार्डेशन" का आधार विफल रहा है।
- ङ. प्राधिकारी दिनांक 31 मई, 2019 के क्षति अनुरोधों की जांच करने या रिकार्ड करने में विफल रहे हैं।
- च. प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आंकड़ों का विश्लेषण गलत तरीके से किया गया है और प्रतिवादियों द्वारा उल्लिखित कारकों पर विचार करने में विफल रहा है।
- छ. प्राधिकारी का आवेदन का विश्लेषण कुछ भागों में अधूरा है और वास्तविक आकलन किए गए बिना निष्कर्ष दिया गया है।
- ज. प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को दर्ज नहीं किया गया है। जबकि आवेदक के अनुरोध को दर्ज किया गया है लेकिन उनकी कोई जांच नहीं की गई है।
- झ. प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों के निर्धारण के लिए डीजीसीआई एंड एस डाटा की बजाय डी जी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। प्राधिकारी द्वारा डी जी सिस्टम के डाटा को उपयुक्त मानने और डीजीसीआई एंड एस को गलत मानने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- ञ. आवेदक को आयात संबंधी डेटा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली की एक प्रति प्रदान करने का निदेश दिया जाए।
- ट. सी पी वी सी पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जन हित में नहीं होगा। घरेलू उद्योग का समग्र प्रयोजन ही प्रतिस्पर्धा को खतम करना और एकक्षत्र अधिकार रखना ही इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।
- ठ. सी पी वी सी पर पाटनरोधी शुल्क लगाना एक अनुचित प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाना होगा और इससे दीर्घ अवधि में उनके संगत उद्योगों का मूलभूत हित प्रभावित होगा।
- ड. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से सी पी वी सी की स्थानीय कीमतों में वृद्धि होगी अथवा यह लाभ ऐसे देशों को अंतरित होगा जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है।
- ढ. प्रारंभिक शुल्क लगाने से सी पी वी सी की कीमतों में करीब 30-40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
- ण. अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय सी पी वी सी बाजार को लाभ की बजाय हानि होगी जबकि भारतीय घरेलू उद्योग को वास्तव में कोई पर्याप्त लाभ नहीं होगा।

त. प्राधिकारी द्वारा मैटेरियल रिटार्डेशन के मामले में निश्चित पाटनरोधी शुल्क कम अवधि के लिए (2 या 3 वर्षों के लिए) लगाने की सिफारिश की प्रक्रिया अपनाई गई, चूंकि 5 वर्षों की अवधि के लिए शुल्क की सिफारिश यथोचित नहीं होगी।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न मामलों के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत पाए जाने के अनुसार जांच की गई है जो इस प्रकार है

क. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को मैटेरियल रिटार्डेशन के मामले में अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश करने की शक्तियां नहीं हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमों के किसी भी प्रावधान में यह नहीं कहा गया है कि मैटेरियल रिटार्डेशन के मामले में अनंतिम शुल्क नहीं लगाया जा सकता। प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच में अनंतिम शुल्क की सिफारिश करना नियमों के तहत है।

ख. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को दर्ज नहीं किया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद प्राधिकारी ने मौखिक सुनवाई प्रदान की और पक्षकारों को अपने लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर दाखिल करने का परामर्श दिया। प्राधिकारी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने को देखते हुए दूसरी मौखिक सुनवाई और उसके बाद लिखित अनुरोध तथा प्रत्युत्तर अनुरोध दाखिल करने की अनुमति प्रदान की थी। सभी संगत अनुरोध जांच परिणाम में दर्ज किए गए हैं और उनकी जांच की गई है।

ग. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में डीजीसीआई एंड एस डाटा की बजाय डी जी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा करने का कारण नहीं दिया है, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि डी जी सिस्टम डाटा में सूचित आयातों की मात्रा डीजीसीआई एंड एस डाटा की तुलना में अधिक थी, इसलिए प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के समय डी जी सिस्टम के डाटा अपनाए ताकि संबद्ध वस्तुओं के समग्र निर्यात को शामिल किया जा सके। विस्तृत जांच करने के बाद, यह पाया गया कि डी जी सिस्टम ने तीन प्रकार के आयातों के डेटा सूचित किए हैं जो घरेलू खपत के लिए मंजूर बिल प्रविष्टि, एक्स बांड बिल प्रविष्टि और वेयर हाउसिंग के लिए दी गई बिल प्रविष्टि के आधार पर हैं। यह नोट किया गया है कि वेयर हाउसिंग के लिए दी गई बिल प्रविष्टि और घरेलू खपत के लिए बिल प्रविष्टि को ही सूचित आंकड़ों में शामिल किया जाना चाहिए था ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। यह भी नोट किया गया है कि डीजीसीआई एंड एस केवल घरेलू खपत के लिए बिल प्रविष्टि और वेयर हाउसिंग के लिए बिल प्रविष्टि के आधार पर ही डेटा सूचित करता है। इसे देखते हुए प्राधिकारी ने अब वर्तमान जांच के प्रयोजन से डीजीसीआई एंड एस के सौदा-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीजीसीआई एंड एस डाटा पर यदि प्रारंभिक जांच में विचार किया जाता, तो केवल आयातों की मात्रा कम होती। तथापि, आयातों की मात्रा में परिणामी वृद्धि से प्रवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो वही रहा अर्थात् संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि डीजीसीआई एंड एस डाटा और प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए डाटा में सूचित आयात कीमतें लगभग वही हैं।

घ. इस तर्क के संबंध में कि सी पी वी सी पर शुल्क लगाने से यह जन हित में नहीं होगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्कों का अनिवार्य उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रक्रिया को ठीक करना होता है।

ड. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से सी पी वी सी की स्थानीय कीमतों में वृद्धि होगी अथवा लाभ ऐसे देशों को अंतरित होगा, जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है, यह नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से आयात कीमतें संबद्ध देशों से पाटित कीमतों से अधिक हैं। भारत में पाटनरोधी

शुल्क लगाने से केवल घरेलू उद्योग को मुकाबले का अवसर मिलेगा जिससे भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित हो सकेगा। इससे भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू निर्माण आधार तैयार करने में मदद मिलेगी ताकि भारतीय उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं के घरेलू व वैश्विक उत्पादन, दोनों से लाभान्वित हो सके।

च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्रारंभिक शुल्क लगाए जाने से सी पी वी सी की कीमतों में करीब 30-40 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटनरोधी प्रथा से प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त किया जा सकेगा और इससे घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

छ. पाटन और पाटन मार्जिन

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

संबद्ध देशों के लिए गणना किया गया पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है।

क. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है।

ख. चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान, थाईलैंड या यू एस ए से भारत में आयात कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों देश अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक सामान्य मूल्य दर्शाते हैं।

ग. हितबद्ध पक्षकारों को सामान्य मूल्य के प्रयोजन से विचार किए जा रहे सरोगेट देश को पर्याप्त नोटिस दिए गए थे, क्योंकि इनकी सूचना जांच प्रारंभ अधिसूचना के पैरा 10 में दी गई थी।

घ. चूंकि घरेलू बाजार में खपत कीमत निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है और जहां निर्यातक बार-बार यह कह रहे हैं कि सी पी वी सी रेसिन की कीमतें पी वी सी सस्पेंशन रेसिन की कीमत से दोगुनी है, तो यह स्पष्ट है कि जिन कीमतों पर हनवा ने कोरिया में घरेलू बाजार में सी पी वी सी की बिक्री की है वह सामान्य व्यापार के दौरान की कीमत नहीं है।

ङ. हनवा केमिकल कारपोरेशन ने संभवतः कोरिया में दो या तीन ग्राहकों को वास्तव में उत्पाद की बिक्री की है। अतः यह संभावना है कि कोरियाई उत्पादक की कीमत में "अपने उत्पाद के विकास" की बात हो, जिससे यह कीमतें अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं।

च. हनवा केमिकल कारपोरेशन की उत्पादन की लागत जो प्राधिकारी को प्रदान की गई थी, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती।

छ. धारा 9 क 1 (ग) के प्रावधानों के अनुसार कोरिया गणराज्य के मामले में सामान्य मूल्य कोरिया में संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों पर आधारित हो सकता है।

ज. निर्यात कीमत की गणना के बारे में विवरण व्यापार नोटिस की अपेक्षा के अनुसार प्रदान किया गया है।

झ. प्रारंभिक जांच परिणाम कोरियाई उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन की गणना पर अंतिम जांच परिणामों के लिए विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्पादक यह निर्धारित नहीं पाया है कि कैसे उसकी लागत और बिक्री लागत स्वीकार की जाएगी।

ञ. हनवा केमिकल कारपोरेशन द्वारा दाखिल उत्तरों को अस्वीकार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि निर्यातक ने दाखिल किए उत्तर में महत्वपूर्ण सूचना छिपाई है।

- ट. एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को कीमत और भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत विधिवत समायोजन के बाद निर्धारण के स्तर पर ही प्रतीत होती है और इसलिए इसे सामान्य मूल्य के रूप में विचार किया जा सकता है।
- ठ. सामान्य मूल्य निर्यातक उत्पादक की लागत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, यदि इसे प्रथम शर्त अर्थात् खपत कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों ने उपयुक्त तीसरे देश के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।
- ढ. आयातक ने थाईलैंड से आयात कीमतों को विश्वसनीय न मानने के लिए कोई प्रभाव नहीं दिया है। आयातक द्वारा अपने दाखिल किए गए आयातक प्रश्नावली उत्तर में कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है।
- ण. केवल यह तथ्य कि नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक मामले में यह पाया गया था कि उस मामले के लिए थाईलैंड पर सरोगेट देश के रूप में विचार नहीं किया जा सका था, इसका यह अर्थ आवश्यक नहीं है कि थाईलैंड पर यहां तक कि वर्तमान मामले में भी एक उपयुक्त सरोगेट देश के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।
- त. थाईलैंड से आयात कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बंदरगाह व्यय, विदेशी मालभाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी मालभाड़ा, बैंक प्रभार और लाभ के साथ समायोजित नहीं किया गया है।
- थ. यह तथ्य कि थाईलैंड से आयातों में सीमा शुल्क के रूप में एफ टी ए का लाभ मिला है, असंगत है, क्योंकि आवेदक ने सी आई एफ आयात कीमतों की तुलना की है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :
 - क. माननीय उच्चतम न्यायालय ने शेनयांग मत्सुशिता एस. बैट्री कं० लि० बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि० [2005 (181) ईएलटी 320 (एस सी)] मामले में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है कि चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। प्राधिकारी ने कुल मिलाकर यह जांच करने से चूक की है कि क्या पहला विकल्प वर्तमान जांच में अपनाया जा सकता था। प्राधिकारी ने कहीं भी प्रारंभिक जांच में यह नहीं कहा कि क्यों पहला तरीका किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य को अपनाया नहीं जा सकता।
 - ख. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में सिफारिश करने से पूर्व थाईलैंड सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक उपयुक्त तीसरा देश चुनने का प्रस्ताव नहीं किया। इसके अलावा, उपलब्ध विकल्पों में से सबसे अधिक आयात कीमत वाले देश को चुनने के लिए कोई भी कारण नहीं बताया गया।
 - ग. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक आधार के रूप में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत की आयात कीमत पर विचार करने को स्पष्ट करना होगा।
 - घ. प्रस्तावित देश अथवा उत्पाद के विकास के स्तर पर कोई जांच परिणाम नहीं हैं। थाईलैंड में विकास के स्तर की चीन में विकास के स्तर के साथ तुलना की गई है।
 - ङ. थाईलैंड से आयात भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमतों को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि यह चुने गए सैम्पल के स्रोत के आधार पर होगा, जो अत्यधिक सीमित होगा और वास्तविक भुगतान की गई कीमत अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत को नहीं दर्शाएगा।
 - च. थाईलैंड को चीन के लिए उपयुक्त तीसरे देश के रूप में नहीं माना जा सकता।
 - छ. प्राधिकारी ने एफ टी ए के कारण थाईलैंड और चीन से आयातों पर लागू शुल्कों की दर में भिन्नता पर विचार नहीं किया है।

- ज. चूंकि थाईलैंड से आयातक का भारत में एक संबद्ध आयातक, अर्थात् लुब्रिजोल इंडिया है, इसलिए कीमतों को बारीकी से देखा जाना जरूरी है।
- झ. गुनवालू लाजिस्टिक सर्विस गम्भ बनाम हौप्टजोलेम्पट हम्बर्ग – स्टेड्ट (मामला सी-338/10) के अनुसार तीसरे देश का चयन उपयुक्त होना चाहिए।
- ञ. जापान, थाईलैंड और यू एस ए की आयात कीमतों पर चीन के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के प्रयोजन से विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आयात विशिष्ट लाइसेंस के तहत हैं और इसीलिए उच्च कीमतों पर हैं।
- ट. प्राधिकारी से अनुरोध है कि यदि एम ई टी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो भी निर्यातकों के खपत मानकों पर विचार किया जाए।
- ठ. चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक (एन टी सी एफ) (13 अप्रैल, 2015) द्वारा विगत में समाप्त जांच में थाईलैंड को तीसरे देश के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था।
- ड. हांगझोऊ इलेक्ट्रोकेमिकल न्यू मैटेरियल कं० लि० के उत्तर को जांच में भाग न लेने वाले गैर- संबद्ध उत्पादक के कारण अस्वीकार कर दिया गया। उत्पादक किसी असंगत निर्यातकों को किसी जांच में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
- ढ. शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कंपनी लि० भारत में सी पी वी सी कंपाउंड का निर्यात नहीं कर रहा है लेकिन अभी भी सी पी वी सी कंपाउंड के संबंध में अवशिष्ट दर प्रदान की गई है।
- ण. मै० एच सी सी द्वारा जांच की अवधि के दौरान *** मी. टन की घरेलू बिक्री की गई और भारत को *** मी. टन का निर्यात किया गया, जो भारत को निर्यातों का करीब *** प्रतिशत है। घरेलू बिक्रियां किसी असंगत क्रेता के माध्यम से की गई हैं। घरेलू बिक्रियों की मात्रा सामान्य मूल्य की खपत के लिए उस पर विचार करने हेतु मानदंड को पूरा करती हैं।
- त. पी वी सी क्लोरीन, स्टीम की लागत सी ओ पी में निर्यातक द्वारा ठीक से प्राप्त की गई है।
- थ. प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य के प्रस्ताव के लिए अपनाया गया आधार त्रुटिपूर्ण है। आवेदक द्वारा प्रदान किए गए इनवायस का पता नहीं लगाया जा सकता।
- द. प्राधिकारी ने चीन से कैल्शियम क्लोराइड के लिए जांच में यह निर्धारित किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण कुछ इनवायस के आधार पर नहीं किया जा सकता।
- ध. हनवा कारपोरेशन द्वारा व्यय की गई शुरुआती लागत को कोरियाई लेखांकन मानकों के अनुसार समायोजित किया गया है।
- न. हनवा कारपोरेशन के तथ्यों को छिपाया नहीं गया है। इसने उत्तर में सभी विवरण प्रदान किए हैं।
- ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण
- ज.1 चीन के लिए सामान्य मूल्य
34. चीन से निम्नलिखित उत्पादक निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं :
- क. शानडोंग गाओक्सिन केमिकल कं० लि०
- ख. शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कं० लि०
- ग. हांगझोऊ इलेक्ट्रोकेमिकल न्यू मैटेरियल कंपनी लि०
- घ. वाइफांग सुंडो केमिकल्स कं० लि०

ड. शानडोंग जुयी न्यू मैटेरियल्स कं० लि०

च. शानडोंग जियांगशेन्ग न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं० लि०

35. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत, गैर बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा :

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

36. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए और तीसरे देशों नामतः जापान, थाईलैंड और यू एस ए से भारत में आयात कीमतों के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य का दावा किया है, क्योंकि आवेदक को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य पर संगत सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए जापान, थाईलैंड अथवा यू एस ए से आयात कीमत पर विचार करने के लिए आवेदक के दावे को मानते हुए प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए भारतीय उत्पादक की लागत के आधार पर चीन में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
37. जांच शुरू करने के बाद प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों को जांच शुरू करने की सूचना का उत्तर देने और उनकी बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का निर्धारण करने के लिए संगत सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को गैर बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करके उनकी अपनी लागत/ कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य तय करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नावली भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. की सरकार से भी अनुरोध किया था कि वह चीन में उत्पादकों/ निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने का परामर्श दे। चीन के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और चीन जन. गण. की सरकार को इस संबंध में अपना अनुरोध भेजने के लिए निर्धारित प्रारूप और निर्धारित तरीके से अपेक्षित सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पर्याप्त रूप से अधिसूचित किया। अनेक उत्पादकों/ निर्यातकों ने वर्तमान जांच में उत्तर दिया। तथापि, उनमें से किसी ने भी संगत प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया जिससे कि प्राधिकार यह जांच कर सके कि क्या उनकी लागत और कीमतें बाजार से संचालित थी अथवा नहीं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के दावे को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने नियमावली में विनिर्दिष्ट कोई अन्य वैकल्पिक आधार प्रदान नहीं किया, जिस पर कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाता। हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दावे का विरोध करते समय चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोई भी सूचना प्रदान नहीं की।
38. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए और चीन की किसी भी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दावे का खंडन न करने के कारण प्राधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करना उपयुक्त समझा। पैरा 7 में सामान्य मूल्य के

निर्धारण के लिए अनुक्रम दिया गया है और यह प्रावधान है कि उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंधन के पैरा 7 के तहत प्रदत्त विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर किया जाना है।

39. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने विरोध किया कि उन्हें नियमावली के अनुबंधन-1 के पैरा 7 के अनुसार उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में थाईलैंड को चुनने के संबंध में उन्हें कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किसी उपयुक्त अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को निर्यात की कीमत मानने के लिए आवेदक का दावा जांच शुरू करने संबंधी नोटिस में अपनी तरह से उल्लिखित किया गया था और आवेदन की एक प्रति सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। चूंकि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी कर दिए थे, जिनमें कि थाईलैंड से भारत को निर्यात कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया था और उस पर टिप्पणियां मांगी गई थीं, अतः हितबद्ध पक्षकारों को उपयुक्त अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में थाईलैंड पर विचार करने के प्रस्ताव पर टिप्पणियां भेजने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिला है। यह नोट किया जाता है कि या तो जांच की शुरूआती अवस्था में या प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया है। यहां तक कि प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद भी इनमें से किसी भी पक्षकार ने कोई विकल्प नहीं सुझाया जिसे कि प्राधिकारी चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपना सके।
40. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के लिए एक क्रमबद्ध ढंग से सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार करने के लिए किसी देश के लिए सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंधन-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार करनी होती है। वर्तमान मामले में चूंकि किसी भी निर्यातक ने अनुपूरक प्रश्नावली दाखिल नहीं की है, नियमावली के अनुबंधन-1 के पैरा 7 के तहत दिए गए विकल्प को तलाशने की जरूरत है। पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण अनुक्रम का उल्लेख है और यह प्रावधान है कि उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है या अन्य आधार पर किया जाएगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध 7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न हैं। क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर किया जाना अपेक्षित है। चूंकि थाईलैंड में लागत अथवा कीमत के संबंध में कोई सूचना दर्ज नहीं है। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इसके आधार पर नहीं किया जा सका। इसके अलावा, चूंकि थाईलैंड से भारत को निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की कीमत के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और कानून के तहत सूचीबद्ध "कोई अन्य आधार" अपनाने का विकल्प अपनाया नहीं जा सकता। अतः प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि प्राधिकारी के पास समुचित विकल्प उपलब्ध है जिनसे थाईलैंड से भारत में निर्यात कीमत अपना कर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा सके।
41. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि थाईलैंड पर विकास के स्तर भारत में आयातक के साथ संबंध, एफ टी ए के कारण सीमा शुल्कों में अंतर और विशिष्ट लाइसेंस के कारण अधिक कीमतों को देखते हुए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के निर्धारण के लिए उत्पाद के स्तर और देश पर विचार करना अपेक्षित है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां तक आर्थिक विकास के स्तर का संबंध है

किसी भी उत्पादक/ निर्यातक/ आयातक/ प्रयोक्ता ने किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का सुझाव नहीं दिया है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने थाईलैंड, जापान और यू एस ए को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में सुझाव दिया था। जापान, यू एस ए या थाईलैंड के रूप में उपलब्ध विकल्पों पर विचार करके प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आर्थिक विकास के स्तर के संबंध में विभिन्न पैरामीटरों पर चीन जन. गण. और थाईलैंड की तुलना अधिक उचित है। थाईलैंड पर यू एस ए और यूरोपीय संघ जैसे अन्य प्रमुख व्यापार उपचार प्रयोक्ता डब्ल्यू टी ओ सहायक देशों द्वारा चीन के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में भी विचार किया जा चुका है। इसके अलावा, डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि यद्यपि चीन जन. गण. के पास जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 27 प्रतिशत अर्थात् 53,104 मी. टन है, उसी स्तर का आयात थाईलैंड से है जो भारत में कुल आयात का 28 प्रतिशत अर्थात् 51,808 मी. टन के लगभग है, जो यह दर्शाता है कि चीन में इस उत्पाद विशेष के विकास का स्तर थाईलैंड से तुलनीय है। साथ ही, थाईलैंड से आयात की मात्रा गैर-संबद्ध देशों में से सबसे अधिक है। थाईलैंड चूंकि एक गैर-संबद्ध देश है, जिस पर कोई पाटनरोधी शुल्क उपाय लागू नहीं है और आयात की मात्रा बिल्कुल सार्थक है, थाईलैंड से सी आई एफ कीमत प्रतिनिधिक प्रकृति की है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्कों में अंतर भी असंगत है, क्योंकि सामान्य मूल्य की गणना इस मामले में थाईलैंड से कारखाना बाह्य स्तर के आधार पर की गई थी। सीमा शुल्क केवल तभी संगत होते यदि प्राधिकारी ने भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत पर विचार किया होता। जहां तक निर्यातक और आयातक के बीच संबंध होने की बात है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सूचित की गई कीमत उपयुक्त नहीं है। मात्रा संबंध मौजूद होने का ही तात्पर्य यह नहीं होता कि कीमत विश्वसनीय नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने थाईलैंड को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार किया है और नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। तदनुसार, प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि वर्तमान मामले में सबसे उपयुक्त आधार कीमत है, जिस पर वस्तुएं थाईलैंड से भारत को निर्यात की गई हैं। प्राधिकारी ने समुद्री मालभाड़ा, बंदरगाह व्यय, स्वदेशी मालभाड़ा, ऋण लागत और समुद्री बीमा तथा बैंक प्रभारों जैसे विभिन्न तथ्यों को कारखाना बाह्य कीमत निकालने के लिए अनुकूल प्रक्रिया के अनुसार समायोजित किया है। इस प्रकार से परिकल्पित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है।

ज.2 कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

42. धारा 9क (ग) के तहत किसी वस्तु सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत.

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

43. केवल एक ही उत्पादक नामतः मै० हनवा केमिकल कारपोरेशन कोरिया ने अपनी संगत संस्था मै० हनवा कारपोरेशन के साथ निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किया है। उत्पादक और निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तरों की जांच की गई है। प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी करते समय यह पाया गया था कि प्रश्नावली उत्तर निर्धारित प्रारूप और निर्धारित ढंग से नहीं थे। उदाहरण के लिए, परिशिष्ट 7 और 8 निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार नहीं हैं, सीमित रूप से उपभोग की गई कच्ची सामग्री के उत्पादन की लागत के पूर्व ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे, प्रस्तुत किए गए फॉर्मेट अप्रमाणित थे, इत्यादि। अतः उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना अधूरी थी और प्राधिकारी को उत्पादन की लागत की गणना करने में सुविधा के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस प्रकार से प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी करते समय प्राधिकारी ने उत्पादक की दावा की गई घरेलू बिक्री कीमतों पर विचार न करने का निर्णय लिया था।
44. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय, प्राधिकारी ने हनवा केमिकल कारपोरेशन को त्रुटि का उल्लेख करते हुए कमियों के लिए दो पत्र जारी किए थे। उत्पादक ने दोनों पत्रों का उत्तर दिया। अब यह नोट किया गया है कि उत्पादक द्वारा विभिन्न आयातकों में प्रदान किए गए आंकड़ों में काफी परिवर्तन हैं, जो नीचे दिए गए :
 - i. पी वी सी सस्पेंशन के उत्पादन के बारे में मात्रा, जो कि सी पी वी सी के उत्पादन के लिए प्राथमिक कच्ची सामग्री है, प्रारंभिक उत्तर की तुलना में त्रुटियों के लिए प्रथम और द्वितीय पत्र के उत्तरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।
 - ii. उत्पादक ने मूल प्रश्नावली उत्तर के समय निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार परिशिष्ट 7 में पूरी सूचना दाखिल नहीं की और पूरी लागत का विवरण जैसे यूटिलिटी, पैकिंग, उपभोग और स्टोर, मूल्य ह्रास, मरम्मत, आर एंड डी, अन्य निर्माण ओवरहेड, अन्य प्रशासनिक ओवरहेड इत्यादि के संबंध में आवश्यक सूचना प्रदान करने में विफल रहा है।
 - iii. पूरी कंपनी के लिए और विचाराधीन उत्पाद के लिए बिक्री और लाभ/ (हानि) की लागत के संबंध में सूचना शुरू में परिशिष्ट 7 में प्रदान नहीं की गई थी। बाद में उत्पादक/ निर्यातक ने त्रुटियों के पत्रों के उत्तर में लाभ/ (हानि) के संबंध में सूचना प्रदान की लेकिन पूरी कंपनी के लिए और विचाराधीन उत्पाद के लिए बिक्रियों और लाभ/ हानि के आंकड़ों में बदलाव किया।
 - iv. उत्पादक/ निर्यातक तैयार किए गए उत्पादों और सीमित रूप से उपभोग किए गए उत्पादों तथा बाजार में बेचे गए उत्पादों की पूरी बिक्री का विवरण प्रदान करने में विफल रहे हैं जबकि प्राधिकारी द्वारा इन कीमतों को बताने के लिए पत्र जारी किए गए थे।
45. जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद हनवा केमिकल कारपोरेशन ने कंपनी और विचाराधीन उत्पाद की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय, उत्पादक/ बिक्रियों की लागत के आंकड़ों में बदलाव किया। इसके अलावा, उन्होंने कैप्टिव इनपुट की बिक्रियों की गैर-प्रतिनिधिक बिक्रियों का विवरण प्रदान किया है। उत्पादक/ निर्यातक द्वारा इस अनिवार्य डाटा को छिपाना जो भी डाटा प्रदान किए गए हैं, उनकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि उत्पादक/ निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना अविश्वसनीय है और इसलिए उत्तर को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है।
46. हनवा कोरिया में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक है। उत्पादक/ निर्यातक के उत्तर को अस्वीकार करने और कोरिया में विचाराधीन उत्पाद के इस एकमात्र उत्पादक के आंकड़ों की अविश्वसनीयता को देखते हुए कोरिया में घरेलू बिक्री कीमत अथवा तीसरे देश को निर्यात कीमत में से किसी भी विकल्प पर विचार नहीं

किया जा सकता। इसके अलावा, कोरिया में उत्पादन की लागत के आधार पर परिकल्पित सामान्य मूल्य पर भी विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के एक मात्र उत्पादक/ निर्यातक के डाटा अविश्वसनीय पाए गए हैं।

47. उपरोक्त सभी विकल्पों के अभाव में प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का प्रस्ताव किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि कोरिया में सामान्य मूल्य का निर्धारण कोरिया में संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों के आधार पर किया जाए। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि कोरिया में आयातक ने हाल ही में विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए क्षमता तैयार की है और इसीलिए विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग का अधिकांश हिस्सा अभी भी आयातों से पूरा किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि कोरिया में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग *** मी. टन/ प्रति वर्ष है, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना के अनुसार है और इस मांग का अधिकांश हिस्सा जापान से विचाराधीन आयातों द्वारा पूरा किया रहा है और इसीलिए जापान से कोरिया गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद की आयात की मात्रा कोरिया गणराज्य में सामान्य मूल्य परिकल्पित करने के लिए की जानी चाहिए। अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने जापान से कोरिया के लिए विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के करीब 50 प्रतिशत हिस्से के साक्ष्य के लिए बिक्री इनवायस प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने जापान से कोरिया के लिए औसत आयात कीमत लेकर संभावना की तलाश की है और तदनुसार जापान से कोरिया के लिए आयात की कीमत का पता लगाने के लिए विश्व व्यापार एटलस (डब्ल्यू टी ए) डाटा का विश्लेषण किया है। तथापि, यह नोट किया गया था कि सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड डाटा का विभाजन इन दोनों वस्तुओं के लिए डब्ल्यू टी ए डाटा में उपलब्ध नहीं था। सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड का एक ही टैरिफ कोड है। चूंकि सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड के लिए इस जांच में उल्लिखित कारणों से अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए डब्ल्यू टी ए डाटा के तहत सूचित औसत आयात कीमत लेना उपयुक्त नहीं होगा। उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत इनवायस पर भरोसा किया है। इस प्रकार से परिकल्पित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पाटन मार्जिन सारणी में दी गई है।
48. मै० हनवा केमिकल कारपोरेशन ने अपने दिनांक 16.01.2020 के पत्र के तहत हनवा केमिकल कारपोरेशन का नाम बदलकर दिनांक 06.01.2020 से मै० हनवा सेल्यूसस कारपोरेशन करने का अनुरोध दायर किया है, क्योंकि दो अन्य संस्थाओं का विभिन्न कारोबारी क्रियाकलापों के साथ अर्थात् क्यूसेल्स और एडवांस्ट केमिकल्स का मै० हनवा केमिकल कारपोरेशन के साथ विलय हो गया है। इस पत्र को रिकार्ड में ले लिया है और सार्वजनिक फाइल में रखा है।

झ. निर्यात कीमत का निर्धारण

झ.1 चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

- i. (i) शानडोंग गाओक्सिन केमिकल कं० लि० (ii) शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कं० लि० (iii) वाइफांग सुंडो केमिकल्स कं० लि० (vi) शानडोंग जुयी न्यू मैटेरियल्स कं० लि० और (v) शानडोंग जियांगशेन न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं० लि० के लिए निर्यात कीमत

49. प्राधिकारी ने उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा परिशिष्ट - 3 में दिए गए अनुसार निर्यात के विवरणों पर भरोसा किया है। स्वदेशी मालभाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बीमा, ऋण लागत, बैंक प्रभार, वेट वापसी और पैकिंग लागत के लिए समायोजन उत्पादक निर्यातकों द्वारा किए गए दावों के अनुसार स्वीकार कर लिए गए हैं। एक उत्पादक ने व्यापार के स्तर के संबंध में निर्यात कीमत में समायोजन का दावा किया है, तथापि, उसकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। विचाराधीन उत्पाद (रेसिन और कंपाउंड के लिए) के लिए निर्यात कीमत, जो कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित की गई थी, पाटन मार्जिन सारणी में दी गई है।

ii. हांगझोऊ इलेक्ट्रोकेमिकल न्यू मैटेरियल कंपनी लि० के लिए निर्यात कीमत

50. मै० हांगझोऊ इलेक्ट्रोकेमिकल न्यू मैटेरियल कंपनी लि० ने हांगझोऊ इलेक्ट्रोकेमिकल न्यू मैटेरियल कंपनी लि० और हांगझोऊ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रुप कंपनी लि० की ओर से उत्तर दाखिल किया गया है। उत्तरों की जांच करने पर यह पाया गया कि उत्पादक ने भारत को सीधे निर्यात किया है और साथ ही, असंगत निर्यातक के माध्यम से भी। चूंकि असंगत ट्रेडर नामतः चीफडू लि०, जिसके माध्यम से भारत में अधिकांश निर्यात किए गए हैं, मै० हांगझोऊ इलेक्ट्रोकेमिकल न्यू मैटेरियल कंपनी लि० नामक उत्पादक द्वारा किए गए हैं, उसने प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किए इसलिए प्राधिकारी ने उत्तरों को अस्वीकार कर दिया है।

iii. चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

51. चीन जन. गण. से अन्य गैर-सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6 (8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

झ.2 कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

कोरिया गणराज्य से सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

52. कोरिया गणराज्य से सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एंड एस के सौदा- वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया गया है। कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकालने के लिए विधिवत समायोजन किए गए हैं।

ट. पाटन मार्जिन का निर्धारण

53. वर्तमान जांच में सभी संबद्ध देशों के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन नीचे सारणी में दिया गया है :

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	कारखाना बाह्य निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		यू एस डालर/ मी. टन	यू एस डालर/ मी. टन	यू एस डालर/ मी. टन	(%)	(रैंज)
क	चीन जन. गण. के लिए					
		रेसिन				
1	शानडोंग गाओक्सिन केमिकल कं० लि०	***	***	***	***	40-60
2	शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कं० लि०	***	***	***	***	50-70
3	शानडोंग जियांगशेन्ग न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं० लि०	***	***	***	***	40-60
4	वाइफांग सुंडो केमिकल्स कं० लि०	***	***	***	***	40-60
5	शानडोंग जुयी न्यू मैटेरियल्स कं० लि०	***	***	***	***	50-70
6	सभी अन्य	***	***	***	***	60-80
		कंपाउंड				
1	शानडोंग गाओक्सिन केमिकल कं० लि०	***	***	***	***	0-20
2	शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कं० लि०	-	-	-	-	-
3	शानडोंग जियांगशेन्ग न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं० लि०	-	-	-	-	-
4	वाइफांग सुंडो केमिकल्स कं० लि०	-	-	-	-	-

5	शानडोंग जुयी न्यू मैटेरियल्स कं० लि०	***	***	***	***	20-40
6	अन्य सभी	***	***	***	***	20-40
ख	कोरिया गणराज्य					
				रेसिन		
1	सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	30-50
				कंपाउंड		
1	सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	30-50

ठ. क्षति और कारणात्मक संबंध

ठ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

54. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. वर्ष 2016-17 के साथ साथ क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, जिसमें मामूली गिरावट दर्शाई गई है। तिमाही आधार पर उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध आयातों के हिस्से में वृद्धि दर्शाई गई है। आयातों के हिस्से में कुछ तिमाहियों के दौरान 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
- ग. अन्य देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिन उनकी कीमतें अधिक हैं और वे भारतीय उद्योग को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं।
- घ. घरेलू उद्योग का बाजार अंश जिस स्तर को प्राप्त कर सकता था, उससे काफी कम है। इसके अलावा, बाजार अंश का यह स्तर भी घरेलू उद्योग द्वारा अपनी बिक्री कीमतों को काफी कम किए जाने के बाद प्राप्त किया जा सका।
- ङ. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पूर्णतया वृद्धि हुई है और खपत में भी वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग अपना उत्पादन शुरू कर रहा है।
- च. संबद्ध आयातों की कीमतें गैर-संबद्ध देशों के आयातों की कीमतों से काफी कम है।
- छ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि देखी गई है लेकिन यह अभी 18 माह के उत्पादन के बावजूद अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा है। घरेलू उद्योग का उपयोग अभी 80 प्रतिशत से कम है।
- ज. घरेलू उद्योग की बिक्रियां काफी कम रही हैं।
- झ. घरेलू उद्योग अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। तथापि, सस्ते और पाटित आयातों के कारण यह इन्वेंट्री पूरी करने के स्तर तक ही आ पाया है।
- ञ. बिक्री का कम स्तर नए संयंत्र में तकनीकी बाधाओं के कारण से नहीं है और न ही यह ग्राहकों द्वारा उत्पाद स्वीकार न किए जाने के कारण से है।
- ट. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बिक्री की अपेक्षित और वास्तविक लागत की तुलना में काफी कम है।
- ठ. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लक्षित बिक्री कीमत से काफी कम है।
- ड. घरेलू उद्योग की वास्तविक और अपेक्षित बिक्री लागत से कम कीमत पर आयात हो रहे हैं।
- ढ. घरेलू उद्योग अपनी तर्कसंगत लागत के स्तर पर करीब 50 प्रतिशत लागत वसूलने में ही समर्थ होगा।
- ण. पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर इतना प्रभाव पड़ रहा है कि घरेलू उद्योग ईष्टतम उत्पादन के स्तर तक कीमत वृद्धि करने में भी समर्थ नहीं होगा।

- त. चूंकि घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद के ऐतिहासिक निष्पादन के लिए कोई आंकड़े नहीं होते, इसलिए कीमत दबाव और सीमित ह्रास का निर्धारण जांच की अवधि के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
- थ. वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में कीमत कटौती सकारात्मक थी। तथापि, घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करने पर विवश होना पड़ा और इसीलिए कीमत कटौती नकारात्मक थी।
- द. यहां तक कि 100 प्रतिशत संयंत्र उपयोग पर भी गैर – क्षति कीमत में सकारात्मक रूप से कम कीमत पर बिक्री देखी गई।
- ध. घरेलू उद्योग प्रति यूनिट बिक्री में हानि का सामना कर रहा है और नकदी हानि तथा नकारात्मक प्रतिफल का सामना कर रहा है।
- न. यहां तक कि घरेलू उद्योग की बिक्री सर्वाधिक थी, लेकिन उनकी हानि सर्वाधिक स्तर पर थी।
- त. 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग होने पर भी लागत में नुकसान होगा क्योंकि पाटित आयातों के कारण कम बिक्री कीमतें हैं।
- प. घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी पैरामीटर में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई गई है लेकिन यह केवल इस तथ्य के कारण से है कि आवेदक एक नया उत्पादक है। अपेक्षित विकास से भी काफी कम विकास हुआ है।
- ब. यहां तक कि भारत में क्षमता स्थापित करने वाले उत्पादक उत्पाद में निवेश करने के बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण पाटन हो रहा है। यह दर्शाता है कि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता बाधित होगी।
- भ. संबद्ध देशों से पाटित आयात आश्चर्यजनक दर पर आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि इन निर्यातकों के लिए भारत एक बाजार है। इतनी अधिक मात्रा में आयात आने से वे सभी घरेलू उद्योगों के लिए गंभीर समस्या होंगे और इसीलिए औद्योगिक विकास सीमित होगा ।
- म. आयातों की पहुंच कीमत नए घरेलू उद्योग की कीमतों को गिरा रही है। वस्तुओं की मांग बढ़ने की संभावना के साथ ही आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आने की अधिक संभावना हो जाती है और इससे घरेलू उद्योग घाटे में कमी आए बिना अपना उत्पाद रोकन पर बाध्य होगा ।
- य. संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के पास सरप्लस उत्पादन क्षमताएं हैं।
- र. ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसने संबद्ध देशों से उत्पादकों के निर्यात अभिमुखी होने का पता चलता है।
- ल. भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बढ़ती मांग से निर्यातक भारत में आयातों में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
- व. घरेलू उद्योग केवल 18 माह से प्रचालन में रहा है और उसने पहले ही भारी घाटा उठाया है।
- श. घरेलू उद्योग तर्कसंगत कीमतों पर बेचने के लिए भी समर्थ नहीं है।
- ष. क्षति के क्रय में मैटेरियल रिटर्नेशन ऐसे उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है, जो अपनी संस्थापना के शुरुआती चरणों में हैं।
- स. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को बाजार में स्थापित होने में रूकावट आ रही है।
- ह. घरेलू उद्योग का वास्तविक निष्पादन संयंत्र की स्थापना से पूर्व किए गए अनुमानों से बिल्कुल ही प्रतिकूल स्थिति में है।
- कक. ऐसे अन्य कोई कारक नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके।

खख. घरेलू उद्योग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि स्टार्ट अप लागत ईष्टतम क्षमता उपयोग पर मानी गई है।

गग. मांग और आपूर्ति अंतराल की गणना करने के लिए शेष विश्व से आयातों पर विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पर शुल्क की मांग नहीं की जा रही है।

घघ. उत्पाद में नए निवेशों की संख्या की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि अंतरिम शुल्क के माध्यम से उचित बाजार स्थिति तैयार की जा रही है।

ड.ड. जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों में आयात की कीमत में वृद्धि दर्शाई गई है।

चच. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के लिए डी सी डब्ल्यू को किसी प्रकार की पानी की कमी के कारण से समस्त हानि का सामना नहीं करना पड़ा।

छछ. आवेदक चूंकि एक नया उद्योग है, लंबी अवधि पर विचार करने से प्राधिकारी को अधिक मात्रात्मक सूचना प्राप्त हो सकेगी।

जज. जांच की संभावित अवधि के आधार पर एन आई पी निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्व में अन्य मैटेरियल रिटार्डेशन के मामले में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

झझ. रेसिन और कंपाउंड के लिए अलग-अलग क्षति सूचना प्रदान करने की कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये समान वस्तु के दो अलग-अलग रूप हैं।

टट. बाजार में उत्पाद की मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता होने से पाटित आयातों को संरक्षण प्रदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

ठठ. संबद्ध वस्तुओं के पाटन से घरेलू उद्योग को परियोजना में निवेश शुरू करने से रुकावट आ रही है।

डड. चीन और कोरिया में उत्पादन क्षमताएं संबद्ध देशों में मांग से अधिक हैं। चीन और कोरिया में संस्थापित क्षमता की मांग मुश्किल से क्रमशः 10 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है।

ढढ. इसके अलावा, भारत में क्षमता विस्तार की योजना बनाई जा रही है। यदि सूचित क्षमताएं वास्तव में संस्थापित की जाती हैं तो भारत में क्षमता भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग को शीघ्र ही पार कर जाएगी।

णण. यहां तक कि गैर क्षति कीमतों के निर्धारण के लिए 18 माह की जांच की अवधि पर विचार किया गया है लेकिन विश्लेषण एक तिमाही से दूसरी तिमाही आधार पर किया गया है। इसके अलावा, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जैसा कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कहा गया है। भावी जांच की अवधि पर विचार किया जाए।

तत. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण मात्रा और कीमत संबंधी क्षति का सामना करना पड़ा है न कि नए उत्पाद को स्वीकार न करने के कारण।

थथ. विगत में ऐसी अनेक जांच हो चुकी हैं, जिनमें कीमत कटौती नकारात्मक होने के कारण प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आयातों से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ।

दद. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य संगत जांचों पर निर्भरता अनुप्रयुक्त है।

धध. चूंकि केम वन ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है, इसलिए इसके कोई आंकड़े नहीं हैं जिन पर गैर क्षति कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जा सके।

8.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

55. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. प्राधिकारी ने गैर- क्षति कीमत परिकल्पित करने के लिए अपनाई गई प्रणाली को प्रकट नहीं किया है।

- ख. यद्यपि प्राधिकारी ने सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड को एक ही वस्तु माना है, लेकिन उसने शुल्क और मार्जिन अलग-अलग दर्शाए हैं। संबद्ध देशों के आकलन के लिए भी वही सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए।
- ग. आवेदन में केवल घरेलू उद्योग की स्टार्ट अप स्थिति ही शामिल है और कथित पाटित आयातों से क्षति को शामिल नहीं किया है।
- घ. प्राधिकारी ने अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे संबद्ध देश की उत्पाद मिश्रित कीमतें और अन्य देश की कीमतों पर विचार नहीं किया है।
- ङ. भारतीय कानून के तहत “मैटेरियल रिटार्डेशन” के निर्धारण के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं और इसलिए संबद्ध जांच की शुरुआत करना कानून के अनुसार गलत है।
- च. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम में निर्धारित समस्त और सामग्री क्षति केवल एक उत्पादक अथवा दोनों उत्पादकों के आंकड़ों और सूचना के आधार पर है।
- छ. प्राधिकारी ने बिन बुने फैब्रिक के आयातों की एक पूर्व जांच में मैटेरियल रिटार्डेशन की जांच के लिए भावी आंकड़ों की जांच की थी। प्राधिकारी को इस जांच में भी एक सामान्य जांच करनी चाहिए थी।
- ज. जैसा कि ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में पाया गया है, इन्वेंट्री में मात्र वृद्धि होने से क्षति नहीं दर्शाती।
- झ. प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ से एक्स – रे सुरक्षा निरीक्षण उपस्कर की जांच में यह पाया है कि यदि नकारात्मक कीमत कटौती होती है तो पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में ह्रास नहीं होता।
- ञ. जब गैर-संबद्ध देशों से कीमतों में वृद्धि हुई है तो घरेलू उद्योग यह स्पष्ट करें कि क्या गैर – संबद्ध देशों की कीमतों से तुलना नहीं हो सकती।
- ट. घरेलू उद्योग भारतीय उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं होगा।
- ठ. नकारात्मक कीमत कटौती हो रही है। यदि घरेलू उद्योग ने कीमतों में वृद्धि की होती तो संबद्ध देश में उत्पादकों को भी अपनी कीमतों में वृद्धि करने पर मजबूर होना पड़ता।
- ड. डी सी डब्ल्यू लि० की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पानी की कमी रहना कम उत्पादकता का कारण थी।
- ढ. आवेदक को कोई मैटेरियल रिटार्डेशन का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि भारत में मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत मैटेरियल रिटार्डेशन के आवेदनों को देखने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं।
- ण. कारणात्मक संबंधों का विश्लेषण केवल ऐसी अवधि के लिए किया जाना चाहिए जिसमें घरेलू उद्योग समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है। संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई है, जिनके पाटित कीमतों पर होने का दावा किया गया है।
- त. आवेदक क्षमता विस्तार दिखाने के लिए केवल कुछ समाचारों पर भरोसा कर रहा है जिनमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं कि क्षमता वर्धन किया जाएगा।
- थ. गैर- संबद्ध देशों का हिस्सा कोरिया और चीन के हिस्से से अधिक था। प्राधिकारी को गैर – संबद्ध देशों को भी शामिल करना चाहिए था।
- द. यदि घरेलू उद्योग कुल मांग के 20 प्रतिशत को पूरा करने के लिए कुल आयातों के 25 प्रतिशत का मुकाबला भी नहीं कर सकता तो वह विश्व में अग्रणी नहीं हो सकता।
- ध. घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के बाद में सुधार आया है।

- न. यहां तक कि आवेदक ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रारंभिक जांच परिणामों में आयात अधिक बताए गए थे।
- प. घरेलू उद्योग से यह स्पष्ट करने को कहा जाना चाहिए कि वह अन्य देशों की कीमतों के समान अपनी कीमतें क्यों नहीं ला सकता।
- फ. रिकार्ड में ऐसा कुछ भी दर्शाने के लिए नहीं है कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों में आयात की कीमतों में गिरावट की मात्रा में वृद्धि अथवा कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट आई है।
- ब. पी वी सी की तुलना सी पी वी सी के साथ करने का इस जांच के प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है।
- भ. घरेलू उद्योग ने गैर – संबद्ध देशों से वस्तुओं की कीमत को कम किया है।
- म. मैटेरियल रिटार्डेशन के लिए घरेलू उद्योग के लिए कोई कारक जिम्मेदार नहीं है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 56. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों का उत्तर है।
- 57. यह नोट किया जाता है कि नियम 11 क्षति के संबंध में है जसमें यह प्रावधान है कि प्राधिकारी जांच के परिणाम दर्ज करेगा कि क्यों ऐसी वस्तुओं का भारत में पाटन होने से भारत में किसी स्थापित उद्योग को कोई क्षति अथवा सामग्री क्षति होती है अथवा भारत में किसी स्थापित उद्योग का मैटेरियल रिटार्ड होता है। इसके साथ ही इसमें यह भी विनिर्दिष्ट है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग की स्थापना को मैटेरियल रिटार्डेशन और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सभी संगत तथ्यों को शामिल करना, पाटित आयातों की मात्रा समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव को ध्यान में रखकर और नियमों के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित करेगा।
- 58. पाटनरोधी प्रक्रिया के संबंध में डब्ल्यू टी ओ समिति की सिफारिश में यह सुझाव दिया गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में पाटन जांच के लिए डाटा एकत्र करने की अवधि बारह माह की होनी चाहिए और वह किसी भी मामले में 6 माह से कम की नहीं होनी चाहिए, जो जांच शुरू करने की व्यवहारिक तरीख को समाप्त हो, जबकि क्षति जांच के लिए डाटा एकत्र की अवधि समान्यतः कम से कम तीन वर्षों की हो, जब तक कि कोई पक्षकार जहां से डाटा एकत्र किया जा रहा है, कम अवधि के लिए मौजूद हो और इसमें पाटन जांच के लिए डाटा एकत्र की समग्र अवधि शामिल है। इस प्रकार जबकि पाटनरोधी प्रक्रिया समिति ने क्षति आकलन के लिए डाटा एकत्र करने की अवधि न्यूनतम तीन वर्ष निर्धारित की है, इसने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि यह इस शर्त के अध्ययधीन होगी कि पक्षकार कम से कम इतनी लंबी अवधि के लिए मौजूद हो। अतः ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग की पहले भी न्यूनतम निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए मौजूदगी रही है, यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ऐसी कम अवधि के लिए घरेलू उद्योग की मौजूदगी पर विचार कर सकते हैं।
- 59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नए उद्योगों के मामले में मैटेरियल रिटार्डेशन की जांच लागू की जानी चाहिए। कानूनी अधिदेश यह मूल्यांकन करने के लिए है कि क्या घरेलू उद्योग की स्थापना भारत में आयातों से मंद हुई है। अतः मैटेरियल रिटार्डेशन के लिए जांच केवल घरेलू उद्योग की मौजूदगी की अवधि के लिए ही की जा सकती है।
- 60. वर्तमान मामले में, आवेदक ने जुलाई, 2017 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और इसीलिए 3 वर्ष की अवधि के लिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। तथापि, इस पर विचार करते हुए कि अवधि 3 वर्ष से कम की है, आवेदक ने तिमाही आधार पर सूचना दी है। इसके आधार पर यह माना गया है कि वर्तमान जांच के तथ्यों पर परिस्थितियों में यह उपयुक्त समझा जाएगा कि क्या पाटित आयातों के कारण, घरेलू उद्योग का

इसकी मौजूदगी की अवधि के दौरान और तिमाही विश्लेषण करके वास्तविक निष्पादन पर विचार करके घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए मैटेरियल रिटार्डेशन हुआ है।

61. चूंकि आवेदक देश में एक नया उत्पादक है और इसने क्षति की अवधि के दौरान ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, घरेलू उद्योग का निष्पादन स्टार्ट अप प्रचालनों से प्रभावित होता है। स्टार्ट अप प्रचालनों के कारण क्षति के प्रभाव को दूर करने के लिए यह उपयुक्त समझा गया था कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए, जो 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर विचार करके परिकल्पित आधार पर हो।

ड. संचयी मूल्यांकन

62. विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 3.3 और पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध- 2 के पैरा (3) में यह प्रावधान है कि ऐसे मामले में जिसमें एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयातों की एक साथ पाटन-रोधी जांच की जाती है, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यदि निम्नलिखित का निर्धारण किया जाना है :

(क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन, निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में दो प्रतिशत अधिक होता है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा, समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) होती है अथवा जहां विशिष्ट पृथक देश का निर्यात तीन प्रतिशत से कम होता है, तो वहां समग्र रूप से संचयी आयात, समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से भी अधिक बनते हैं और

(ख) आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की दशाओं के आलोक में आयातों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि

(क) संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। ऐसे प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन, नियमावली में निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

(ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा, विशिष्ट रूप से प्रत्येक देश की मात्रा, आयातों की मूल मात्रा के 3% से अधिक है।

(ग) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल प्रत्येक संबद्ध देश द्वारा पेश की जा रही समान वस्तुओं से बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जा रही समान वस्तुओं से भी सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं।

64. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह समझते हैं कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से घरेलू उद्योग की क्षति का मूल्यांकन करना उचित है।

65. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन रोधी नियमावली के नियम -11 में किसी क्षति के निर्धारण के लिए यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " *पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए..* ".... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को

प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

66. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और निर्यातकों/आयातकों/व्यापारियों/प्रयोक्ताओं के अनुरोधों पर विचार किया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों के अनुसार विचार करके विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा लिया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
67. चूंकि आवेदक ने अपना उत्पादन केवल जांच की अवधि में ही शुरू किया है, अतः प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि क्षति मानदंडों पर भी तिमाही विश्लेषण करना बेहतर होगा।

II. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. मांग का आकलन

68. वर्तमान जांच के प्रयोजन के भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को आवेदक की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों के आयातों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे सारणी में दी गई है :

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि (क)	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन				***	***
संबद्ध आयात	मी. टन	10,256	21,240	29,583	41,673	62,509
अन्य आयात	मी. टन	69,357	88,098	62,642	89,784	1,34,676
कुल मांग	मी. टन	79,612	1,09,338	92,224	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	116	170	255

विवरण	यूनिट	पहली तिमाही 2017-18	दूसरी तिमाही 2017-18	तीसरी तिमाही 2017-18	चौथी तिमाही 2017-18	पहली तिमाही 2018-19	दूसरी तिमाही 2018-19	कुल
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***	***	***
संबद्ध आयात	मी. टन	7,582	9,548	12,274	11,213	12,347	9,547	62,509
अन्य आयात	मी. टन	23,356	23,326	19,406	19,525	26,571	22,492	1,34,676
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	105	103	131	111	

69. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

ii. आयातों की मात्रा और संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयातों की मात्रा का विश्लेषण इस प्रकार किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि (क)
1	चीन गण. जन.	मी. टन	10,256	21,238	29,581	35,403
2	कोरिया गण. जन.	मी. टन	0	1.9	2.05	6,270
3	संबद्ध आयात	मी. टन	10,256	21,240	29,583	41,673
4	अन्य आयात	मी. टन	69,357	88,098	62,642	89,784
5	कुल आयात	मी. टन	79,612	1,09,338	92,224	1,31,457
6	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%				***
	रेंज					0-2000
ख	भारतीय खपत	%	13%	19%	32%	***
	रेंज					30-40
ग	भारत में कुल आयात	%	13%	19%	32%	32%

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	पहली तिमाही 2017-18	दूसरी तिमाही 2017-18	तीसरी तिमाही 2017-18	चौथी तिमाही 2017-18	पहली तिमाही 2018-19	दूसरी तिमाही 2018-19
1	चीन गण. जन.	मी. टन	7,441	9,412	11,375	9,242	9,223	6,412
2	कोरिया गण. जन.	मी. टन	141	136	899	1,971	3,124	3,135
3	संबद्ध आयात	मी. टन	7,582	9,548	12,274	11,213	12,347	9,547
4	अन्य आयात	मी. टन	23,356	23,326	19,406	19,525	26,571	22,492
5	कुल आयात	मी. टन	30,938	32,873	31,680	30,737	38,918	32,038
6	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात							
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***	***	***

	रेंज		5000-7000	4000-6000	1000-3000	1000-3000	0-2000	0-2000
ख	भारती खपत	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज		10-30	10-30	30-50	30-50	20-40	20-40
ग	भारत में कुल आयात	%	25%	29%	39%	36%	32%	30%

71. यह देखा गया है कि –

- समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। यहां तक कि तिमाही आधार पर भी अंतिम तिमाही (दूसरी -22018-19) को छोड़कर आयातों में वृद्धि हुई है।
- कुल आयातों और भारत में खपत के प्रसंग में संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यहां तक कि संबद्ध देशों से तिमाही आधार पर आयातों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

III. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

72. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पादकों की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती की जा रही है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा कीमतों को अत्यधिक स्तर पर मंद करते अथवा कीमत में वृद्धि को रोकते हैं, जो कि अन्यथा बहुत अधिक हो जाती। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कीमतों के प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई है, को ध्यान में रख कर किए जाने की आवश्यकता है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निबल बिक्री वसूली तथा क्षति रहित कीमत की संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच लागत के साथ तुलना की गई है।

I. कीमत कटौती

73. जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती की गणना आयातों की पहुंच कीमत की घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली के साथ तुलना करके की गई है। सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड के लिए अलग से विश्लेषण किया गया है।

		सी पी वी सी रेसिन					
क्र. सं.	अवधि	आयात की मात्रा	बिक्री कीमत (रु/ कि. ग्रा.)	पहुंच मूल्य	कीमत कटौती	कीमत कटौती	कीमत कटौती
		मी. टन	रु/ कि. ग्रा.	रु/ कि. ग्रा.	रु/ कि. ग्रा.	%	रेंज
	जांच की अवधि (18 माह)	61,475	***	92.98	(***)	(***)	(0-10)
1	2017-18 पहली तिमाही	7,416	***	93.54	***	***	10-20
2	2017-18 दूसरी तिमाही	9,345	***	91.44	(***)	(***)	(0-10)

3	2017-18 तीसरी तिमाही	11,983	***	91.75	***	***	0-10
4	2017-18 चौथी तिमाही	11,090	***	91.15	(***)	(***)	(0-10)
5	2018-19 पहली तिमाही	12,258	***	93.52	***	(***)	(0-10)
6	2018-19 दूसरी तिमाही	9,384	***	97.10	(***)	(***)	(0-10)
क्र. सं.	अवधि	सी पी वी सी कंपाउंड					
		आयात की मात्रा	बिक्री कीमत (रु/ कि.ग्रा.)	पहुंच मूल्य	कीमत कटौती	कीमत कटौती	कीमत कटौती
		मी. टन	रु/ कि. ग्रा.	रु/ कि. ग्रा.	रु/ कि. ग्रा.	%	रेंज
	जांच की अवधि (18 माह)	1,034	***	149.46	(***)	(***)	(0-10)
1	2017-18 पहली तिमाही	166	***	151.93	(***)	(***)	(0-10)
2	2017-18 दूसरी तिमाही	203	***	152.64	(***)	(***)	(10-20)
3	2017-18 तीसरी तिमाही	291	***	149.06	(***)	(***)	(10-20)
4	2017-18 चौथी तिमाही	123	***	149.06	(***)	(***)	(0-10)
5	2018-19 पहली तिमाही	89	***	139.24	(***)	(***)	(0-10)
6	2018-19 दूसरी तिमाही	163	***	149.57	(***)	(***)	(0-10)
क्र. सं.	अवधि	औसत					
		आयात की मात्रा	बिक्री कीमत (रु/ कि.ग्रा.)	पहुंच मूल्य	कीमत कटौती	कीमत कटौती	कीमत कटौती
		मी. टन	रु/ कि. ग्रा.	रु/ कि. ग्रा.	रु/ कि. ग्रा.	%	रेंज
	जांच की अवधि (18 माह)	62,509	***	93.91	(***)	(***)	(0-10)
1	2017-18 पहली तिमाही	7,582	***	94.81	***	***	10-20
2	2017-18 दूसरी तिमाही	9,548	***	92.74	(***)	(***)	(0-10)
3	2017-18 तीसरी तिमाही	12,274	***	93.11	***	***	0-10
4	2017-18 चौथी तिमाही	11,213	***	91.79	(***)	(***)	(0-10)
5	2018-19 पहली तिमाही	12,347	***	93.85	***	(***)	(0-10)
6	2018-19 दूसरी तिमाही	9,547	***	98.00	(***)	(***)	(0-10)

74. यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती नकारात्मक है।

II. कीमतों पर दबाव और न्यूनता

75. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव अथवा न्यूनता का प्रभाव पड़ रहा है, प्राधिकारी ने आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है। इसके अलावा, उत्पादन की लागत की गणना 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग को लेकर उत्पादन की ईष्टतम लागत पर की गई है, क्योंकि वास्तविक लागत उत्पादन की कम मात्रा के कारण काफी अधिक है। बिक्रियों की लागत और बिक्रियों की कीमत की तुलना आयातों के वर्तमान पहुंच मूल्य को देखते हुए की गई है, जैसा कि नीचे सारणी में दिखाया गया है। सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड के लिए अलग-अलग विश्लेषण किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	जांच की अवधि	
			रेसिन	कंपाउंड
1	बिक्रियों की लागत (वास्तविक)	रु/ कि. ग्रा.	***	***
2	बिक्रियों की लागत (अनुकूलतम)	रु/ कि. ग्रा.	***	***
3	बिक्री कीमत	रु/ कि. ग्रा.	***	***
4	पहुंच कीमत	रु/ कि. ग्रा.	92.98	149.46

क्र. सं.	अवधि	जांच की अवधि— वास्तविक				
		बिक्रियों की लागत (वास्तविक)		बिक्री कीमत	पहुंच कीमत	
		रु/कि. ग्रा.	प्रवृत्ति	रु/कि. ग्रा.	प्रवृत्ति	रु/कि. ग्रा.
1	2017-18 पहली तिमाही	***	100	***	100	94.81
2	2017-18 दूसरी तिमाही	***	107	***	83	92.74
3	2017-18 तीसरी तिमाही	***	103	***	86	93.11
4	2017-18 चौथी तिमाही	***	104	***	85	91.79
5	2018-19 पहली तिमाही	***	105	***	87	93.85
6	2018-19 दूसरी तिमाही	***	104	***	83	98.00
		जांच की अवधि 100%				
क्र. सं.	अवधि	बिक्री की लागत		बिक्री कीमत	पहुंच कीमत	
		रु/ कि. ग्रा.	प्रवृत्ति	रु/कि. ग्रा.	प्रवृत्ति	रु/ कि. ग्रा.
1	2017-18 पहली तिमाही	***	100	***	100	94.81
2	2017-18 दूसरी तिमाही	***	97	***	83	92.74
3	2017-18 तीसरी तिमाही	***	96	***	86	93.11

4	2017-18 चौथी तिमाही	***	97	***	85	91.79
5	2018-19 पहली तिमाही	***	98	***	87	93.85
6	2018-19 दूसरी तिमाही	***	99	***	83	98.00

76. यह नोट किया जाता है कि -

- घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उसकी बिक्रियों की अनुकूलतम और वास्तविक लागत से काफी कम है।
- आयातों का पहुंच मूल्य, बिक्रियों की वास्तविक लागत और बिक्री की अनुकूलतम लागत से कम है।
- घरेलू उद्योग लागत को वसूल करने में असमर्थ रहा है।
- लागत और बिक्री कीमत तिमाही आधार पर है, जो यह सुझाव देती है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव और न्यूनता का प्रभाव पड़ रहा है।

III. कम कीमत पर बिक्री

77. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री करने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भी जांच की है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई एनआईपी की तुलना, आयात की पहुंच कीमत के साथ की गई है। एन आई पी की गणना के लिए 100 प्रतिशत पर क्षमता उपयोग अनुकूलन किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	रेसिन	कंपाउंड
क	चीन जन. गण.			
1	आयात की मात्रा	मी. टन	52,381	723
2	क्षतिरहित कीमत	रु/ कि. ग्रा.	***	***
3	पहुंच मूल्य	रु/ कि. ग्रा.	92.41	154.52
4	कम कीमत पर बिक्री	रु/ कि. ग्रा.	***	***
5	कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
6	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	50-60	20-30
ख	कोरिया गणराज्य			
1	आयात की मात्रा	मी. टन	9,094	311
2	क्षति रहित कीमत	रु/ कि. ग्रा.	***	***
3	पहुंच मूल्य	रु/ कि. ग्रा.	95.01	136.99
4	कम कीमत पर बिक्री	रु/ कि. ग्रा.	***	***
5	कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
6	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	50-60	30-40

78. यह देखा गया है कि कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है और रेसिन तथा कंपाउंड दोनों के लिए प्रत्येक संबद्ध देशों से महत्वपूर्ण है।

79. सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	एन आई पी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		यूएस डालर/ मी. टन	यूएस डालर/ मी. टन	यूएस डालर/ मी. टन	(%)	(रेंज)
क	चीन जन. गण.					
		रेसिन				
1	शानडोंग गाओक्सिन केमिकल कं० लि०	***	***	***	***	40-60
2	शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कं० लि०	***	***	***	***	50-70
3	शानडोंग जियांगशेन्ग न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं० लि०	***	***	***	***	40-60
4	वाइफांग सुंडो केमिकल्स कं० लि०	***	***	***	***	40-60
5	शानडोंग जुयी न्यू मैटेरियल्स कं० लि०	***	***	***	***	50-70
6	अन्य सभी	***	***	***	***	40-60
		कंपाउंड				
1	शानडोंग गाओक्सिन केमिकल कं० लि०	***	***	***	***	0-20
2	शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कं० लि०	-	-	-	-	-
3	शानडोंग जियांगशेन्ग न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं० लि०	-	-	-	-	-
4	वाइफांग सुंडो केमिकल्स कं० लि०	-	-	-	-	-
5	शानडोंग जुयी न्यू मैटेरियल्स कं० लि०	***	***	***	***	20-40
6	अन्य सभी	***	***	***	***	20-40
ख	कोरिया गणराज्य					
				रेसिन		
1	सभी उत्पादकों/ निर्यातक	***	1,426	***	***	40-60
				कंपाउंड		
1	सभी उत्पादकों/ निर्यातक	***	2,057	***	***	20-40

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

80. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- 11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह

उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों ; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :

81. आवेदक एक नया उद्योग है और उसने अप्रैल, 2017 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। जांच की अवधि के लिए आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण किया गया है और प्रवृत्तियों का भी तिमाही आधार पर विश्लेषण किया गया है।

क. क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री

82. घरेलू उद्योग ने सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड के निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित की हैं। संयंत्र की क्षमता के उपयोग की गणना करने के लिए प्राधिकारी ने कंपाउंड के उत्पादन को समान रेसिन उत्पादन में बदला है, जिसका उपयोग घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण के लिए किया गया है। ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं :

क्र. सं.	विवरण	क्षमता	समकक्ष रेसिन उत्पादन	प्रवृत्ति	क्षमता उपयोग	प्रवृत्ति	उत्पादन (रेसिन और कंपाउंड)	प्रवृत्ति	घरेलू बिक्रियां (रेसिन और कंपाउंड)	प्रवृत्ति
		मी. टन	मी. टन	सूचीबद्ध	मी. टन	सूचीबद्ध	मी. टन	सूचीबद्ध	मी. टन	सूचीबद्ध
1	2017-18 पहली तिमाही	2,500	***	100	***	100	***	100	***	100
2	2017-18 दूसरी तिमाही	2,500	***	150	***	140	***	161	***	1,175
3	2017-18 तीसरी तिमाही	2,500	***	593	***	560	***	633	***	7,467
4	2017-18 चौथी तिमाही	2,500	***	699	***	660	***	746	***	8,233
5	2018-19 पहली तिमाही	2,500	***	1,637	***	1,540	***	1,691	***	13,608
6	2018-19 दूसरी तिमाही	2,500	***	1,625	***	1,540	***	1,698	***	18,150

83. यह देखा गया है कि :-

क. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, यह जांच की अवधि में संयंत्र की शुरुआत होने के कारण प्राकृतिक था।

ख. यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास भारत में मांग को देखते हुए यह महत्वपूर्ण रूप से निष्क्रिय क्षमता है।

ग. औसत आधार पर घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 38 प्रतिशत है जो काफी कम है।

ख. बाजार अंश

84. घरेलू उद्योग का बाजार अंश जांच की अवधि के दौरान तिमाही आधार पर इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	संबद्ध देशों से आयात	अन्य देशों से आयात	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मांग	घरेलू उद्योग का हिस्सा	संबद्ध देशों का हिस्सा	अन्य देशों का हिस्सा
		मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	रेंज	रेंज	रेंज
1	2017-18 पहली तिमाही	7,582	23,356	***	***	0-10	20-30	70-80
2	2017-18 दूसरी तिमाही	9,548	23,326	***	***	0-10	20-30	70-80
3	2017-18 तीसरी तिमाही	12,274	19,406	***	***	0-10	30-40	60-70
4	2017-18 चौथी तिमाही	11,213	19,525	***	***	0-10	30-40	60-70
5	2018-19 पहली तिमाही	12,347	26,571	***	***	0-10	30-40	60-70
6	2018-19 दूसरी तिमाही	9,547	22,492	***	***	0-10	20-30	60-70

85. यह देखा गया है कि :-

- प्रारंभिक दो तिमाहियों में, घरेलू उद्योग का अंश काफी कम था। यह उसके बाद बढ़ा है। तथापि, घरेलू उद्योग का अंश तुच्छ रहा है।
- संबद्ध आयातों का अंश महत्वपूर्ण रहा है और इसमें 2017-18 की प्रथम तिमाही से 2017-18 की तीसरी तिमाही तक वृद्धि हुई है और उसके बाद गिरावट आई है।
- अन्य देशों के अंश में 2017-18 की तीसरी तिमाही तक गिरावट आई है और उसके बाद वृद्धि हुई है।

ग. लाभ पी बी आई टी और निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह

86. वास्तविक लाभ/ हानि, नकदी लाभ, पी बी आई टी (आय और कर पूर्व लाभ) तथा निवेश पर प्रतिफल के संबंध में घरेलू उद्योग का विश्लेषण नीचे सारणी में दिया गया है। चूंकि संयंत्र एक नई सुविधा है जिसमें उत्पादन केवल जांच की अवधि के दौरान शुरू हुआ और घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन इसके अनुमान के स्तर से भी कम था, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर विचार करके लाभ मापदंडों का निर्धारण किया है।

क्र. सं.	अवधि	बिक्रियों की लागत	बिक्री कीमत	लाभ/हानि	लाभ/ (हानि)	नकद लाभ	पीबीआई टी	आरओसी ई
		सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	रेंज
		रु/ कि.ग्रा.	रु/कि.ग्रा.	रु/कि. ग्रा.	रु/ लाख	रु/ लाख	रु/ लाख	%
1	2017-18 पहली तिमाही	100	100	(100)	(100)	100	100	0-10
2	2017-18 दूसरी तिमाही	97	88	(164)	(164)	(217)	(289)	(0-10)
3	2017-18 तीसरी तिमाही	96	92	(126)	(126)	(27)	(55)	(0-10)
4	2017-18 चौथी तिमाही	97	92	(131)	(131)	(55)	(90)	(0-10)

5	2018-19 पहली तिमाही	98	93	(142)	(142)	(119)	(284)	(0-10)
6	2018-19 दूसरी तिमाही	99	95	(136)	(136)	(93)	(252)	(0-10)

87. यह देखा गया है कि :

क. घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री उत्पादन की लागत से अधिक कीमत पर नहीं कर पाया और इसलिए घाटे में चल रहा है।

ख. नकदी लाभ में भी पी बी आई टी की ही प्रवृत्ति का अनुसरण किया गया है। यद्यपि जांच की अवधि की प्रथम तिमाही में नकद लाभ दर्ज किया गया लेकिन घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में सभी अन्य तिमाहियों में नकदी हानि पर चलाना पड़ा

ग. इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग ने सकारात्मक अर्जन किया लेकिन जांच की अवधि की प्रथम तिमाही में पूंजी पर न्यूनतम प्रतिफल प्राप्त हुआ लेकिन उसके बाद लगातार नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ।

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

88. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की जांच की है, जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है :

मापदंड	यूनिट	जांच की अवधि - क
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***
मजदूरी	रु लाख में	***
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/संख्या	***

89. तिमाही उत्पादन के डाटा से यह कहा जा सकता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में सुधार आया है।

ड. इन्वेन्ट्री

क्र. सं.	तिमाही	औसत	
		मी. टन	सूचीबद्ध
1	2017-18 पहली तिमाही	***	100
2	2017-18 दूसरी तिमाही	***	113
3	2017-18 तीसरी तिमाही	***	99
4	2017-18 चौथी तिमाही	***	69
5	2018-19 पहली तिमाही	***	104
6	2018-19 दूसरी तिमाही	***	132

90. यह देखा गया है कि प्रथम तिमाही की तुलना में अंतिम तिमाही में इन्वेन्ट्री में वृद्धि हुई है।

च. संवृद्धि

91. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने बड़ी मौजूदा और भावी मात्रा को देखकर नई क्षमताएं स्थापित की हैं, लेकिन उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग के अनुकूलतम स्तरों तक पहुंचने में समर्थ नहीं रहा है।

छ. पाटन की मात्रा

92. जांच अवधि के लिए संबद्ध देशों से उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन अत्यधिक हैं

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

93. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और एनआईपी से वास्तविक रूप से कम कीमतों पर आयात हो रहे हैं। चूंकि घरेलू उद्योग को केवल आयात से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और घरेलू उद्योग देश में एक नया उत्पादक है, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जा रही कीमतों के लिए एक मात्र आयात कीमत उत्तरदायी है। अन्य देशों आयात काफी अधिक कीमतों पर है।

झ. पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

94. देश में पर्याप्त मांग रखने वाले उत्पाद में भारत में नए निवेश के बावजूद भी घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन बदतर है। नकारात्मक लाभप्रदता, नकदी लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, से ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षेत्र के लिए पूंजीगत निवेश बढ़ाने के घरेलू उद्योग की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

V. जांच की अवधि के बाद विश्लेषण

95. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की जांच की अवधि के बाद की स्थिति की भी जांच करनी चाहिए, जैसे कि जांच की शुरुआत के समय की गई थी, घरेलू उद्योग की केवल 18 माह का ही इतिहास है और उसके बाद घरेलू उद्योग ने अब तक एक वर्ष से अधिक पूरा कर लिया है। यह मानकर कि घरेलू उद्योग मामले की शुरुआत के समय एक नया उद्योग है, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद के आयातों, मांग, बाजार अंश और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच को ही जांच की अवधि के बाद के विश्लेषण में अक्टूबर, 18 से सितंबर, 19 तक को शामिल किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

क. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और आयातों का अंश

96. नीचे दी गई सारणी में संबद्ध देशों और अन्य देशों से जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा दर्शाई गई है :

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	जांच की अवधि के बाद
क	आयात की मात्रा		
1	संबद्ध देश	मी. टन	42,950
2	अन्य देश	मी. टन	91,781
3	कुल आयात की मात्रा	मी. टन	1,34,731
ख	आयातों में बाजार अंश		
1	संबद्ध देश	%	32%
2	अन्य देश	%	68%
3	कुल आयातों की मात्रा में कुल अंश	%	100%

97. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि के बाद आगे काफी अधिक वृद्धि हुई है।

ख. मांग और बाजार अंश

98. नीचे दी गई सारणी में जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों और अन्य देशों की मांग और बाजार अंश दर्शाया गया है :

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	जांच की अवधि (क)	जांच की अवधि के बाद
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***
2	संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	41,673	42,950
3	अन्य देशों से आयात	मी. टन	89,784	91,781
4	कुल मांग	मी. टन	***	***
5	मांग में हिस्सा			
क	घरेलू उद्योग	%	0-10	0-10
ख	संबद्ध देश	%	30-40	20-30
ग	अन्य देश	%	60-70	60-70
घ	कुल	%	100	100

99. यह देखा गया है कि जांच की अवधि के बाद मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। घरेलू उद्योग के हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देशों के हिस्से में मामूली गिरावट (1 प्रतिशत से कम) आई है। अन्य देशों के अंश में भी गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग का निष्पादन मापदंड

100. नीचे दी गई सारणी में जांच की अवधि के बाद के दौरान के घरेलू उद्योग के संगत मापदंड दर्शाए गए हैं :

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	जांच की अवधि के बाद
1	क्षमता	मी. टन	10,000
2	समान उत्पादन	मी. टन	***
3	क्षमता उपयोग	%	***
4	घरेलू बिक्रियां- रेसिन	मी. टन	***
5	घरेलू बिक्रियां- कंपाउंड	मी. टन	***
6	बाजार अंश	%	***
7	लाभ/(हानि)	रु/ मी. टन	(***)
8	आर ओ आई	%	0-10
9	बिक्रियों की लागत	रु/ मी. टन	***
10.	बिक्री कीमत	रु/ मी. टन	***

101. यह देखा गया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, लेकिन अनुकूल से कम रही है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अभी भी जांच की अवधि के दौरान की बिक्रियों की लागत से कम है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग घाटा उठा रहा है। घरेलू उद्योग की आर ओ आई सकारात्मक हो गई है लेकिन अनुकूल स्तर से नीचे है।

VI. क्षति का निष्कर्ष

102. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि :

- क. संबद्ध आयातों में देश में नया निवेश होने के बावजूद सापेक्ष और निरपेक्ष अर्थों में वृद्धि हुई है।
- ख. हानि के साथ नकारात्मक कीमत कटौती यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने के लिए कम कीमतों पर बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ा ।
- ग. आयातों से घरेलू उद्योग को उद्योग की लागत से भी कम कीमत पर बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ा है ।
- घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि के बावजूद घरेलू मांग की तुलना में काफी कमी आई है।
- ङ. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और एन आई पी काफी कम कीमत पर है।
- च. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकदी हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग के निष्पादन पर अपनी मौजूदगी की अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसका निष्पादन लक्षित/ अनुमानित स्तर से नीचे है तथा इसकी स्थापना संबद्ध देश से उत्पाद के पाटन से काफी मंद पड़ गई है।
- छ. जांच की अवधि के बाद के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में मात्रात्मक मापदंडों की दृष्टि से सुधार आया है जबकि कीमत मापदंड अभी भी मामूली सुधार के बाद नकारात्मक है।

VII. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

103. क्षति की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातकों के कीमत प्रभाव की मौजूदगी की जांच करते हुए प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के अलावा अन्य किसी कारक के कारण से है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

104. यद्यपि यूरोपीय संघ, जापान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात न्यूनतम से ऊपर है, संबद्ध देशों और गैर-संबद्ध देशों से आयातों में एक महत्वपूर्ण कीमत अंतर है। गैर-संबद्ध देशों से आयातों की कीमत काफी अधिक है और उचित कीमत प्रतीत होती है। ये आयात घरेलू उद्योग के निष्पादन से प्रभावित प्रतीत नहीं होते। प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग को गैर-संबद्ध देशों से आयातों के परिणामस्वरूप क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है।

ख मांग में संकुचन

105. चूंकि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है, अतः इस संबंध में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग खपत के पैटर्न में परिवर्तन

106. प्राधिकारी को खपत के पैटर्न में ऐसा कोई संभव परिवर्तन नहीं पाया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

घ विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ड प्रोद्योगिकी में विकास

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन की प्रोद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

च निर्यात निष्पादन

109. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति होने का दावा निर्यातों के कारण नहीं किया गया है।

छ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

110. आवेदक एक बहु उत्पाद कंपनी है, तथापि, लागत और वित्तीय डाटा अलग किए गए हैं तथा केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए विचार किया गया है और वर्तमान जांच के लिए विश्लेषण किया गया है।

VIII. कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

111. अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग को क्षति केवल संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण से हुई है।

ड. प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणी

112. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उसमें उठाए गए अधिकांश मुद्दों को पहले ही जांच के दौरान उठाया गया है और इस जाँच परिणाम के ऊपर संबंधित भागों (भागों) में उचित रूप से संबोधित किया गया है। अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

ix. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

113. प्रकटीकरण विवरण के संबंध में घरेलू द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. शामिल प्रारंभिक उत्पाद रेसिन के उत्पादन में है। रेसिन से कंपाउंड में उत्पादन की प्रक्रिया एक लघु संवर्धनात्मक प्रक्रिया है, जो उत्पाद को उपयोगी बनाने के लिए की गई है और इसमें उत्पाद के आवश्यक गुणों को बदला नहीं है।
- ख. सी पी सी सी रेसिन का कोई स्वतंत्रता उपयोग नहीं है और इसे अनिवार्य रूप से कंपाउंड में प्रसंस्कृत करना होगा।
- ग. कंपाउंड में निवेश का स्तर महत्वपूर्ण नहीं है। प्रमुख निवेश रेसिन के निर्माण में है। कंपाउंडिंग की प्रक्रिया न तो हाई-टेक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है और न ही उच्च कौशल प्राप्त मानवीय प्रक्रिया।
- घ. पूर्व जांचों में भी प्राधिकारी ने उत्पाद और इसकी पूर्ण अथवा बाद की/प्रसंस्कृत अवस्था को एक ही वस्तु माना है।
- ड. विचाराधीन उत्पाद के लिए टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव हो गया है और नया वर्गीकरण 39049010 है।
- च. श्रीलंका और यू ए ई जैसे देशों से, जिनके पास रेसिन की उत्पादन सुविधा नहीं है, से सी पी वी सी कंपाउंड के आयात भी भारत में पाटनरोधी शुल्क के अधीन होंगे, यदि सी पी वी सी रेसिन कोरिया अथवा चीन से उस देश को निर्यात की जाती है।
- छ. यदि पाटनरोधी शुल्क रेसिन का निर्माण न करने वाले देशों से वस्तु के रेसिन घटक पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो आयातक ऐसे स्रोतों से आयात करना शुरू कर देंगे।

- ज. याचिकाकर्ताओं को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के लिए कोई सुझाव नहीं दिए हैं। यूरोपी संघ, जापान, थाइलैंड तथा यू एस ए के उपलब्ध विकल्पों में से थाइलैंड वर्तमान प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त देश है।
- झ. मैसर्स हनवा केमिकल कारपोरेशन ने दाखिल किए गए उत्तर में सूचना छिपाई है। कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान क्रियाकलापों की सूचना प्राधिकारी द्वारा छिपाई गई है। हनवा सीपीवीसी का उत्पादन कर रहा था और उसके कारण उत्पाद के निर्माण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसने अपनी सीपीवीसी निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए कोरियाई प्रौद्योगिकी एजेंसी द्वारा मानक प्रदान किए हैं। इस प्रकार, प्रतिवादी (निर्यातक) को प्रौद्योगिकी के विकास में काफल लागत कम करनी चाहिए और यह लागत उत्पाद पर डाली जानी चाहिए।
- ञ. हनवा कास्टिक सोडा, क्लोरीन, पीवीसी ससपेंशन रेसिन, हाइड्रोजन, स्टीम और विद्युत का कैप्टिव उत्पादन करता है और यह प्रदर्शित करने के लिए मूल्यांकन के लिए उत्तर में कुछ भी नहीं है कि कैसे उत्तर में दर्शाई गई कीमतें कैसे बाजार दर कीमत के दर्शाती हैं।
- ट. हनवा का भारत में एक कार्यालय है, जिसके माध्यम से वह विक्रय क्रियाकलाप करता है। इस तथ्य को उत्तर में छिपाया गया है।
- ठ. उसके द्वारा दर्ज किया गया उत्तर डी जी टी आर द्वारा जारी किए गए व्यापार नोट्स और पाटनरोधी नियमों के मानकों को पूरा नहीं करता।
- ड. वाणिज्य मंत्रालय बनाम मैसर्स हलडारे टोप्सो मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुदेश के अनुसार जब संबद्ध देश में प्रचलित कीमतों के संबंध में सूचना उपलब्ध है, प्राधिकारी सामान्य मूल्य के संबंध में अन्य विकल्पों का चयन नहीं कर सकता।
- ढ. यूनिवर्सल कैमिकल्स मामले में सेस्टेट ने यह पाया था कि सत्यापन केवल तभी किया जाना चाहिए जब निर्यातक ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ सहयोग किया हो।
- ण. यदि आंकड़े में पर्याप्त बदलाव होता है तो उत्तर को अस्वीकार करने की वैश्विक प्रक्रिया है।
- त. प्राधिकारी को शुल्क के यथा मूल्य का प्रस्ताव करना चाहिए क्योंकि बैंचमार्क शुल्क प्रयोजन को पूरा करने में विफल रहता है। निर्यातक पाटनरोधी शुल्क के बैंचमार्क रूप से बचने के लिए उत्पाद की कीमत को अधिक बनाकर रखते हैं।
- थ. सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास न तो कोई ऐसी व्यवस्था है और न ही अधिक कीमत का सत्यापन करने अथवा कीमतों को सही करना सुनिश्चित करना व्यावहारिक है।
- द. दोनों की उत्पादों की कीमत और लागत में कोई पर्याप्त अंतर नहीं है इसलिए, शुल्क का निर्धारित तरीका रेसिन के लिए अधिक संरक्षण और कंपाउंड के लिए संरक्षण के तहत लाना होगा।

x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

114. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण विवरण के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

- i. उत्पाद का उपयोग स्वयं ही एक "अनिवार्य गुण" है। यह तथ्य कि सीपीवीसी रेसिन बिना कंपाउंड के अनुपयोगी है और जिस उत्पाद की उपयोगिता है, वह सीपीवीसी कंपाउंड है, से तात्पर्य यह है कि कंपाउंडिंग में मूल्य वर्धन महत्वपूर्ण है और इससे उपयोगिता गुण में बदलाव आता है।
- ii. उदाहरण के लिए अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट के आयात के संबंध में जांच में उसे "समान वस्तु" नहीं माना गया था जबकि आयातित उत्पाद - दानेदार रूप में अमोनियम नाइट्रेट को अनिवार्य रूप से अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट में परिवर्तित किया जाना था ताकि इसके औद्योगिकी अनुप्रयोग में इसकी उपयोज्यता थी।

- iii. संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ कोड पर "कंपाउंडिंग" प्रक्रिया की "संवर्धनात्मक" प्रकृति के पहचानकर्ता के रूप में विचार करना सही नहीं है। इसके अलावा, केवल एक ही "टैरिफ शीर्ष" के तहत आने का तात्पर्य नहीं है कि दो उत्पादों को एक समान गुण वाले माने जाएं।
- iv. प्राधिकारी ने यह कहा है कि मध्यवर्ती उत्पाद, सी पी वी सी रेसिन और एंड प्रोडक्ट, सीपीवीसी कंपाउंड के लिए वास्तविक उपयोग का बाजार अनिवार्य तौर पर वही रहता है। यह सही नहीं है कि रेसिन के क्रेता और कंपाउंड के क्रेता भिन्न हैं, उनकी भिन्न क्षमताएं हैं और उनका उत्पाद बाजार भिन्न है।
- v. समान रासायनिक संरचनाएं होना विचाराधीन उत्पाद/समान वस्तु के प्रयोजन के लिए दो उत्पादों को "समान" मानने के लिए मानदंड नहीं हैं। इस संबंध में, रिलायंस को अमोनियम नाइट्रेट की जांच में पुनः प्राधिकारी के भरोसे छोड़ा गया है।
- vi. प्राधिकारी यह विचार करने में असफल रहे हैं कि सी पी वी सी रेसिन और सीपीवीसी कंपाउंड का अनुपात चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से भिन्न है। वे यह विचार करने में भी असफल रहे हैं कि दोनों उत्पादों (भिन्न उत्पाद मान लिए गए हैं) को मिलाया नहीं जा सकता है और संचित आकलन के लिए एक उत्पाद माना गया है।
- vii. प्राधिकारी ने केवल यही कहा है कि घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के प्रयोजन के लिए उत्पादक के लिए रेसिन का निर्माता होना "अनिवार्य" है न कि केवल कंपाउंड का निर्माता। यह तर्क गोल मोल है। हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे यह स्पष्ट करें कि क्यों उत्पादन के लिए सी पी वी सी रेसिन का एक निर्माता होना "आवश्यक है", चाहे वे सीपीवीसी कंपाउंड का उत्पादन करते हों अथवा नहीं।
- viii. याचिकाकर्ता एम पी वी सी का एक निर्माता है और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि आयात की लागत याचिकाकर्ता द्वारा क्यों शामिल की जा रही है। प्राधिकारी इसकी जांच करे और यह पता लगाए कि कैप्टिव खपत पर ऐसा आयात याचिकाकर्ता की लागतों को कैसे प्रभावित करता है।
- ix. यह जांच करना भी संगत है कि क्यों एम पी वी सी का निर्माता विदेशी स्रोतों से इसका आयात करता है और उसमें सौदे की प्रकृति और उसकी संबद्ध लागत की भी जांच करे।
- x. यह संदेह है कि ऐसे आयात के लिए कारण याचिकाकर्ता और आर्क्रेमा, फ्रांस के बीच एक तकनीकी लाइसेंस करार का निष्पादन होना है, जिसके तहत फ्रांस से एम पी वी सी के आयात किए जाते हैं। प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की एमपीवीसी की आयात कीमत की भी जांच करनी चाहिए। यह कार्य आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लागत (और यहां तक कि एन आई पी) पर अनावश्यक वृद्धि नहीं हुई है।
- xi. प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम धारा 9ख(1)(ख)(iii) के तहत "आगे का निर्धारण" करने की अपेक्षा की अनुपालना करने में असफल रहे हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार 9 क (2) के तहत तब तक पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी जब तक कि पाटन की एक प्रारंभिक जांच के परिणाम और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा आगे एक निर्धारण न किया जाए कि जांच के दौरान हुई क्षति को रोकने के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है।
- xii. एक निर्धारित डाटा को चुनना बहुत ही मनमाना है, क्योंकि वह डाटा का आकलन किए बिना ही आयातों की अधिक मात्रा दर्शाता है। प्राधिकारी यह विश्वास करते प्रतीत होते हैं कि एक पर दूसरा डाटा चुनना तर्कसंगत है।
- xiii. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद, प्राधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि डी जी सिस्टम के डाटा में कतिपय ऐसी सूचना शामिल थी जो एक दूसरे की नकल थी और उसमें मेरिट को छोड़ दिया गया।

- xiv. ऐसा हेरफेर दोनों संबद्ध देशों से सी पी वी सी कंपाउंडिंग आयातों की काफी कम मात्रा को "छिपाता" है।
- xv. यदि किसी भी तरह से प्राधिकारी वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं तो प्राधिकारी को एक ऐसे निर्धारित शुल्क लगाने की बजाय एक बैचमार्क कीमत आधारित शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए, जो संबद्ध वस्तुओं के उपयोक्ताओं और आयातकों के लिए अनावश्यक रूप से भार ही रहेगा।
- xvi. यदि किसी भी तरह से प्राधिकारी वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, तो प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शुल्क की सिफारिश इतने सीमित समय के लिए की जाए कि याचिकाकर्ता एक तर्कसंगत समय में अपना निष्पादन करके कुछ संरक्षण प्राप्त करना जरूरी रख सके और प्राधिकारी को उसकी बाजार की स्थिति और क्षति का तर्कसंगत आकलन करने का पूर्ण और बेहतर अवसर मिल सके।
- xvii. यथा मूल्य आधार पर शुल्क लगाए जाने चाहिए क्योंकि बैचमार्क रूप में शुल्क लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की कीमत परिवर्तनशील है और स्थिर नहीं है।
- xviii. बैचमार्क शुल्क लगाने से भविष्य में भी शुल्क में वृद्धि होगी और यहां तक कि पाटन के मार्जिन से भी अधिक शुल्क हो सकता है।
- xix. मूल उत्तर में एच सी सी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पीवीसी सस्पेंशन की खपत की मात्रा का ब्यौरा प्रदान किया है जबकि दूसरे अनुपूरक उत्तर में एचसीसी ने पीवीसी सस्पेंशन की उत्पादन की मात्रा तथा जांच की अवधि के दौरान सी पी वी सी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त खपत मात्रा प्रदान की है।
- xx. पीवीसी सस्पेंशन के उत्पादन में परिवर्तन संबंधी तर्क बाद में डी जी टी आर द्वारा उठाया गया है। डी जी टी आर ने पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा।
- xxi. यद्यपि एच सी सी ने मूल उत्तर प्रस्तुत करने में प्रश्नावली में डी जी टी आर द्वारा विनिर्धारित पूरी लागत सूची प्रदान नहीं की थी, लेकिन एच सी सी ने दूसरे अनुपूरक उत्तर में दूसरे त्रुटि संबंधी पत्र के अनुदेशों के अनुसार परिशिष्ट-7 की पूरी सूचना की थी।
- xxii. एचसीसी ने दूसरे अनुपूरक उत्तर में एच सी सी की सामान्य लागत लेखांकन प्रणाली द्वारा तैयार तत्वों के आधार पर अपनी लागत बताई है, जो कि के-जीएएपी के अनुसार और दूसरे त्रुटि संबंधी पत्र में डी जी टी आर के अनुरोध के अनुसार है। अतः डी जी टी आर के लिए यह निर्धारित करने का कोई आधार नहीं है कि एच सी सी की बताई गई लागत अविश्वसनीय है अर्थात् इंकार करने योग्य है।
- xxiii. जारी किए गए दूसरे त्रुटि संबंधी पत्र में डी जी टी आर ने एच सी सी से परिशिष्ट-7 का परिशिष्ट-9 के साथ मिलान करने का अनुरोध किया है। अतः डी जी टी आर के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए, एच सी सी को एस जी एंड ए, गैर प्रचालन आय/व्यय और वित्तीय आय/ बिक्री मूल्य के व्यय अनुपात को लागू करके परिशिष्ट-7 को बदलना पड़ा था जो कि एच सी सी के मूल उत्तर और प्रथम अनुपूरक उत्तर में प्रयुक्त किया गया था। लाभ/(हानि) कंपनी-वार अथवा विचाराधीन उत्पाद-वार परिवर्तन एचसीसी ने जैसा चाहा था वैसा नहीं है।
- xxiv. यद्यपि, डी जी टी आर के पास दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के दूसरे अनुपूरक उत्तर और 29 जनवरी, 2020 के प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बीच की अवधि ("3 माह से अधिक") के लिए एच सी सी पर स्थल सत्यापन करने का पर्याप्त अवसर है। डी जी टी आर ने स्वयं ही सहयोगी प्रतिवादी, एच सी सी पर सत्यापन करने की अपनी झूटी को नजरअंदाज किया है और एच सी सी

को डीजीटीआर द्वारा बिना नोटिस दिए उसकी स्थिति की सुरक्षा के अधिकार से अनावश्यक रूप से वंचित किया है।

- xxv. एच सी सी की निर्यात कीमत के संबंध में प्रकटीकरण विवरण में ऐसा कोई आधार अथवा संकेत नहीं है जिससे निर्यात कीमत के संदर्भ में एच सी सी के उत्तर को पाटन मार्जिन की गणना में अस्वीकार किया जाए। अंतिम जांच परिणामों में निर्यात कीमत आयात डाटा की बजाए एच सी सी की सूचित की गई निर्यात कीमत पर आधारित होनी चाहिए।
- xxvi. कतिपय त्रुटियां शानडोंग गाओक्सिन कैमिकल कं. लि. और शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड के लिए "पहुंच कीमत" की गणना से सामने आई है।
- xxvii. कुछ पक्षकार जांच की अवधि के दौरान सी पी वी सी कंपाउंड का निर्यात नहीं कर रहे हैं और इसीलिए प्राधिकारी को इन पक्षकारों की न्यू शिपर समीक्षा के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।
- xxviii. प्राधिकारी ने यह प्रकट नहीं किया है कि कैसे उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के निर्धारण के प्रयोजन से उसने उत्पाद और देश के विकास के स्तर की तुलना की है।
- xxix. इसके अलावा, प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के तहत केवल उत्पादन और देश के विकास के स्तर पर विचार करना आवश्यक है बल्कि "चयन के समय किसी विश्वसनीय सूचना को उपलब्ध कराना" भी आवश्यक है।
- xxx. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन का भार, जिसमें सुझाव भी शामिल हैं, प्राधिकारी पर है न कि जांच के पक्षकारों पर है।
- xxxi. प्राधिकारी ने अपनी जांच का कार्य हितवद्ध पक्षकारों पर डाल दिया है और तब पक्षकार अनावश्यक कार्य में विफल रहे हैं और जिसके चलते याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए सेरगेट देश के रूप में थाइलैंड को चुना है।
- xxxii. प्राधिकारी यह मानते प्रतीत होते हैं कि भारत को बिक्रियों की तुलनीय मात्रा होना दोनों भिन्न देशों के मूल के उत्पादों के बीच की तुलना को दर्शाता है।
- xxxiii. चीन जन. गण. से शुल्क भुगतान किए उत्पादों की तुलना में शुल्क मुक्त थाई वस्तुओं पर 7.5 प्रतिशत का एक महत्वपूर्ण मार्जिन लाभ है। अतः यह प्राकृतिक बात है कि थाई कीमतें चीन जन. गण. से आयातों की कीमतों से करीब 7.5 प्रतिशत अधिक होंगी। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों थाई कीमतें चीन की कीमतों के साथ तुलनीय नहीं हैं, जिससे थाईलैंड एक अनुप्रयुक्त सेरगेट देश बन गया है।
- xxxiv. सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सूचित की गई आयात कीमत संगत पक्षकार सौदा कीमतों और असंगत पक्षकार सौदा कीमतों में उल्लेखनीय अंतर दर्शाएंगी। प्राधिकारी ने यह जांच नहीं की है कि क्या यह विचाराधीन आयात डाटा से सिद्ध होता है। इसकी बजाय, प्राधिकारी ने यह दावा करने का प्रयास किया है कि संगत पक्षकारों के बीच मात्र संबंध होने का अर्थ यह नहीं है कि कीमत अविश्वसनीय है।
- xxxv. प्राधिकारी ने एक शानडोंग गाओक्सिन कैमिकल कं० लि० और शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कं० लि० के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत के निर्धारण में एक असंगत और गैर निर्यातक के लिए बिक्री की मात्रा और कीमत पर विचार किया है। इसे इन उत्पादकों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण करने में भी शामिल किया जा रहा है।

- xxxvi. प्राधिकारी ऐसे विचार के लिए औचित्य स्पष्ट कर सकते हैं, यहां तक कि भारत में अधिकांश बिक्रियां सीधे मार्ग से की गई हैं न कि असंगत निर्यातकों के माध्यम से। प्राधिकारी समायोज का स्तर प्रदान करें।
- xxxvii. थाईलैंड को चीन के लिए एक सेरेगेट तीसरा देश बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचारा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को कोई पर्याप्त सूचना नहीं थी। जांच शुरू करने की सूचना में विवरण केवल घरेलू उद्योग के दावों की पुनरावृत्ति थी।
- xxxviii. अनुबंध-I के पैरा 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा देश के चयन के बाद तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करना अनिवार्य है ताकि हितबद्ध पक्षकार चयन पर टिप्पणी कर सकें।
- xxxix. उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए अन्य कारक संगत नहीं हैं।
- xl. प्राधिकारी को संगत आयातकों को यह प्रमाणित करने के लिए उत्तर दाखिल करने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिए था कि सौदे निष्पक्ष कीमत पर हैं।
- xli. थाईलैंड से सभी देशों को निर्यातों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिक स्पष्ट कीमत होगी।
- xlii. प्राधिकारी भविष्य में संबद्ध देशों से सी पी वी सी कंपाउंड के आयातों की संभावना के बारे में सी पी वी सी रेसिन के मामले में वे शुल्क लगाने के मामले में चिंतित प्रतीत होते हैं। तथापि, ऐसी स्थिति पाटनरोधी जांच में आमतौर पर होती है और हमेशा ऐसा अवसर होता है कि एक वस्तु पर शुल्क लगाने से एक अपस्ट्रीम उत्पाद अथवा डाउनस्ट्रीम उत्पाद के आयातों में वृद्धि होती है।
- xliii. यह सामान्यतः एक ऐसा मामला है, जहां याचिकाकर्ता के समक्ष लायसेंस करार, उत्पादन शुरू करने में देरी, पी वी सी को अर्केमा फ्रांस से प्राप्त करने के लिए लायसेंस करार के तहत अपेक्षा के चलते उत्पादन की उच्च लागत का सामना कर रहे हैं।
- xliv. आर ओ सी ई के लिए शामिल औसत पूंजी पर 22 प्रतिशत पर विचार किया गया है। तथापि, एक नए और अस्थापित उद्योग के लिए आर ओ सी ई स्थापित और पूर्णतः कार्यरत उद्योग के समान स्तर पर नहीं हो सकती। प्राधिकारी को एन आई पी के प्रयोजन से न्यून आर ओ सी ई पर विचार करना चाहिए।
- xliv. निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह जांच करनी थी कि क्यों मेसर्स डीसीडब्ल्यू लि० स्थापित है अथवा नहीं। प्रतिवादी ने यह प्रदर्शित किया है कि मेसर्स डीसीडब्ल्यू लि० एक स्थापित उद्योग है।
- xlvi. जांच की 18 माह की आवधिक का चयन किए जाने से एक बड़ी हुई गैर-क्षति कीमत प्राप्त हुई। जांच की अवधि में उद्योग की स्थापना की अवधि भी शामिल है।
- xlvi. प्राधिकारी को एन आई पी के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के बाद की अवधि की जांच करना चाहिए।
- xlvi. प्राधिकारी को क्षति की जांच करने के लिए उद्योग के निष्पादन के बाद की अवधि की जांच करनी चाहिए।
- xlix. घरेलू उद्योग कंपनी के शुरूआती चरण में समस्या से प्रभावित था। लाभप्रदता पी वी आई टी, आर ओ आई और नकदी प्रवाह में गिरावट की प्रवृत्ति आयातों के कारण नहीं हो सकती, बल्कि घरेलू उद्योग के शुरूआती चरण के कारण से थी।

- I. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक को गोपनीय माना है जबकि सूचीबद्ध डाटा याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया था।
- ii. हनवा केमिकल कारपोरेशन ने प्राधिकारी से कोरिया गणराज्य के लिए पाटन मार्जिन की गणना को प्रकट करने का अनुरोध किया।

XI. प्राधिकारी द्वारा जांच

115. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश प्रकटीकरण उपरांत के अनुरोध इस जांच परिणाम के संगत पैरा में पहले भी शामिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध की संगत पाए गए अनुसार इस प्रकार जांच की है और उन्हें अन्यत्र शामिल नहीं किया गया है :-

- i. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सी पी वी सी रेसिन बिना कंपाउंड के अनुप्रयोगी है और उपयोगी उत्पाद सी पी वी सी कंपाउंड है, इसका तात्पर्य यह है कि कंपाउंडिंग में मूल्यवर्धन महत्वपूर्ण है, जिससे उसकी उपभोक्ता में परिवर्तन हुआ है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सी पी वी सी रेसिन का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है और इसे आवश्यक रूप से कंपाउंड में परिवर्तित करना होता है ताकि इसे उपयोगी बनाया जा सके और इस प्रकार दोनों प्रकार के उत्पाद एक ही प्रकार के अंतिम उपयोग के लिए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि रिलायंस को अमोनियम नाइट्रेट जांच में शामिल किया गया, गलत है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट को भी आवेदकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं रखा गया था। इसके अलावा, अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट का कोई भी आयात संगत अवधि के दौरान नहीं किया गया था। इस जांच के अंतिम जांच परिणामों में यह दर्ज किया गया था कि सभी हितबद्ध पक्षकारों का करार था कि अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट का आयात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अपने रूप में परिवर्तन किए बिना है। अतः इन दोनों जांचों में समानता लाना अनुचित है।
- ii. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि उत्पाद के दायरे में सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड, दोनों शामिल हैं और कंपाउंड एक मूल्यवर्धित उत्पाद है तथा इसलिए इसे अलग उत्पाद माना जाए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसका व्यावहारिक उपयोग करने के लिए, सी पी वी सी रेसिन को कंपाउंड में बदला गया है और इसका आगे उपयोग करने के लिए कंपाउंड बनाने के अतिरिक्त इसे अलग-अलग उत्पाद नहीं माना गया है।
- iii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ कोड को “कंपाउंडिंग” प्रक्रिया की “संवर्धनात्मक” प्रकृति के पहचानकर्ता के रूप में लेना और मात्र उसका “टैरिफ शीर्ष” के तहत आने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों उत्पादों को समान गुणों का माना जाए, यदि यह नोट किया जाता है कि यद्यपि टैरिफ कोड स्वयं ही उत्पाद के समान होने का एक मात्र मानदंड नहीं हो सकता, वास्तव में दो उत्पादों के आठ अंकों का स्तर एक ही टैरिफ कोड में होना एक संकेतक है कि एक से दूसरे में परिवर्तन (सी पी वी सी रेसिन का सी पी वी सी कंपाउंड में परिवर्तन) एक वृद्धिशील प्रक्रिया है।
- iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि रेसिन और कंपाउंड अलग-अलग बाजारों की मांग को पूरा करते हैं, यह नोट किया जाता है कि सी पी वी सी रेसिन का कोड स्वतंत्र उपयोग नहीं होता, इसका केवल सी पी वी सी कंपाउंड बनाने में उपयोग होता है और इसीलिए रेसिन और कंपाउंड दोनों ही अंततः वास्तविक उपयोग के लिए है।
- v. इस तर्क के संबंध में कि रासायनिक संरचना समान होने से दोनों उत्पादों को एक समान नहीं माना जा सकता, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रासायनिक संरचना भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन उत्पादों की समानता के निर्धारण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है।

- vi जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी यह विचार करने में विफल रहे कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड का अनुपात भिन्न और इसका संचित आकलन उपयुक्त नहीं है तो प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड जो चीन जन. गण. और कोरिया से निर्यातित हैं, का अनुपात एक बार वर्तमान जांच में एक उत्पाद मान लिए जाने के बाद संचित आकलित के लिए संगत नहीं है। नियमानुसार संचित आकलन के लिए एकमात्र आवश्यकता यह पता लगाने की है कि क्या आयातित विचाराधीन उत्पाद आवेदकों द्वारा उत्पादित समान वस्तु से मुकाबला कर रही है अथवा नहीं और क्या संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं अथवा नहीं।
- vii. जहां तक सी पी वी सी रेसिन के निर्माण में लगे उत्पादकों के लिए आवश्यक न होने के बारे में तर्क का संबंध है, यह नोट किया गया है कि सी पी वी सी रेसिन का निर्माण अनिवार्यतः प्रमुख निर्माण क्रियाकलाप है और कंपाउंड निर्माण केवल एक बढ़त की प्रक्रिया है। अतः घरेलू उत्पाद के सी पी वी सी रेसिन में लगाना जरूरी है। यदि उसे घरेलू उद्योग के रूप में पात्र होना है।
- viii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि प्रायः यह संभावना बनी रहती है कि किसी उत्पाद विशेष पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से अपस्ट्रीम अथवा डाउनस्ट्रीम उत्पाद के आयातों में वृद्धि होगी। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि सी पी वी सी कंपाउंड को वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जाता है तो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की संभावना इस तथ्य के कारण अधिक होगी कि (क) सी पी वी सी रेसिन स्टेज से कंपाउंड का निर्माण केवल एक बढ़त का क्रियाकलाप है और (ख) सी पी वी सी रेसिन का उपयोग सी पी वी सी कंपाउंड के निर्माण के लिए विशिष्ट है।
- ix. फ्रांस से आयातित एम पी वी सी के साथ कैप्टिव उत्पादित / उपभोग की गई एम पी वी सी की लागत की तुलना के बारे में तर्क के संबंध में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग एम पी वी सी का निर्माण नहीं कर रहा और वह केवल फ्रांस से इसका आयात कर रहा है, जो सी पी वी सी रेसिन के उत्पादन के लिए प्रयोग की जा रही है। अतः आयातित और कैप्टिव खपत के संबंध में भिन्न-भिन्न कच्ची सामग्री लागत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्राधिकारी ने उत्पाद के उत्पादन की लागत का निर्धारण घरेलू उद्योग के आंकड़ों का सत्यापन करने के बाद विचाराधीन किया है।
- x. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम धारा 9ख (1) (ख) (iii) के तहत “आगे निर्धारण” करने की अपेक्षा की अनुपालना करने में विफल रहे, यह कहा जाता है कि केंद्रीय सरकार तब तक 9क (2) के तहत पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी जब तक कि घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम नहीं किए गए हैं और आगे एक निर्धारण किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान होने वाली क्षति को रोकने के लिए शुल्क आवश्यक हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने घरेलू उद्योग को आगे क्षति की लंबित जांच से बचाने के लिए कानून के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए हैं।
- xi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मात्र इस कारण से निर्धारित डाटा का चयन करना मनमाना है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में आयात दर्शाए गए हैं, यह नोट किया जाता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद, डीजीसीआई एंड एस और डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात डाटा के बीच विसंगतियों की विस्तार से जांच की गई थी और तब यह नोट किया गया था कि डीजी सिस्टम के डाटा में कतिपय ऐसी सूचना शामिल थी जो दोहराय था। यह नोट किया गया था कि वेयरहाउसिंग बिल प्रविष्टि और घरेलू खपत के लिए बिल प्रविष्टि के माध्यम से प्राप्त आयात पर केवल दोहरी गणना से बचने के लिए विचार किया जाना है और उसके परिणामस्वरूप केवल डीजीसीआई एंड एस के आयात डाटा पर ही विचारा किया गया और उसका प्रकटीकरण विवरण

में स्पष्टीकरण दिया गया है। यह पुनः कहा जाता है कि प्राधिकारी ने केवल डीजीसीआई एंड एस के सौदा-वार आंकड़ों पर अंतिम जांच परिणामों में भरोसा किया गया है।

- xii. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को वर्तमान जांच में एक सीमित अवधि के लिए ही पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए सिफारिश की जानी चाहिए ताकि घरेलू उद्योग को संरक्षण दिया जा सके। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की सामान्यतः 5 वर्षों के लिए सिफारिश की जाती है। बहरहाल नियम 23 (1क) में मध्यावधिक समीक्षा के लिए प्रावधान है। हितबद्ध पक्षकार नियम 23 (1क) के प्रावधानों के अनुसार एक मध्यावधिक समीक्षा की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- xiii. जहां तक शुल्क के उपयुक्त रूप के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने निर्धारित शुल्क की बजाय एक बेंचमार्क कीमत पर आधारित शुल्क का अनुरोध किया है। जबकि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने मूल्यानुसार शुल्क के लिए अनुरोध किया है। यह नोट किया जाता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम के समय प्राधिकारी ने बेंचमार्क शुल्क की सिफारिश की थी। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों के नवीन तर्कों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने बेंचमार्क शुल्क को जारी रखना उचित समझा।
- xiv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि थाईलैंड पर विकास के स्तर, भारत में आयातक के साथ संबंध, एफ टी ए के कारण सीमा शुल्कों में अंतर के कारण से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार नहीं किया जा सकता, पुनः यह कहा जाता है कि प्राधिकारी को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के निर्धारण के लिए उत्पाद और देश के विकास के स्तर पर विचार करना अपेक्षित है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां तक आर्थिक विकास के स्तर का संबंध है, किसी अन्य उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का सुझाव नहीं दिया है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने थाईलैंड, जापान और यू एस ए को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार साझे का सुझाव दिया गया था। उपलब्ध विकल्पों अर्थात् जापान, यू एस या थाईलैंड पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पी पी पी (खरीद, विद्युत, समानता) पर जीडीपी मानदंडों सहित विभिन्न मापदंडों के आधार पर आर्थिक विकास के स्तर के संदर्भ में चीन जन. गण. और थाईलैंड की बेहतर तुलना की जा सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि थाईलैंड पर अन्य प्रमुख व्यापार उपचार उपभोगकर्ता डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा चीन के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार किया गया है। इसके अलावा, चीन जन. गण. और थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का स्तर लगभग समान है, जिससे यह सुझाव मिलता है कि इन दोनों देशों में उत्पाद विकास का स्तर समान है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क में भिन्नता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि थाईलैंड से भारत को निर्यात कीमत कारखाना बाह्य स्तर पर है, उस पर ही सामान्य मूल्य की गणना के लिए विचार किया गया है।
- xv. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का संबंध है, थाईलैंड से आयात कीमत संगत पक्षकार सौदे के कारण अविश्वसनीय है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने डीजीसीआई एंड एस डाटा की जांच की है और यह पाया है कि लुब्रिजोल के अलावा अन्य आयातकों द्वारा किए गए आयात थाईलैंड से औसत आयात कीमत से करीब 6 प्रतिशत अधिक है और यह कि कीमत स्तरों में भी कोई बाजार भिन्नता नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि यदि प्राधिकारी ने लुब्रिजोल द्वारा किए गए आयात की मात्रा को निकाल दिया होता, जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकार सुझाव देते हुए देखे गए हैं, तो आयात कीमत और उसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य अधिक होता, जिससे

अधिक पाटन मार्जिन होता और उससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया यह तर्क ही व्यर्थ है।

- xvi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि थाईलैंड से सभी देशों को निर्यातों पर सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिक स्पष्ट कीमत होगी, तो प्राधिकारी ने विश्व व्यापार एटलस (डब्ल्यूटीए) डाटा का विश्लेषण किया है ताकि थाईलैंड से अन्य देशों की निर्माण कीमत पता लगाई जा सके। यह नोट किया जाता है कि सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड डाटा अलग-अलग कीमत यद्यपि डब्ल्यूटीए डाटा में इन दोनों मदों के संदर्भ में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन सी पी वी सी रेसिन और सी पी वी सी कंपाउंड का एक समान टैरिफ कोड पाया गया।
- xvii. जहां तक पहुंच प्रभारों और पहुंच कीमत में उपकर घटक पर विचार न करने के कतिपय तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी ने इसकी जांच की है और उन्हें उचित मूल्य पर गणना करके निवारक कार्रवाई की है।
- xviii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि असंगत गैर-प्रतियामी निर्यातक मार्जिन के लिए बिक्री और कीमत की मात्रा को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए शामिल न किया जाए, क्योंकि अधिकांश बिक्रियां सीधे की गई हैं। यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा भागीदारी की सीमा तक व्यक्तिगत दर/मार्जिन का भारित औसत और गैर भागीदारी की सीमा तक अवशिष्ट दर लेकर मार्जिन का निर्धारण करने में एक तर्कसंगत संकल्पना अपनाई गई है।
- xix. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने बिना कोई कारण बताए व्यापार समायोजन के स्तर को अस्वीकार कर दिया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने मासिक आधार पर दोनों चैनल में यूएस डॉलर में निर्यात कीमत का विश्लेषण किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यापार समायोजन के स्तर के लिए कीमत में किसी निश्चित पैटर्न अथवा प्रवृत्ति का अभाव है।
- xx. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने हनवा द्वारा दाखिल किए गए उत्तर को अनुचित तरीके से अस्वीकार किया है, यह नोट किया जाता है कि निर्धारित प्रश्नावली में उत्पादक/निर्यातक पूर्ण विवरण प्रदान करना अपेक्षित है। हनवा ने यह स्वीकार किया है कि उसका प्रारंभिक प्रश्नावली उत्तर पूर्णतया अपूर्ण था और नई सूचना का बड़ा हिस्सा पहले और दूसरे अनुपूरक उत्तर में प्रदान किया गया था। यह नोट किया जाता है कि पहले उत्तर में और तदोपरांत दूसरे अनुपूरक उत्तर में महत्वपूर्ण सूचना संशोधित की गई थी। कंपनी का समग्र लाभ और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन व बिक्री के संबंध में लाभ भी कंपनी द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित किया गया। जहां तक स्थल सत्यापन के मामले का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब प्रश्नावली उत्तर ही अस्वीकार कर दिया गया तो सामान्यतः सत्यापन दौरा नहीं किया जाएगा।
- xxi. हनवा को यह भी बताया गया था कि प्रश्नावली उत्तर का परिशिष्ट-7, परिशिष्ट-9 से मेल नहीं खाता। उनसे यह भी पूछा गया था कि एसजीए उत्तर के घटक-वार व्यौरे प्रदान करें। तथापि, त्रुटि संबंधी पत्र के उत्तर में, हनवा ने एसजीए व्यय और कंपनी तथा विचाराधीन उत्पाद के लाभ को बदल दिया।
- xxii. हनवा से सभी उत्पादों तथा संगत उत्पादन की मात्रा और मूल्य, बिक्री मात्रा तथा मूल्य और बाहरी पक्षकारों को बिक्री के विवरण प्रदान करने के लिए भी कहा गया था। तथापि, हनवा ने केवल चुनिन्दा डाटा / सूचना प्रदान की और जो उसके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्तरों में अलग-अलग थी।
- xxiii. जहां तक पर्याप्त अवसर प्रदान न करने के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि हनवा को दो त्रुटि संबंधी पत्र जारी करके पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। यह भी नोट किया जाता है

कि प्राधिकारी द्वारा विशेष अपेक्षाओं का उल्लेख करके और यह कहकर कि विदेशी उत्पादक / निर्यातक द्वारा प्रश्नावली में निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से सूचना प्रदान करके भाग लेने हेतु व्यापक प्रश्नावली निर्धारित की गई है। प्रतिवादी उत्पादक / निर्यातक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह स्वयं प्रश्नावली को संशोधित करे और इस तरह से सूचना प्रदान करे जो वे उपयुक्त समझें। तथापि यह नोट किया जाता है कि हनवा ने स्वयं ही प्रश्नावली को कई जगह पर संशोधित किया और चुनिन्दा सूचना प्रदान की।

- xxiv. जहां तक निर्यात कीमत को अस्वीकार करने का संबंध है, हनवा ने बिक्री और वितरण लागत के संबंध में सूचना को संशोधित नहीं किया। इसके अलावा, जिस ढंग से हनवा ने पहले अनुपूरक उत्तर में सूचना संशोधित की है, और उसके बाद दूसरे अनुपूरक उत्तर में स्वयं ही सूचना की विश्वसनीयता पर संदेह उठाया है।
- xxv. हनवा केमिकल कारपोरेशन द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में पाटन मार्जिन गणना प्रकट करने के लिए यह नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए आधार को पैरा- 47 में विस्तार से बताया गया है, जो स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि इस गणना के लिए अपनाई गई पद्धति जापान से कोरिया गणराज्य के लिए विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री के संबंध में इनवॉयस में उल्लिखित कीमतों के आधार पर है। चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री डाटा के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है, और प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो सामान्य मूल्य और परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन की गणना को प्रकट नहीं किया जा सकता।
- xxvi. जहां तक हनवा केमिकल कारपोरेशन का नाम बदलकर मेसर्स हनवा सोल्यूशंस कारपोरेशन करने के लिए मेसर्स हनवा केमिकल कारपोरेशन के अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि अनुरोध को हितबद्ध पक्षकारों की सार्वजनिक फाइल में उनकी टिप्पणियों के लिए रखा गया था। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई। यह भी नोट किया जाता है कि मेसर्स हनवा केमिकल कारपोरेशन यह प्रमाणित नहीं कर पाया कि इससे स्वामित्व का इक्विटी होल्डिंग बदले बिना केवल नाम परिवर्तन शामिल है।
- xxvii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह कहा है कि कुछ पक्षकार जांच की अवधि के दौरान सी पी वी सी कंपाउंडिंग का निर्यात नहीं कर रहे हैं और इसीलिए प्राधिकारी को इन पक्षकारों की न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन करने का विशेष अधिकार रखना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि न्यू शिपर समीक्षा केवल वही दाखिल कर सकते हैं, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और जो ऐसी संस्थाओं से संबद्ध नहीं है, जिन्होंने व्यक्तिगत शुल्क दें / मार्जिन प्रदान की हैं। चूंकि विचाराधीन उत्पाद में सी पी वी सी रेसिन और कंपाउंड, दोनों शामिल हैं, अतः अनुरोध अपुष्ट है। यह भी नोट किया जाता है कि इस प्रकार का अनुरोध सी पी वी सी रेसिन से सी पी वी सी कंपाउंड के निर्यात की संभावना की ओर संकेत करता है। यदि इनमें से दोनों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं लाया जाता है।
- xxviii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह कहा है कि याचिकाकर्ता अर्केमा फ्रांस से पी वी सी प्राप्त करने के लिए लायसेंस करार के तहत अपेक्षा के चलते उत्पादन शुल्क करने में विलंब आदि के कारण उत्पादन में अधिक लागत की समस्या का सामना कर रहा है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक चूंकि एक नया उत्पादक है, जिसने क्षति अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू ही किया है, घरेलू उद्योग का निष्पादन स्टार्ट-अप कार्य के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। तथापि, स्टार्ट-अप कार्य के कारण प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए, यह उपयुक्त समझा गया कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन को, 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग मानकर नेशनल आधार पर मूल्यांकित किया जाए।

- xxix. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को एक नए और अस्थापित उद्योग के लिए एन आई पी के प्रयोजन से कम आरओसीई पर विचार करना चाहिए जैसे एक स्थापित उद्योग और पूर्णतः कार्यरत उद्योग के लिए, लगाई गई औसत पूंजी पर 22 प्रतिशत की दर की बजाय यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी की यह प्रक्रिया है कि लगाई गई पूंजी के 22 प्रतिशत पर आरओसीई पर विचार किया जाए।
- xxx. इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि के 18 माह का चयन होने से गैर-क्षति कीमत में वृद्धि हुई, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने एन आई पी का निर्धारण अनुलग्नक-III के प्रावधानों के तहत घरेलू उद्योग की समग्र मौजूद अवधि के लिए किया है। यह भी नोट किया जाता है कि स्टार्ट-अप प्रभाव को दूर करने के लिए 100 प्रतिशत की दर से क्षमता उपयोग पर विचार करके उत्पादन की लागत का निर्धारण किया गया है।
- xxxi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को एन आई पी के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के बाद की अवधि पर विचार करना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कानून एन आई पी और क्षति मार्जिन का निर्धारण 100 प्रतिशत की दर से क्षमता को उपयोग पर विचार करके किया गया है।
- xxxii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग कंपनी के स्टार्ट-अप फेज के बारे में समस्या से प्रभावित था और इसलिए लाभप्रदता में गिरावट की प्रवृत्ति, पी बी आई टी, आर ओ आई और नकदी प्रवाह को संबद्ध आयातों के कारण नहीं माना जा सकता है, बल्कि घरेलू उद्योग के स्टार्ट-अप फेज के कारण है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि क्षति, यदि कोई हो, स्टार्ट-अप समस्या के कारण हुई है तो वह 100 प्रतिशत के स्तर पर क्षमता का उपयोग करके उत्पादन की लागत निर्धारित करके अप्रभावी की जा सकती है।

XII. भारतीय उद्योग के हित पक्षकारों एवं अन्य मामले

116. जहां तक उपभोक्ता उद्योग पर प्रभाव के बारे में अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी ने यह पाया है कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो कि सामान्यतः देश के हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाना किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध लगाना और उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता से प्रभावित करना नहीं है।
117. प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने की अवस्था में, भारत में उत्पाद की कीमत का स्तर प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारतीय बाजार में पारदर्शी प्रतिस्पर्धा से ऐसे पाटनरोधी उपायों को कम नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों से पाटनकी प्रक्रिया से प्राप्त अनुचित लाभ को कम किया जा सकता है और इससे संबद्ध वस्तुओं के ग्राहकों को व्यापार विकल्प की उपलब्धता को बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी।

XIII. निष्कर्ष

118. किए गए अनुरोधों और उठाए गए मामलों की जांच करने और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-
- क. विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से भारत को सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है।
- ख. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के ऐसे धारित आयातों से घरेलू उद्योग की स्थापना को मैटेरियल गतिरोध हुआ है।

XIV. सिफारिशें :

119. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और इसके लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था। निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और तत्संबंधी कारणात्मक संबंध की एक जांच किए जाने और ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को सकारात्मक पाटन मार्जिन और क्षति होने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।
120. कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के कम मार्जिन और क्षति के मार्जिन के समान निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए संबंध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और नीचे दी गई शुल्क सारणी के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बीच के अंतर के रूप में, बशर्ते पहुंच मूल्य कॉलम 7 में उल्लिखित मूल्य से कम है, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 द्वारा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9क, के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर लागू सीमा शुल्क के स्तर पर होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं..	एच एस कोड	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	विनिर्देशन	राशि (यू एस डॉलर/ मी. टन)
1	2	3	4		5	6	7
1	39042110 39042190 39042210 39042290 39041090 39049000 39049010	क्लोरीनेटेड पोलिविनाइल क्लोराइड रेसिन (सीपीवीसी)- चाहे आगे सम्मिश्रण (कंपाउंड) में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं	चीन जन. गण.	चीन जन. सहित कोई भी देश	शानडोंग गाओक्सिन केमिकल कं० लि०	सीपीवीसी रेजिन	2087
			चीन जन. गण.	चीन जन. सहित कोई भी देश		सीपीवीसी कंपाउंड	2717
2			चीन जन. गण.	चीन जन. सहित कोई भी देश	शानडोंग पूजी रबड़ एंड प्लास्टिक कं० लि०	सीपीवीसी रेजिन	2053
			चीन जन. गण.	चीन जन. सहित कोई भी देश		सीपीवीसी कंपाउंड	2853
3			चीन जन. गण.	चीन जन. सहित कोई भी देश	शानडोंग जियांगशेन्ग न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं० लि०	सीपीवीसी रेजिन	2045
			चीन जन. गण.	चीन जन. सहित कोई भी देश		सीपीवीसी कंपाउंड	2853

4			चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	वाइफांग सुंडो केमिकल्स कं० लि०	सीपीवीसी रेजिन	2025
			चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश		सीपीवीसी कंपाउंड	2853
5			चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	शानडोंग जुयी न्यू मैटेरियल्स कं० लि०	सीपीवीसी रेजिन	2057
			चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश		सीपीवीसी कंपाउंड	2657
6			चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लिखित के अलावा कोई अन्य उत्पादक	सीपीवीसी रेजिन	2161
						सीपीवीसी कंपाउंड	2853
7			चीन जन. गण. एवं कोरिया गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य	सीपीवीसी रेजिन	2161
						सीपीवीसी कंपाउंड	2853
8			कोरिया गणराज्य	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई अन्य उत्पादक	सीपीवीसी रेजिन	2024
						सीपीवीसी कंपाउंड	2853
9			चीन जन. गण. एवं कोरिया गणराज्य के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई अन्य उत्पादक	सीपीवीसी रेजिन	2024
						सीपीवीसी कंपाउंड	2853

XV. आगे की प्रक्रिया :

121. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

भूपिंदर एस भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2020

FINAL FINDING

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin- whether or not further processed into compound", originating in or exported from China PR and Korea RP.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/3/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “**the Act**”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “**the Rules**”) thereof.

1. M/s DCW Limited and M/s Kem One Chemplast Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the “Applicants”) filed an application before the Designated Authority(hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and Anti-Dumping Rules, for initiation of anti- dumping investigation concerning imports of "Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin - whether or not further processed into compound (hereinafter also referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) from China PR and Korea RP (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicants, issued a Notification No. 6/3/2019-DGTR dated 28th March, 2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the AD Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from subject countries and to recommend an amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.
3. The Authority having regard to the Act and the Rules, considered it appropriate to recommend interim duties and issued preliminary finding vide Notification No. 6/3/2019-DGTR dated 12th July 2019, recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Korea RP. Accordingly, the Central Government vide Notification No.33/2019-Customs dated 26th August, 2019 imposed provisional anti-dumping duties on imports of the subject goods, originating in or exported from the China PR and Korea RP which are valid for 6 months.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra and bilateral commitments.
 - ii. The Authority issued a notification dated 28th March, 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of subject goods.
 - iii. The Embassies of China and Korea in India were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules with a request to advise the exporters/producers from China PR and Korea RP to respond to the questionnaire within prescribed time limit.
 - iv. Copy of the non-confidential version of the application filed by the Applicants was made available to the known producers / exporters of the subject countries and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(2) & 6(3) of the Anti-Dumping Rules.
 - v. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating anti-dumping investigation to the following known producers / exporters in the subject countries and provided them an opportunity to file response to questionnaire in the form and manner prescribed and make their views known in writing within forty days in accordance with the Rules 6(4) of the Rules:

1. Shandong Gaoxin Chemicals Co.Ltd.,China PR
 2. Hangzhou Electrochemical New Material Co. Ltd.
 3. Shangdong Yada New Material Co Ltd
 4. Novista, China
 5. Shandong Xuye New Materials Co. Ltd., China PR
 6. Sundow Polymers Co ltd, China
 7. Shandong Xiangsheng New Materials Technology Co., Ltd., China PR
 8. Hanwha Chemical Corporation, Korea.
- vi. In response to the notification, following exporters/producers responded by filing exporter's questionnaire response-
1. Shandong Gaoxin Chemical Co.Ltd, China
 2. Shandong Pujie Rubber and Plastic Co. Ltd., China PR
 3. Hangzhou Electrochemical New Material Co. Ltd
 4. Weifang Sundow Chemicals Co. Ltd, China PR
 5. Shangdong Xuye New Material Co Ltd, China
 6. Shandong Xiangsheng New Materials Technology Co., Ltd, China
 7. Hanwha Chemical Corporation, Korea (HCC)
 8. Hanwha Corporation, Korea RP (HC)
- vii. The Authority sent Questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
- Ala Chemicals Limited
1. Apollo Pipes Ltd
 2. Ajay Industrial Corporation Limited
 3. Ajay Polymers
 4. Bothara Agro Equipment Pvt Ltd
 5. Desana Poly Plastic Industries
 6. Lubrizol Advanced Materials India Pvt.Ltd.
 7. Basil Prompt Vinyl Private Limited
 8. Flowkem Poly Plast Private Limited.
 9. Kankai Pipes & Fittings Pvt. Ltd.
 10. Hil Limited
 11. HP International
 12. Karan Polymers Pvt Ltd
 13. Kelvin Plastic Pvt Ltd
 14. Kisan Mouldings Limited
 15. Krishi Polymers Pvt.Ltd,
 16. Neoseal Adhesive Pvt. Ltd.
 17. Pidilite Industries Limited
 18. Precision Plastic Industries Pvt. Ltd.
 19. Param Polymers Private Limited
 20. Prince Pipes & Fittings Pvt Ltd
 21. Prince Swr Systems Pvt. Ltd.

22. Pushp Global Company
23. R C Plasto Tanks & Pipes Pvt. Ltd.,
24. Reva Poly Plast
25. Sagar Polytechnik Ltd
26. Spectra Pipes Pvt Ltd
27. Star Industries
28. Star Pvc Pipes and Fittings Pvt Ltd
29. Subray Catal Chem Pvt.Ltd.,
30. Sudhakar Irrigation Systems Private Limited
31. Sumo Polyplast Pvt. Ltd.
32. The Supreme Industries Limited
33. Surya Roshni Limited
34. Vectus Industries Limited
35. Waterflo Piping System
36. Watertec (India) P Ltd
37. Abk Industries
38. Ace Poly Plast Pvt Ltd.
39. Champion Commercial Co.Ltd.
40. Gourishanker Polymers
41. H Saleix & Company
42. Mas Additives Pvt. Ltd.
43. Mayur Dyes & Chemical Corporation
44. Meet Marketing (India) Pvt Ltd.
45. Navyug Chemicals Pvt. Ltd.
46. Osho Polymers
47. Overseas Polymers Pvt Ltd
48. Polmann India Ltd.
49. Prayag Polymers (P) Ltd.
50. Prince Marketing
51. Sai Exim
52. Salasar Impex Pvt. Ltd-
53. Shreeji Impex
54. Sushila Parmar International Pvt. Ltd.
55. Synergy Industriez
56. Astral Polytechnik Ltd

viii. In response to the above, following importers/users filed a response and made submissions:

1. Sushila Parmar International Private Limited
2. HIL Limited
3. Vectus Industries Limited
4. Prince Pipes and Fittings Ltd.
5. Basil Prompt Vinyl Private Limited
6. Gourishanker Polymers

- ix. Authority also sent copies of initiation notification to the following associations and sought their comments:
- All India Plastic Industries Association
 1. Organization of Paper Processor of India (OPPI)
 2. Maharashtra PVC Pipe Manufacturers Association.
 3. All India Plastic Manufacturers Association
 4. Andhra Pradesh Plastics Manufacturers Association
 5. TN PVC Manufacturers Association
- x. None of the above associations responded to the initiation notification. However, a letter was received from Alkali Manufacturers Association and Chemical and Petrochemical Manufacturers Association (CPMA) with a request for an urgent help for safeguarding the investments already made by the Indian producers and for reinstating the industry's confidence.
- xi. The following interested parties filed submissions responding to the initiation notification-
1. HP International
 2. Precision Plastic Industry Private Limited
 3. Mas Additives Private Limited
 4. Astral Poly Technik Ltd.
 5. Jiangsu Lee & Man Chemical Limited
 6. China Chlor-Alkali Industry Association
 7. Canadian Speciality Vinyl
- xii. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xiii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2017 to 30th September 2018 (18 months) (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the period of investigation. The period of investigation has been divided into quarters for the purpose of injury analysis in view of shorter length of data of domestic industry.
- xiv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems & Data Management (DG Systems) to provide details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation.
- xv. The Applicants had submitted the application alleging dumping of the subject goods from China PR and Korea RP relying upon the transaction-wise import data sourced from the DGCI&S. The Authority had relied upon the data provided by the Applicants while initiating the present investigation. Post initiation, the Authority also obtained transaction-wise import data from the DGCI&S and DG System and issued the preliminary finding while relying upon the DG System data in view of higher volume reported in DG Systems as compared to DGCI&S. However, post issuance of preliminary finding, the interested parties contended that the volume of imports reported in application was materially lower than the volume of imports reported in the preliminary finding. On examination in detail, it was found that the DG Systems has reported data containing three kinds of imports i.e. based on bill of entry cleared for home consumption, ex-bond bill of entry and bill of entry for warehousing. It is noted that imports reported through bills of entry filed for warehousing and bills of entry filed for home consumption only ought to have been considered to avoid double counting. It is further noted that DGCI&S reports data only on the basis of bills of entry for home consumption and bill of entry for warehousing. In view of this, the Authority has now relied upon DGCI&S transaction-wise data for the purpose of present final finding. The Authority however notes that had DGCI&S data been considered in the preliminary finding, only the volume of imports would have been lower. However, the resultant decrease in volume of imports would not have impacted the trend, which continues to remain the same i.e. imports of the product under consideration have increased from subject countries over the injury period. Further, it is noted that the import prices reported in the DGCI&S data and the data considered by the Authority in the preliminary finding are almost the same.

- xvi. On-the-spot verification of the information / data provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of the present investigation.
- xvii. Desk verification was carried out for the data filed by the following producers/ exporters from China PR:
1. Shandong Gaoxin Chemical Co. Ltd, China PR
 2. Shandong Pujie Rubber and Plastic Co. Ltd., China PR
 3. Weifang Sundow Chemicals Co. Ltd, China PR
 4. Shandong Xuye New Materials Co. Ltd, China PR
 5. Shandong Xiangsheng New Materials Technology Co., Ltd, China PR
- xviii. Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The non-injurious price (NIP) has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure – III to the Rules.
- xix. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 19th August 2019. Further, a 2nd oral hearing was held on 3rd December 2019 in view of change in the Designated Authority, in the light of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyres Manufacturer Association vs Designated Authority. The parties, which presented their views in the oral hearing, were provided an opportunity to file written submissions of the views expressed orally, followed by submission of rejoinders.
- xx. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final finding.
- xxii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxiii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the finding on the basis of facts available.
- xxiv. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which forms the basis of the present Final Finding was issued to the interested parties on 29.01.2020. The post Disclosure Statement submissions received from the domestic industry and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Finding Notification.
- xxv. ***represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules. Information in () bracket indicates negative number/range.
- xxvi. The average exchange rate of 1 US\$ = Rs 66.61 prevailing during the period of investigation has been adopted by the Authority for the present investigation.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) - whether or not further processed into compound”.

C.1. Submissions made by the domestic industry

6. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to product under consideration:
- CPVC resin and compound are one article and cannot be seen in isolation as two distinct articles.
 - The production process employed for conversion of CPVC resin into compound is a mere incremental process as: -
 - Compounding does not require highly skilled labour.
 - Compounding is neither high-tech process nor highly skilled manpower process.
 - Compounding does not require lot of manual work.
 - Compounding investment is not significant.
 - Compounding being done by a party which does not even possess technology and the same is provided by resin producer.
 - Compounding has very low value addition.
 - For value addition, the value of additional/ other raw materials added is entirely immaterial.
 - The difference in the prices of two product types due to addition of other raw materials does not mean significant value addition made by the compound producers.
 - Resin is an intermediate product which eventually is to be converted into compound used for making pipes.
 - All the resin goes into making compound and is not consumed for any other applications.
 - Resin cannot be used as it is, and it has to be compulsorily further processed into compounds for making pipes and fittings.
 - Mere difference in the cost of production of different product types does not render them different products.
 - The Authority in past investigations such as Peroxosulphates, Caustic soda, Glass Fiber held multiple products inside the scope of PUC for an investigation.

C.2. Submissions made by the CPMA and AMAI

7. Following submissions have been made by Chemicals & Petrochemicals Manufacturers' Association (CPMA) and Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) with regard to product under consideration;
- CPVC Resins after minimal processing is being converted into compounds. Therefore, the Authority may include compound exported from a non-subject country, made from CPVC resin originating from the subject country, under the purview of the Anti-dumping duty. This is necessary to curb malpractices for avoidance of the anti-dumping duty, otherwise the levy would become totally ineffective.
 - The conversion of compound from resin is not a substantial activity and even after compounding the product essentially remains the same. It does not involve significant investment or technology or technical expertise for making a compound. The resin must necessarily be converted to compound before it can be put to use. Therefore, this process does not transform the essential characteristics of the product, but merely makes it usable for the relevant application.

C.3. Submissions made by the other interested parties

8. Following submissions have been made by the the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration:
- The product under consideration must not contain two products, but only one product.
 - Since the volume of CPVC compound is de-minimis, it warrants an exclusion.

- iii. The Applicants are attempting to include product much beyond the actual imports from the subject countries.
- iv. CPVC resin and CPVC compound are distinct from each other and the assessment of the two products in one investigation can only be done at the risk of bypassing the assessments pertaining to DI standing, dumping and injury distinctly due to the following reasons-
 - a. Resin and compound are entering the Indian market from different sources and different manufacturers.
 - b. Owing to different prices of the resin and compound, the products must be assessed separately.
 - c. The cumulation of various products in one is not as per law.
 - d. Upstream and downstream products should not be combined.
 - e. Lubrizol, which is a single producer of the subject goods has not been considered. This has led to manufacturers of downstream producers getting excluded from the investigation simply because they are the importers of the intermediate product.
- v. CPVC compound manufacturing is in the next step of production from CPVC resin and altogether a different product due to the following reasons: -
 - a. The production process of CPVC compound is different from CPVC resin.
 - b. There is a variation in the cost of production between CPVC compound and CPVC resin by 30% to 100%.
 - c. Many exporter producers of CPVC resin outsource the production of CPVC compound due to it being a high technical process.
 - d. CPVC resin is not a substitute of CPVC compound as both are commercially traded and treated independently and separately.
 - e. There is a vast difference in the selling price of resin and compound to the extent of three times. The fact that the product is derived from an 'incremental process' does not make the two products to be alike to be one product.
 - f. The value of additional raw material required for the production of compound from resin needs to be considered for the purpose of value addition.
 - g. There is a significant difference in the prices of CPVC resin and compound which can be seen from the import prices and the NIP of the domestic industry.
 - h. There is a difference in the import price by around 57% to 70% and in non-injurious price by around 29% to 37% and still both the articles are being considered as one single product.
- vi. The domestic industry itself has admitted to the fact that production of CPVC compound from resin is an extremely incremental process.
- vii. As per CESTAT in the Andhra Petrochemicals Ltd v. Designated Authority, products which are not being imported into India from a certain country could not be deemed to be causing any injury to the industry therein, and therefore no duty could be imposed on such a category of products.
- viii. The Authority in past has carried out individual and separate investigations for intermediate and downstream products.
- ix. The Applicants claim of CPVC plant being a capital-intensive project are vague and baseless. Such claimed high costs were prevailing 7-8 years back and do not represent today's scenario.
- x. In the investigation for Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles from China PR, the Authority assessed standing of the domestic industry, the injury parameters as well as the import volumes for "Front Axle Beam" and "Steering Knuckles" separately.

C.4. Examination by the Authority

- 9. The submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to the product under consideration and like article related issues have been examined below.
- 10. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) - whether or not further processed into compound".

11. The product under consideration is classified under Chapter 39 of Customs Tariff Act. Import data received from DGCI&S and DG Systems shows that the product has been imported under 39042110, 39042190, 39042210, 39042290, 39041090 and 39049000. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the present investigation.
12. The product is produced by chlorination via free radical chlorination reaction of Polyvinyl Chloride resin (Suspension PVC/ Mass PVC) and is significantly more flexible and can withstand higher temperatures than standard PVC. The chlorine content may vary from manufacturer to manufacturer. Various additives are introduced into the resin (CPVC compounding) in order to make the material processable. These additives may consist of stabilizers, lubricants, impact modifiers, processing aids, pigments.
13. CPVC is ideally suited for self-supporting constructions where temperatures go up to 90°C. CPVC exhibits fire-retardant properties. It is very difficult to ignite and tends to self-extinguish when not in direct contact of flame. It is used as a material for water piping systems in residential as well as commercial construction because it can withstand corrosive water at temperatures of 40°C to 50°C or higher. It is used in hot and cold-water plumbing distribution both at residential and commercial areas, fire protection, reclaimed water piping, chilled water piping, hydronic piping and distribution (radiators, fan coils, etc.) and is used in many industrial piping applications.
14. The product is significantly ductile, allowing greater flexure and crush resistance. Additionally, the mechanical strength of CPVC makes it a viable product to replace many types of metal pipe in conditions where metal's susceptibility to corrosion limits its use. CPVC is broadly classified into two grades, namely (a) Pipe grade and (b) Fitting grade on the basis of end use applications. Further, PUC can be produced through two processes, namely dry process and wet process. However, no significant difference in these forms of products on account of different processes or different grades has been reported by any party.
15. With regard to like article, Rule 2(d) of the Rules provides as under:-

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;
16. The Authority has examined the argument made by interested parties that CPVC resin and compound are distinct products as both are produced in different stages of processing. Based on the submissions made by the Applicant and the other interested parties, the Authority notes that CPVC resin is an intermediate product which eventually is to be converted into compound for making pipes and there is no other independent uses of CPVC resin. CPVC resin cannot be used as it is, and it has to be compulsorily processed into compound for making it usable, a fact that has not been disputed by the opposing interested parties. It is noted that difference in the cost of production and selling price is not the only criterion to treat one product different from the other. Compound is nothing but further processed form of CPVC resin to make it useable. It is also noted that compounding basically involves mixing of additives with resin without any substantial manufacturing activity. Therefore, the process to convert CPVC resin into compound is a mere incremental process and this process does not transform the essential characteristics of the product, but merely makes it usable. The very fact that the process involved in conversion of resin into compound does not lead to change in tariff code appears to suggest that the process is incremental in nature. Even if additives are to be considered in computation of value addition in the production phase between CPVC resin and compound, CPVC resin is the most expensive ingredient used to produce Compound. Besides, the end-use markets for

CPVC resin and compound, are essentially the same. CPVC resin and compound possess the same chemical structure and, CPVC resin imparts essential characteristic to compound. Most importantly, submissions on record show that a lot of compound manufacturers in India are importing CPVC resin and converting the same into compound. In view of this, exclusion of compound from purview of levy of anti-dumping duty is likely to lead to direct export of compound from subject countries to India, thereby nullifying the very purpose of entire exercise of imposition of anti-dumping duty. In view of the above, the Authority holds that the scope of product under consideration in the present investigation includes Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC), both in resin and compound form, as one article.
17. There is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that producers by the Applicants. Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) - whether or not further processed into compound produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers can use them

interchangeably. It is concluded that the goods produced by the Applicant are like articles to the product under consideration imported from the subject countries.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the domestic industry

18. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope of domestic industry and standing-

- a. The Applicants have neither imported the subject goods nor are related to any of the exporter or importer.
- b. At the time of filing of application, there was only one producer of the subject goods in India.
- c. M/s. Kem One Chemplast Private Limited has sought imposition of anti-dumping duty as the dumping of the subject goods has withheld its investment after substantial work on the project.

D.2. Submissions of other interested parties

19. The other interested parties have submitted as under with regard to domestic industry and standing-

- a. The Applicants are not the only producer of the subject goods in India and therefore, the present application is woefully inadequate and insufficient;
- b. The industry is not nascent industry.
- c. A major producer of CPVC compound named Lubrizol India, has been ignored in the present investigation simply because of the combined investigation. The Authority has not given any reason for the same.
- d. M/s Kem One Chemplast Pvt. Ltd. cannot be considered eligible to be within the scope of the domestic industry unless it is engaged in the manufacture and production of the like article.
- e. In one of the previous investigations regarding Flax Yarn from China PR, the Authority had not examined the status of Raymond Luxury Cottons which was not producing the subject goods in the period of investigation.
- f. RIL has also established a plant for manufacturing the subject goods.
- g. Respondent requests the Authority to consider domestic industry as "unestablished" if it proceeds on the ground that the establishment of the domestic industry may be materially retarded due to the subject imports.
- h. Front Axle beam and Steering Knuckle investigations have been referred to by other interested parties for defining the standing.

D.3. Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

21. The application had been filed by M/s DCW Limited and M/s Kem One Chemplast Pvt Ltd. The application was subsequently supported by M/s. Meghmani FineChem Ltd. Out of three entities, M/s DCW Ltd. is the only company engaged in production of CPVC resin and Compound in the period of investigation whereas, other two companies viz. M/s Kem One Chemplast Pvt Ltd and M/s. Meghmani FineChem Ltd have not yet commenced production. M/s. Meghmani FineChem Ltd is only at the conceptual stage of setting up of the project depending on the conditions of the market. However, they had expressed willingness to be part of the application. As for M/s Kem One Chemplast Pvt Ltd, they had finalized the project and had done lot of groundwork in setting up of the plant including technology transfer. It had submitted project reports. Therefore, the Authority considered M/s DCW Limited and M/s Kem One Chemplast Pvt Ltd as the domestic industry for the purpose of initiation of investigation and the preliminary finding.

22. The Authority notes that post issuance of preliminary finding, interested parties have contended that M/s Kem One Chemplast Pvt. Ltd. cannot be considered to be eligible within the scope of the domestic industry unless it is engaged in manufacturing and production of the like article. While it is noted that M/s Kem One have finalized the project and has done lot of ground work in setting up of the plant including technology transfer and also submitted its project report, it is also seen that the company has yet to take a number of steps before it commences its commercial production. The Authority, therefore, finds it appropriate to exclude M/s Kem One Chemplast Pvt. Ltd from the scope of domestic industry and only considers M/s DCW Ltd. as domestic industry.
23. There are few producers of CPVC compound who are buying CPVC resin either from DCW or importing the resin and processing the same to manufacture CPVC compound for making pipes. Companies who do not have manufacturing facilities for CPVC resin but are only compounders from purchased CPVC resin (indigenously and/or imported), including Lubrizol India, have not been considered as “domestic industry” within the meaning of Rule 2 (b) for the reasons that (a) the product under consideration in the present investigation is “Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) - whether or not further processed into compound. The subject good, thus, is CPVC resin or CPVC resin and compound. It is, thus, essential for the domestic producer(s) to be a manufacturer of CPVC resin, whether or not they are into the business of compounding the resin, in order to be eligible domestic industry and (b) the compounders sourcing CPVC resin domestically procure it only from DCW Ltd. on account of it being the sole producer of CPVC resin and, hence, inclusion of their production quantity would amount to double counting since production of DCW Ltd has already been taken into account.
24. M/s DCW Ltd. is not related to any importer or exporter of subject goods in the subject countries nor have they imported subject goods from subject countries. M/s DCW Ltd. is importing MPVC for manufacturing of CPVC, from countries other than subject countries. M/s DCW Limited, being the sole producer of the product under consideration, accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods and constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the domestic industry

25. The domestic industry submitted as under, with regard to confidentiality:
 - a. Hanwha Chemical Corporation has a sales office in India but the details regarding it have not been disclosed in the non-confidential version of the EQR.
 - b. In spite of the fact that the details of captive raw materials and utilities are available on the website of Hanwha Chemical Corporation, their names have been claimed as confidential in the NCV of the response.
 - c. As per publicly available information, Hanwha Chemical Corporation undertakes significant research & development activities within the company, with group companies and with other entities.
 - d. Hanwha Chemical Corporation produces PVC and chlorine captively and thus exporter is required to establish that the transfer price is reflective of fair market value. However, the reply has been claimed confidential by the producer.
 - e. The Authority has provided detailed analysis of data claimed confidential, which lends reasonable understanding to other interested parties.
 - f. Reference to the Reliance Industries vs Designated Authority [2006(202) ELT 23 (SC)] is misplaced as the decision talks about confidentiality claimed by the Authority from the party supplying the said data.
 - g. The Applicant has provided all the information which it was obliged to provide on non-confidential basis.
 - h. Because a number of producers are planning to set up capacities in India, therefore the project report is highly confidential and hence cannot be shared.

E.2. Submissions made by the other interested parties

26. The other interested parties argued, as under, with regard to confidentiality claims of the domestic industry:

- a. The information which has not been claimed confidential by the Applicant, cannot be claimed confidential by the Authority. The petitioner in the petition has provided indexed figures in respect of production, sales, capacity utilization, inventory and closing stock as noted above, however, the Authority has gone one step further by treating all such information as confidential in the preliminary finding. In other words, the Authority has exceeded its jurisdiction to assume information as confidential, which was not claimed to be confidential by the petitioner itself in the petition. This is in direct violation to the decision of Hon'ble Supreme Court of India in the case of Reliance Industries Ltd vs Designated Authority [2006(202) ELT 23 (SC)] as well as order of Larger Bench of Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India vs Meghmani Organics Ltd [2016 (340) E.L.T. 449 (S.C.)], wherein the Hon'ble Court held that the AD Rules do not contemplate any right in Designated Authority to claim confidentiality and Authority does not have any power to assume confidentiality on its own.
- b. Adjustments made in the export prices cannot be claimed confidential in the non-confidential version of the response.
- c. The non-confidential version of the application does not allow a reasonable understanding of the domestic industry's claim.
- d. The Applicant must be directed to provide the non-confidential copy of the project report and other claims made in respect of material retardation.
- e. The adjustments in the net export price cannot be claimed confidential in the non-confidential application.

E.3. Examination by the Authority

27. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

28. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

F. MISCELLANEOUS

F.1. Submissions made by the domestic industry

29. The submissions made by the domestic industry are recorded below -
- a. Applicant has already stated the methodology used to arrive import data in the written submissions filed before the Authority.
 - b. The Authority in past recommended anti-dumping duty in case of material retardation for a period of 5 years.
 - c. The imports in India are coming at higher prices from the other subject countries and still the Indian industry has been seeing a growth in the consumption. This shows that the imposition of the duty will not be against the public interest.

- d. The Korean Government should not be concerned by the rise in prices of CPVC in the Indian market if the duties are imposed.
- e. There has been no instance of consumers being unable to buy the raw material or absorb the price increase.

F.2. Submissions made by other interested parties

30. The miscellaneous submissions made by the interested parties are recorded below:

- a. The Authority has no power, under Indian law, to recommend imposition of provisional measures to address a situation of material retardation to the establishment of the domestic industry.
- b. The Authority has failed to record any examination, in terms of Section 9B (1)(b)(iii) of the Customs Tariff Act, 1975, that a duty is necessary to prevent injury being caused during the investigation.
- c. Under the WTO anti-dumping agreement, provisional duties cannot be imposed in case of material retardation to the establishment of domestic industry.
- d. The Authority's assessment of the ground of "material retardation" is flawed.
- e. The Authority has failed to record or examine any of the claims and submissions put forth by the Respondents in their injury submissions dated 31st May 2019.
- f. The Authority's analysis of the Applicant's data is misguided and fails to consider the factors pointed out by the Respondents.
- g. The Authority's analysis of the Application is incomplete in certain parts and draws conclusions without an actual assessment.
- h. The Authority has not recorded submissions made by other interested parties in its preliminary finding. While the submissions of Applicant are recorded, no examination thereof has been done.
- i. The Authority has placed reliance on the import data from DG Systems rather than DGCI&S data for determining the preliminary finding. No justification has been provided by the Authority to consider the DG System's data as appropriate and DGCI&S data as incorrect.
- j. The Applicant should be directed to provide a copy of methodology that has been used to arrive at the import data considered.
- k. It will not be in public interest to impose anti-dumping duty on CPVC. The overall purpose of the domestic industry is to eliminate competition and enjoy monopoly. This will affect the performance of the downstream industry.
- l. Levy of anti-dumping duty on CPVC will create an unfair competitive environment and would harm the fundamental interests of their respective industries in the long term.
- m. The imposition of anti-dumping duty would lead to rise in local prices of CPVC or the benefit will get transferred to countries not attracting anti-dumping duty.
- n. The imposition of preliminary duty has led to rise in price of CPVC around 30-40%.
- o. The imposition of provisional anti-dumping duty has done more harm than good to the Indian CPVC market, without actually bringing any substantial benefit to Indian domestic industry.
- p. The Authority has followed a practice of recommending definitive anti-dumping duty for a lesser period (up to 2 or 3 years) in case of material retardation since duty recommendation for a period of 5 years may not be justified.
- q. Hanwha

F.3. Examination by the Authority

31. The submissions made by the domestic industry, exporters, importers, users and other interested parties with regard to various issues, considered relevant by the Authority, have been examined as under-

- a. As regards the contention that the Authority does not have the power to recommend the provisional duty in case of material retardation, the Authority notes that none of the provision under the Rules states that the provisional duty cannot be imposed in case of material retardation. Recommendation of provisional duty by the Authority in the present investigation is as per the Rules.
- b. As regards to the contention that the Authority has not recorded submissions made by other interested parties in its preliminary finding, the Authority notes that after issuance of the preliminary finding, the

Authority has granted oral hearing and parties were advised to file their written submissions as well as rejoinders. The Authority also provided 2nd Oral hearing in view of the change of the Designated Authority followed by written submissions and rejoinder submissions. All the relevant submissions have been recorded and examined in the finding.

- c. As regards the contention that the Authority had not given reason for relying on the import data from DG Systems rather than DGCI&S data in the preliminary finding, it is clarified that since volume of imports reported in DG Systems data was higher as compared to the DGCI&S data, the Authority adopted the DG Systems data at the time of the preliminary finding with a view to account for entire import of the subject goods. However, post issuance of preliminary finding, the interested parties contended that the volume of imports reported in application was materially lower than the volume of imports reported in the preliminary finding. On examination in detail, it was found that the DG Systems has reported data containing three kinds of imports i.e. based on bill of entry cleared for home consumption, ex-bond bill of entry and bill of entry for warehousing. It is noted that imports reported through bills of entry filed for warehousing and bills of entry filed for home consumption only ought to have been considered to avoid double counting. It is further noted that DGCI&S reports data only on the basis of bills of entry for home consumption and bill of entry for warehousing. In view of this, the Authority has now relied upon DGCI&S transaction-wise data for the

purpose of present final finding. The Authority however notes that had DGCI&S data been considered in the preliminary finding, only the volume of imports would have been lower. However, the resultant decrease in volume of imports would not have impacted the trend, which continues to remain the same i.e. imports of the product under consideration have increased from subject countries over the injury period. Further, it is noted that the import prices reported in the DGCI&S data and the data considered by the Authority in the preliminary finding are almost the same.

- d. As regards the contention that the imposition of the duty on CPVC will not be in public interest, the Authority notes that the duty essentially aims to address unfair trade practice.
- e. As regards the contention that the imposition of the anti-dumping duty would lead to rise in local prices of CPVC or the benefit will get transferred to countries not attracting anti-dumping duty, it is noted that the import prices from third countries are higher than the dumped prices from subject countries. Imposition of antidumping duty in India will only give level playing field to the domestic industry, ensuring a competitive market for producers of subject goods in India. It will help India develop domestic manufacturing base for subject goods in India so that Indian consumers can benefit both from the domestic as well as global production of the subject goods.
- f. As regards the contention that the imposition of preliminary duty has led to rise in price of CPVC by around 30-40%, the Authority notes that imposition of ADD would remove the unfair advantages gained by dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

G. DUMPING AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made by the domestic industry

32. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - a. The dumping margin calculated for the subject countries is significant.
 - b. None of the interested parties have claimed market economy status.
 - c. The normal value in case of China should be determined on the basis of import price into India from Japan, Thailand or USA as these three countries reflect the actual normal value in accordance of provisions of para-7 of Annexure-I.
 - d. The interested parties were given sufficient notice of surrogate country being considered for the purpose of normal value as the same was communicated in Para 10 of the initiation notification.
 - e. Since the consumption price in the domestic market is higher as compared to the export price and where the exporter has been repeatedly stating that the prices of CPVC resin is twice the price of PVC suspension resin, it is clear that price at which Hanwha has sold CPVC in the domestic market in Korea is not a price in the ordinary course of trade.
 - f. Hanwha Chemical Corporation has probably sold the product practically to two or three customers in Korea only. Thus, there is a possibility that the prices of the Korean producer may have an element of “development of its product”, which renders these prices as unreliable.

- g. Cost of production of Hanwha Chemical Corporation as provided to the Authority, cannot be accepted for determination of normal value
- h. In accordance of the provisions of section 9A 1(C), the normal value in case of Korea RP can be based on the import prices of subject goods in Korea.
- i. Details about calculation of export price have been provided as required by the trade notice.
- j. The calculations of dumping margin for the Korean producer in the preliminary finding should be considered for final finding as the producer has not been able to determine how its cost and selling price shall be accepted.
- k. The response filed by Hanwha Chemical Corporation needs to be rejected as the exporter has suppressed significant information in the response filed.
- l. The price from a market economy third country to India and the price paid or payable in India duly adjusted seems to be at the same level of determination and hence can be considered as normal value.
- m. Normal value cannot be determined based on cost of the producer exporter if it can be determined based on the first condition i.e. consumption price.
- n. The interested parties have not provided any information in regard to an appropriate third country.
- o. The importer has not substantiated anything for not considering import prices from Thailand as not reliable. Nothing has been provided by the importer in importer questionnaire response filed by them.
- p. The mere fact that it was held in Nylon Tyre Cord Fabric case that Thailand could not be considered appropriate surrogate country for that case, it does not necessarily imply that Thailand cannot be considered as an appropriate surrogate country even for the present case.
- q. The import price from Thailand has been adjusted with port expenses, overseas freight, marine insurance, inland freight, bank charges and profit to determine the normal value.
- r. The fact that imports from Thailand enjoy benefit of FTA in form of custom duty is irrelevant as the Applicant has compared the CIF import prices.

G.2. Submissions made by other interested parties

33. The submissions made by the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- a. Hon'ble Supreme Court in Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. vs Exide Industries Ltd [2005 (181) E.L.T. 320 (S.C.)] has clearly held that the normal value in case of China PR has to be determined in a sequential manner. Authority has altogether skipped to examine whether the first alternative could be adopted in the present case. The Authority has nowhere stated in the preliminary finding as to why the first method - price or constructed value in a market economy third country cannot be adopted.
 - b. Authority did not propose selection of Thailand as an appropriate third country for normal value before recommending preliminary finding. Further, no reasoning was provided for choosing the highest import price amongst the available options.
 - c. The Authority will have to justify considering import price from market economy third country to India as a basis of determining normal value.
 - d. There is no finding on the level of development of the proposed country or product. Level of development in Thailand has been compared with the level of development in China.
 - e. Imports from Thailand would not be sufficient to show price paid or payable as it would be based on as the source of sample selected which would be extremely limited and not reflective of actual price paid or payable.
 - f. Thailand cannot be considered as an appropriate third country for China.
 - g. The Authority has not considered the difference in the rate of duties applicable on imports from Thailand and China due to FTA
 - h. Since the exporter from Thailand has a related importer i.e. Lubrizol India in India, the prices need to be checked minutely.

- i. As per Grunwald Logistik Service GmbH V Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Case C-338/10), the choice of third country should be appropriate.
- j. The import prices of Japan, Thailand & USA cannot be considered for the purpose of normal value calculation for China as these imports are under exclusive license and hence are at higher prices.
- k. The Authority is requested to consider the consumption norms of the exporters even if the MET is not granted.
- l. In the past investigation concluded by Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) originating in or exported from China PR (13th April 2015), Thailand was not considered appropriate third country.
- m. The response of Hangzhou Electrochemical New Material Co., Ltd has been rejected on account of non-related producer not participating in the investigation. The producer cannot compel an unrelated exporter to participate in an investigation.
- n. Shandong Pujie Rubber and Plastic Co. Ltd. is not exporting CPVC Compound to India but still has been assigned residual rate with respect to CPVC Compound.
- o. Domestic sales made by M/s HCC of *** MT during POI and exports made to India were *** MT which is around ****% of exports to India. The domestic sales are made through an unrelated buyer. The quantum of domestic sales suffices the criteria for considering the same for consumption of normal value.
- p. The cost of PVC, chlorine, steam has been rightly captured by the exporter in the COP.
- q. The basis adopted by the Applicant for proposing the normal value is flawed. The invoices provided by the Applicant are untraceable.
- r. The Authority in the investigation for Calcium Carbide from China has determined that normal value cannot be determined based on few invoices.
- s. The startup cost incurred by Hanwha Corporation has been duly adjusted as per Korean Accounting Standards.
- t. There is no suppression of the fact of the Hanwha Corporation. It has provided all the details in the response.

H. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN;

H.1. NORMAL VALUE FOR CHINA

34. Following producer exporters from China have filed the exporter's questionnaire response-
 - a. Shandong Gaoxin Chemical Co Ltd
 - b. Shandong Pujie Rubber and Plastic Co. Ltd
 - c. Hangzhou Electrochemical New Material Co. Ltd
 - d. Weifang Sundow Chemical Co. Ltd
 - e. Shandong Xuye New Materials Co. Ltd
 - f. Shandong Xiangsheng New Materials Technology Co., Ltd
35. Under Annexure-I, Para 7 of the Rules, the normal value for non-market economy would be determined as:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question], and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

36. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph 7 of Annexure-I of the Rules and claimed normal value in China on the basis of import prices into India from third countries namely; Japan, Thailand and USA, as the Applicant could not get relevant information on price or constructed value in market economy third country. While acknowledging the Applicant's claim to consider import price from Japan, Thailand or USA to determine normal value in China, the Authority had, for the purpose of initiation, constructed normal value of subject goods in China on the basis of cost of the Indian producer.
37. After the initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent questionnaire to all known producers/ exporters, giving them an opportunity to establish normal value on the basis of their own cost/price, by rebutting presumption of non-market economy, in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China PR to advise the producers/exporters in China to provide the relevant information. The known Chinese producers/ exporters and the Government of China PR were adequately notified about the requirement of information in the form and manner prescribed and adequate opportunity was granted to them to make their submissions in this regard. A number of producers/exporters have responded to the present investigation. However, none of them filed relevant questionnaire response to enable the Authority to examine whether or not their cost and prices were market driven. Further, barring claim of domestic industry, none of the interested parties have provided any other alternative basis, as defined in the Rules, on which normal value can be determined. The interested parties, while disputing the claim of the domestic industry, have not provided any information for determination of normal value in China.
38. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy claim by any Chinese exporting company, the Authority considered it appropriate to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value for the preliminary determination. Paragraph 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that *normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin*. Thus, the Authority noted that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under para 7 of Annexure-I to the Rules.
39. After preliminary finding various interested parties contended that no opportunity was provided to them with regard to selection of Thailand as appropriate market economy third country in terms of para-7 of Annexure-I of the Rules. The Authority notes that the claim of Applicant for treating export price from an appropriate market economy third country to India for determination of normal value was well brought out in the notice of initiation itself and a copy of the application was made available to all interested parties. In any case, since the Authority issued preliminary finding wherein export price from Thailand to India was considered for determining normal value and comments were invited on the same, the interested parties have got sufficient time and opportunity to comment on the proposal for considering Thailand as an appropriate market economy third country. It is noted that either at the stage of initiation or thereafter upon issuance of preliminary finding, none of the interested parties, barring domestic industry, has made any suggestion with regard to an appropriate market economy third country. Even after the preliminary finding, none of these parties have suggested any option which authority should adopt for determining normal value in China.
40. As regards the submissions that the Authority has not determined normal value for China PR in a sequential manner as held by the Hon'ble Supreme Court, the Authority notes that Normal Value for a country considered as a non-market economy is required to be computed in accordance with para 7 and 8 of Annexure-I of the Rules. In the instant case, since none of the exporters have filled up supplementary questionnaire, the options under para 7 of Annexure-I to Rules need to be explored. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7. Since, there is no information on record with regard to cost or price in Thailand, normal value could not be determined on the basis of it. Further, since sufficient information is available with regard to the price at which product under consideration has been exported from Thailand to India, the same cannot be ignored

and option of adopting “any other basis” listed under the law cannot be adopted. The Authority, therefore, considers that the appropriate option available to the authority is to adopt export price from Thailand to India which could be considered for determining normal value.

41. The interested parties have contended that Thailand cannot be considered as appropriate market economy third country in view of level of development, relationship with importer in India, difference in customs duties due to FTA and higher prices due to exclusive license. It is noted that the Authority is required to consider the level of development of the product and the country for determining appropriate market economy third country. The Authority notes that as far as the level of economic development is concerned none of the producers/exporters/importers/users have suggested any appropriate market economy third country. On the other hand, the domestic industry had suggested Thailand, Japan and U.S.A as appropriate market economy third country. Considering the options available viz. Japan, US or Thailand, the Authority notes that China PR and Thailand are more comparable in terms of level of economic development on various parameters. Thailand has also been considered as an appropriate market economy third country for China by other prominent trade remedy user WTO member countries like U.S.A. and European Union. Further, from transaction wise import data from DGCI&S, it is noted that while China PR accounts for 53,104 MT i.e. 27% of total imports of subject goods during POI, similar level of imports are from Thailand at around 51,808 MT constituting 28% of total imports into India, which indicates that the level of development of this particular product in China is comparable with that in Thailand. Also, the volume of import from Thailand is the highest amongst non-subject countries. Thailand being a non-subject country with no ADD measure in force and with import volume being quite significant, the CIF price from Thailand is representative in nature. It is further noted that the difference in customs duty also becomes irrelevant since normal value is computed in this case on the basis of export price from Thailand at ex-factory level. The customs duties would have been relevant only if the Authority had considered the price paid or payable in India. As regards relationship between exporter and importer, Authority notes that no evidence has been provided that the price reported to customs authorities is not appropriate. Mere existence of relationship in itself does not mean that the price is not reliable. In view of the above, the Authority has considered Thailand as the appropriate market economy third country and determined the normal value in terms of para 7 of Annexure-I of the Rules. The Authority accordingly considers that the most appropriate basis in the present case is the price at which goods have been exported from Thailand to India. The Authority has made appropriate adjustments on various elements like ocean freight, port expenses, inland freight, credit cost and marine insurance and bank charges as per consistent practice for arriving at an ex-factory price. The normal value so constructed is mentioned in the dumping margin table.

H.2. Normal value for Korea RP

42. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

43. Only one producer, namely M/s Hanwha Chemical Corporation, Korea has filed the Exporter questionnaire response along with its related entity, namely M/s Hanwha Corporation. The questionnaire responses filed by the producer and exporter have been examined. At the time of issuance of preliminary finding, it was found that the questionnaire response was not in the form and manner prescribed. For

example, Appendix 7 & 8 did not conform to the prescribed format, complete details of cost of production of captively consumed raw material were not submitted, formats submitted were uncertified, etc. The information submitted by producer/exporter was, thus, incomplete and not sufficient to enable the Authority to compute the cost of production. Therefore, at the time of issuance of preliminary finding, the Authority had decided not to consider the claimed domestic selling prices of the producer.

44. After issuance of preliminary finding, the Authority issued two deficiency letters pointing out the discrepancy to Hanwha Chemical Corporation. The producer responded to both the deficiency letters. It is now noted that there are significant changes in the data provided by the producer at different stages, as outlined below.
 - i. The volumes regarding production of PVC suspension, which is the primary raw material for producing CPVC, have been changed significantly in replies to the first and second deficiency letters as compared to the initial response.
 - ii. The producer has not filed complete information in Appendix-7 as per prescribed questionnaire at the time of original questionnaire response and failed to provide the essential information in respect of complete cost detail such as utilities, packing, consumable and store, depreciation, repair, R & D expenses, other manufacturing overhead, other administration overhead etc.
 - iii. The information pertaining to cost of sales and profit/ (loss) for the company as a whole as well as for the product under consideration was not provided in Appendix-7 initially. The producer/exporter subsequently provided the information relating to profit/(loss) in reply to the deficiency letters but changed the cost of sales and the profit/loss figures for the company as a whole as well as for the PUC.
 - iv. The producer/exporter failed to provide complete sales details of the products produced and consumed captively as well as sold in the market despite deficiency letters issued by the Authority.
45. As is clear above, the Authority notes that despite providing adequate opportunity to comply with the requirements, Hanwha Chemical Corporation changed the data of selling, general and administrative expenses, cost of production/ sales and profit/loss of the company as well as for the PUC. Besides, they have provided non-representative details of sales of captive input. The suppression of this essential data by the producer/exporter creates doubts on the credibility of whatever data has been provided. Further, the change in the essential basic data also questions the reliability of the data provided by the producer/exporter. Therefore, the Authority finds that the information provided by the producer/exporter is unreliable and thus rejects the response in its entirety.
46. Hanwha is the sole producer of subject goods in Korea. In view of rejection of response of the producer/exporter and the unreliability of the data of this sole producer of PUC in Korea, the consideration of option of either the domestic selling price in Korea or the export price to third country cannot be considered. Moreover, the normal value can also not be constructed on the basis of cost of production in the Korea as the data of sole producer/exporter of the PUC has been found to be unreliable.
47. In the absence of all the above options, the Authority has proposed to determine normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The domestic industry has claimed that normal value in Korea to be determined on the basis of the import prices of subject goods into Korea. The domestic industry has claimed that producer in Korea has only recently built the capacity for manufacture of the PUC and therefore large portion of the Korean demand for the PUC is still being met by the imports. The domestic industry has stated that the domestic demand of PUC in Korea RP is *** MT/ annum as per the information available in the public domain and that majority of this demand is being met by imports of PUC from Japan and therefore the import price of PUC from Japan into Korea RP should be taken for construction of normal value in Korea RP. In support of their claim, the Applicant has furnished sales invoices evidencing approx. 50% of export of the PUC from Japan to Korea. The Authority has explored the possibility of taking average import price from Japan to Korea and has accordingly analyzed the World Trade Atlas (WTA) data to ascertain the import price from Japan to Korea. It was however noted that the bifurcation of CPVC resin and CPVC compound data was not available in the WTA data on account of both these items, CPVC resin and CPVC compound, having same tariff code. Since separate normal values have been determined for CPVC resin and compound in this investigation for the reasons mentioned, taking average import price reported under WTA data will be inappropriate. In view of the above, the Authority has relied upon the invoices furnished by domestic industry for determination of normal value and export price in terms of Rule 6 (8) of Rules. The normal value and export price so calculated is given in the dumping margin table.

48. M/s Hanwha Chemical Corporation has filed a request vide its letter dated 16.01.2020 for change of name from Hanwha Chemical Corporation to M/s Hanwha Solutions Corporation with effect from 6th January, 2020 as two more entities with different business activities i.e. Qcells and Advanced Chemicals merged with M/s Hanwha Chemical Corporation. The said letter has been taken on record and is placed in public file.

I. DETERMINATION OF EXPORT PRICE

I.1. Export price for China PR

- i. Export Price for (i) Shandong Gaoxin Chemical Co Ltd, (ii) Shandong Pujie Rubber and Plastic Co. Ltd, (iii) Weifang Sundow Chemical Co. Ltd, (iv) Shandong Xuye New Materials Co. Ltd and (v) Shandong Xiangsheng New Materials Technology Co., Ltd**

49. The Authority has relied upon the details of exports as given in Appendix 3 by the producers/exporters. The adjustments towards inland freight, ocean freight, port and other related expenses, insurance, credit cost, bank charges, VAT refund and packing cost have been accepted as claimed by the producer exporters. One of the producers have claimed the adjustment in export price on account of level of trade, however, the same has not been allowed by the Authority. The export price for PUC (for resin and compound) determined at ex-factory level is shown in the dumping margin table.

ii. Export Price for Hangzhou Electrochemical New Material Co. Ltd

50. M/s Hangzhou Electrochemical New Material Co. Ltd has filed response for Hangzhou Electrochemical New Material Co. Ltd and Hangzhou Electrochemical Group Co. Ltd. The examination of the response revealed that the producer has exported directly to India and also through unrelated exporter. Since the unrelated trader namely, Chiefdo Ltd., through whom majority of the exports to India has been made by producer namely, M/s Hangzhou Electrochemical New Material Co. Ltd, has not filed questionnaire response, the Authority rejects the response.

iii. Export price for all producers/exporters from China PR

51. The export price for other non-cooperative producers / exporters from China PR has been determined on the basis of facts available in term of Rule 6(8) of the Rules.

I.2. Export price for Korea RP

Export price for all producers/exporters from Korea RP

52. The export price for all the producers/exporters from Korea RP has been determined on the basis of DGCI&S transaction wise import data. Due adjustments have been made to arrive at ex-factory export price.

J. DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

53. The dumping margin determined in the present investigation for all the subject countries is furnished in the following table: -

S. N.	Particulars	Normal Value	Ex-factory Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	(%)	(Range)
A	China PR					
		Resin				
1	Shangdong Gaoxin Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	40-60
2	Shangdong Pujie Rubber and Plastic Co Ltd	***	***	***	***	50-70
3	Shandong Xiansheng New Material Technology Co Ltd	***	***	***	***	40-60
4	Wei fang Sundow Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	40-60
5	Shangdong Xuye New Material Co Ltd	***	***	***	***	50-70

6	All others	***	***	***	***	60-80
		Compound				
1	Shangdong Gaoxin Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	0-20
2	Shangdong Pujie Rubber and Plastic Co Ltd	-	-	-	-	-
3	Shandong Xiansheng New Material Technology Co Ltd	-	-	-	-	-
4	Wei fang Sundow Chemical Co. Ltd	-	-	-	-	-
5	Shangdong Xuye New Material Co Ltd	***	***	***	***	20-40
6	All others	***	***	***	***	20-40
B	Korea RP					
				Resin		
1	All producers/exporters	***	***	***	***	30-50
				Compound		
1	All producers/exporters	***	***	***	***	30-50

K. INJURY AND CAUSAL LINK**K.1. Submissions made by the domestic industry**

54. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- a. The demand of the subject goods has seen an increase over the injury period with the year 2016-17 showing a slight decline. On a quarterly basis, the demand of the product has seen an increase.
- b. The share of subject imports shows an increase. The share of imports is as high as 30% in some of the quarters.
- c. Import volume from other countries have increased but they are high priced and are not causing any harm to the Indian industry.
- d. The market share of the domestic industry is abysmally low as compared to the level it could have achieved. Further, even this level of market share was achieved after the domestic industry significantly reduced its selling prices.
- e. The volume of imports from subject countries have increased in absolute terms and in relation to consumption despite the domestic industry commencing its production.
- f. The prices of subject imports are lower than the prices of imports from non-subject countries.
- g. The production and capacity utilization of the domestic industry has seen an increase but still has not reached the optimum level in spite of 18 months production. The utilization of the domestic industry is still below 80%.
- h. The sales of the domestic industry have remained low.
- i. The domestic industry has been putting efforts to increase their production. However, due to cheap and dumped imports it has been left with level of inventories piling up.
- j. The low level of sales is neither due to technical constraints in new plant nor due to non-acceptance of product by customers.
- k. The selling price of the domestic industry is far lower as compared to the optimum and actual cost of sales.
- l. The selling price of the domestic industry is far below the targeted selling price.
- m. The imports are coming at a price lower than the actual and the optimum cost of sales of the domestic industry.

- n. The domestic industry will only be able to recover around 50% of costs even at its reasonable level of costs.
- o. The dumped imports are suppressing the prices of the domestic industry to an extent that the domestic industry will not be able to increase prices even at the level of optimum production.
- p. Since the domestic industry does not have data for the historical performance of the product under consideration, price suppression and depression should be determined based on period of investigation itself.
- q. Price undercutting was positive in the first quarter of 2017-18. However, post that the domestic industry was forced to reduce its prices and hence the undercutting was negative.
- r. Even the non-injurious price at 100% plant utilization shows positive price underselling.
- s. The domestic industry has been facing loss per unit sold and facing cash losses and a negative return.
- t. Even when the sales of the domestic industry were highest, the losses of were at highest level.
- u. Even with cost at 100% capacity utilization will lead to losses due to the low selling prices because of the dumped imports.
- v. The volume parameters of the domestic industry show an increase during the injury period, but it is only due to the fact that the Applicant is a new producer. The growth is much lower than the expected growth.
- w. Even the producers setting up capacities in India are rethinking about investing in the product because of the significant dumping happening in the Indian market. This shows that the ability to raise capital investment will be hampered.
- x. The dumped imports have been flowing in from the subject countries at an alarming rate which shows that the India is a market for these exporters. With the imports coming in such increased quantities they would be serious threat to all domestic industry and hence would restrict industrial development.
- y. The landed price of the imports has been suppressing the prices of the budding domestic industry. With the demand of the goods likely to increase, the imports are more likely to suppress the prices of the domestic industry and will force the domestic industry to stop producing due to unabated losses.
- z. The producer of subject goods in the subject countries are having surplus production capacities.
- aa. There are sufficient evidences to show export orientation of the producers in subject countries.
- bb. The growing demand of the subject goods in the Indian market gives the exporter an incentive to aggressively pursue exporting to India.
- cc. The domestic industry has been in operation for only 18 months and has already faced huge losses
- dd. The domestic industry has not been able to sell at reasonable prices.
- ee. Material retardation as a form of injury is able to address the issue of those industries who are at their very initial stage of establishment.
- ff. The subject imports are preventing the establishment of the domestic industry in the market.
- gg. The actual performance of the Domestic industry is quite adverse to the projections made before setting up the plant.
- hh. There are no other factors that could cause injury to the domestic industry.
- ii. Prejudice has been caused to the interest of the domestic industry as the start-up cost has been considered at optimum capacity utilization.
- jj. In order to calculate the demand and supply gap, imports from rest of the world are not required to be considered as the duties are not being sought on them.
- kk. Number of fresh investments in the product are being planned because of the fair market situation being created through interim duty.
- ll. The post period of investigation data shows increases in the import price.

- mm. As against the claim of the interested parties, DCW has not at all suffered injury due to any kind of water scarcity.
- nn. The Applicant being a new industry, consideration of a longer period of time would allow the Authority with more quantitative information.
- oo. There is no provision to determine NIP based on prospective period of investigation. The Authority has not undertaken such a practice in any other past material retardation case.
- pp. There is no legal requirement to provide separate injury information for resin and compound as they are merely two different forms of like article.
- qq. The inability of the domestic industry to meet the demand of the product in the market cannot deprive it from protection against dumped imports.
- rr. Dumping of the subject goods is preventing the domestic industry from starting investments in the project.
- ss. The production capacities in China and Korea are more than the demand in subject countries. Demand is hardly 10% and 25% of the installed in the China and Korea respectively.
- tt. Further capacity expansions are being planned in India. If the capacities reported are actually installed, the capacity in India would soon cross the demand of subject goods in India.
- uu. Even when 18 month period of investigation has been considered for determining the non-injurious price, the analysis has been done on quarter to quarter basis. Further there is no provision in the law to consider prospective period of investigation as contended by some interested parties.
- vv. The domestic industry has suffered both volume and price injury because of dumped imports and not due to unacceptance of the new product.
- ww. There have been numerous investigations in past where in spite of the price undercutting being negative, the Authority had concluded that the imports were causing injury to the domestic industry.
- xx. Reliance placed by some interested parties on other irrelevant investigation are inappropriate.
- yy. Since Kem One has not commenced commercial production, there is no data of it that can be considered for determining non-injurious price.

K.2. Submissions made by other interested parties

55. Following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link:
- a. Authority has not disclosed the methodology adopted for the construction of the non-injurious price.
 - b. While the Authority has considered CPVC resin and compound as one article, it has provided separate duty and margins. The same principal should also be followed for assessment of subject countries.
 - c. The application contains only start-up conditions of an industry and not injury by the alleged dumped imports.
 - d. The Authority has not considered other significant factors such as product mix of subject country prices vis-à-vis other country price.
 - e. There is no guideline which has evolved for determination of "material retardation" under Indian law and thus, the initiation of the subject investigation is bad in law.
 - f. It is not clear whether the overall and the material injury determined by the Authority in the preliminary finding is based on data and information of only one producer or both the producers.
 - g. The Authority in one of the earlier investigation of imports of Non-Woven Fabric had examined prospective data for the material retardation examination. The Authority should conduct a similar examination in this investigation as well.
 - h. As held in the Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) V. Designated Authority, mere increase in inventory does not show injury.
 - i. The Authority in the investigation of X-Ray Security Inspection Equipment from the European Union has held that if there is a negative undercutting, the dumped imports cannot suppress the selling price of the domestic industry.
 - j. When the prices from non-subject countries have increased, the domestic industry must explain why it could not match the prices of the non-subject countries.

- k. The domestic industry will not be able to meet the demand of the Indian Industry.
- l. There is negative price undercutting. Had the domestic industry increased its prices, the producers in the subject country would also be forced to increase their prices.
- m. As per Annual Report of DCW Limited, the scarcity of water was reason for the low productivity.
- n. The Applicant has not suffered any material retardation as there is no guideline to oversee the application of material retardation under current legal provisions in India
- o. Causal link analysis is to be examined only for the period during which the Domestic Industry has been producing the like article. The imports from other countries which are claimed to be at un-dumped prices have increased in relation to imports from the subject countries.
- p. The Applicant is relying merely on some of the news article to show capacity expansion which does not give sufficient evidence that capacity addition will be undertaken.
- q. The share of non-subject countries was higher than share of Korea and China. The Authority should have examined the inclusion of non-subject countries.
- r. If the domestic industry cannot compete with 25% of total imports catering to 20% of the total demand, then it cannot become world leader.
- s. The performance of the domestic industry has improved in post- period of investigation.
- t. Even the Applicant has admitted to the fact that the imports in the preliminary finding are overstated.
- u. The domestic industry must be asked to explain why it could not fetch prices equivalent to the prices of other countries.
- v. There is nothing on record to show that there has been a decline in import prices, increase in volumes or fall in raw material prices in the post period of investigation data.
- w. Comparison of PVC to CPVC has no relevance for the purpose of this investigation.
- x. The domestic industry has deflated the price of goods from non-subject countries.
- y. No factor has been attributed by the domestic industry for material retardation.

K.3. Examination by the Authority

- 56. The Authority has taken note of the arguments and counterarguments of the all the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 57. It is noted that Rule 11 dealing with injury specifies that the Authority shall record a finding whether dumped imports of such article into India cause or threaten material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India. Further, it specifies that the Authority shall determine the injury to Domestic Industry, threat of injury to Domestic Industry, material retardation to establishment of Domestic Industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out under the rules.
- 58. Recommendation by the WTO Committee on Anti-Dumping Practices suggests that as a general rule the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case not less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable, while the period of data collection for injury investigations normally should be at least three years, unless a party from whom data is being gathered has existed for a lesser period, and should include the entirety of the period of data collection for the dumping investigation. Thus, while Committee of Anti-dumping Practices prescribed minimum three years as the period of data collection for injury assessment, it also specified that the same shall be subject to the condition that the party should have existed for at least such a long period. Thus, in a situation where the Domestic Industry has a history of its existence for less than the minimum prescribed period, it is evident that the Authority is entitled to consider such shorter period for which the Domestic Industry existed.
- 59. The Authority notes that in the case of new industries, the test of material retardation is required to be applied. The legal mandate is to evaluate, whether the establishment of the domestic industry is retarded by the imports into India. The examination for material retardation can thus be done only for the period during which the domestic industry existed.

60. In the present case, the Applicant commenced commercial production in July 2017 and therefore information for 3-year period is admittedly not available. However, considering that the period is lower than 3-year period, the Applicant has provided information on quarterly basis. On this basis, it is considered that it would be appropriate in the facts and circumstances of the present case to examine whether dumped imports caused material retardation to the establishment of the domestic Industry by considering the actual performance of domestic Industry over the period of its existence and by undertaking quarterly analysis.
61. Since the Applicant is a new producer in the country and commenced commercial production in the injury period itself, the performance of the Domestic Industry could have been impacted by the start-up operations. In order to remove injury effect on account of start-up operations, it was considered appropriate to evaluate the performance of the domestic industry during POI, derived on notional basis by considering 100% capacity utilization.

I. Cumulative assessment

62. Article 3.3 of WTO agreement and Annexure-II para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
63. The Authority notes that:
 - a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports as can be seen from the relevant table.
 - c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst subject countries.
64. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from China PR and Korea RP on the domestic industry.
65. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules.
66. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and the exporters/importers/traders/users on injury to the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
67. Since the Applicant has commenced its commercial production only in the period of investigation, the Authority has considered that it would be better to conduct quarterly analysis of the injury parameters as well.

II. Volume Effect of dumped imports and impact on domestic Industry**i. Assessment of Demand**

68. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the Applicant and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI (A)	POI
Sale of domestic industry	MT				***	***
Subject imports	MT	10,256	21,240	29,583	41,673	62,509
Other imports	MT	69,357	88,098	62,642	89,784	1,34,676
Total Demand	MT	79,612	1,09,338	92,224	***	***
Trend	Indexed	100	137	116	170	255

Particular	Unit	Q1 2017- 18	Q2 2017- 18	Q3 2017- 18	Q4 2017- 18	Q1 2018- 19	Q2 2018- 19	Total
Sale of domestic industry	MT	***	***	***	***	***	***	***
Subject imports	MT	7,582	9,548	12,274	11,213	12,347	9,547	62,509
Other imports	MT	23,356	23,326	19,406	19,525	26,571	22,492	1,34,676
Total Demand	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	105	103	131	111	

69. The Authority notes that the demand of the subject goods has increased vis-à-vis the base year.

ii. Imports volumes and share of the imports from subject countries

70. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analyzed as under –

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI (A)
1	China PR	MT	10,256	21,238	29,581	35,403
2	Korea RP	MT	0	1.9	2.05	6,270
3	Subject imports	MT	10,256	21,240	29,583	41,673
4	Other imports	MT	69,357	88,098	62,642	89,784
5	Total imports	MT	79,612	1,09,338	92,224	1,31,457
6	Subject imports in relation to					
a	Indian production	%				***
	Range					0-2000
b	Indian Consumption	%	13%	19%	32%	***
	Range					30-40
c	Total Imports into India	%	13%	19%	32%	32%

S.N.	Particulars	Unit	Q1 2017-18	Q2 2017-18	Q3 2017-18	Q4 2017-18	Q1 2018-19	Q2 2018-19
1	China PR	MT	7,441	9,412	11,375	9,242	9,223	6,412
2	Korea RP	MT	141	136	899	1,971	3,124	3,135
3	Subject imports	MT	7,582	9,548	12,274	11,213	12,347	9,547
4	Other imports	MT	23,356	23,326	19,406	19,525	26,571	22,492
5	Total imports	MT	30,938	32,873	31,680	30,737	38,918	32,038
6	Subject imports in relation to							
a	Indian production	%	***	***	***	***	***	***
	Range		5000-7000	4000-6000	1000-3000	1000-3000	0-2000	0-2000
b	Indian Consumption	%	***	***	***	***	***	***
	Range		10-30	10-30	30-50	30-50	20-40	20-40
c	Total Imports into India	%	25%	29%	39%	36%	32%	30%

71. It is seen that-

- Imports from subject countries have increased during the entire injury period and the POI in absolute terms. Even on quarterly basis, imports have increased throughout except during the last quarter (Q2 of 2018-19).
- The imports from subject countries have witnessed substantial increase in relation to total imports and consumption in India. Even on quarterly basis imports remained significant from subject countries.

III. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

72. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization and non-injurious price of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

i. Price undercutting

73. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the net sales realization of the domestic industry for the period of investigation. Separate analysis has been done for CPVC resin and CPVC compound.

		CPVC Resin					
S.N.	Period	Import Volume	Selling Price (Rs/Kg)	Landed Price	Price Undercutting	Price Undercutting	Price Undercutting
		MT	Rs./ Kg	Rs./ Kg	Rs./ Kg	%	Range
	POI (18 months)	61,475	***	92.98	(***)	(***)	(0-10)
1	2017-18 Q1	7,416	***	93.54	***	***	10-20
2	2017-18 Q2	9,345	***	91.44	(***)	(***)	(0-10)
3	2017-18 Q3	11,983	***	91.75	***	***	0-10
4	2017-18 Q4	11,090	***	91.15	(***)	(***)	(0-10)
5	2018-19 Q1	12,258	***	93.52	***	(***)	(0-10)

6	2018-19 Q2	9,384	***	97.10	(***)	(***)	(0-10)
S.N.	Period	CPVC Compound					
		Import Volume	Selling Price (Rs/Kg)	Landed Price	Price Undercutting	Price Undercutting	Price Undercutting
		MT	Rs./ Kg	Rs./ Kg	Rs./ Kg	%	Range
	POI (18 months)	1,034	***	149.46	(***)	(***)	(0-10)
1	2017-18 Q1	166	***	151.93	(***)	(***)	(0-10)
2	2017-18 Q2	203	***	152.64	(***)	(***)	(10-20)
3	2017-18 Q3	291	***	149.06	(***)	(***)	(10-20)
4	2017-18 Q4	123	***	149.06	(***)	(***)	(0-10)
5	2018-19 Q1	89	***	139.24	(***)	(***)	(0-10)
6	2018-19 Q2	163	***	149.57	(***)	(***)	(0-10)
S.N.	Period	Average					
		Import Volume	Selling Price (Rs/Kg)	Landed Price	Price Undercutting	Price Undercutting	Price Undercutting
		MT	Rs./ Kg	Rs./ Kg	Rs./ Kg	%	Range
	POI (18 months)	62,509	***	93.91	(***)	(***)	(0-10)
1	2017-18 Q1	7,582	***	94.81	***	***	10-20
2	2017-18 Q2	9,548	***	92.74	(***)	(***)	(0-10)
3	2017-18 Q3	12,274	***	93.11	***	***	0-10
4	2017-18 Q4	11,213	***	91.79	(***)	(***)	(0-10)
5	2018-19 Q1	12,347	***	93.85	***	(***)	(0-10)
6	2018-19 Q2	9,547	***	98.00	(***)	(***)	(0-10)

74. It is seen that the price undercutting is negative during the POI.

ii. Price suppression and depression.

75. In order to determine whether the dumped imports are causing price suppression or depression effect in the prices of the domestic industry, the Authority has considered the changes in the costs and prices over the period of investigation as compared to the landed price of imports. Further, cost of production has been computed at optimum cost of production by taking 100% capacity utilization because the actual costs are quite high due to low volume of production. The comparison of cost of sales and with selling prices has been undertaken in light of prevailing landed value of the imports as in the table below. Separate analysis has been done for CPVC resin and CPVC compound.

S.N.	Particulars	Unit	POI	
			Resin	Compound
1	Cost of sales (Actual)	Rs/Kg	***	***
2	Cost of sales (Optimum)	Rs/Kg	***	***
3	Selling price	Rs/Kg	***	***
4	Landed Price	Rs/Kg	92.98	149.46

S.N.	Period	POI- Actual				
		Cost of sales (Actual)		Selling Price		Landed Price
		Rs/Kg	Trend	Rs/Kg	Trend	Rs/Kg
1	2017-18 Q1	***	100	***	100	94.81
2	2017-18 Q2	***	107	***	83	92.74
3	2017-18 Q3	***	103	***	86	93.11
4	2017-18 Q4	***	104	***	85	91.79
5	2018-19 Q1	***	105	***	87	93.85
6	2018-19 Q2	***	104	***	83	98.00
POI at 100%						
S.N.	Period	Cost of sales		Selling Price		Landed Price
		Rs/Kg	Trend	Rs/Kg	Trend	Rs/Kg
1	2017-18 Q1	***	100	***	100	94.81
2	2017-18 Q2	***	97	***	83	92.74
3	2017-18 Q3	***	96	***	86	93.11
4	2017-18 Q4	***	97	***	85	91.79
5	2018-19 Q1	***	98	***	87	93.85
6	2018-19 Q2	***	99	***	83	98.00

76. It is seen that -

- Selling price of the domestic industry is far below its actual cost of sales and even below its optimum cost of sales.
- Landed value of imports is lower than the actual cost of sales and optimum cost of sale.
- The domestic industry is unable to recover even the cost.
- The cost and selling price trends on quarterly basis suggest that the imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry.

iii. Price underselling

77. The Authority has also examined the price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries. For this purpose, the non-injurious price determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports. The capacity utilization has been optimized at 100% for the computation of NIP.

S.N.	Particulars	Unit	Resin	Compound
A	China PR			
1	Import Volume	MT	52,381	723
2	Non-Injurious Price	Rs/Kg	***	***
3	Landed Value	Rs/Kg	92.41	154.52
4	Price Underselling	Rs/Kg	***	***
5	Price Underselling	%	***	***
6	Price Underselling	Range	50-60	20-30
B	Korea RP			
1	Import Volume	MT	9,094	311

2	Non-Injurious Price	Rs/Kg	***	***
3	Landed Value	Rs/Kg	95.01	136.99
4	Price Underselling	Rs/Kg	***	***
5	Price Underselling	%	***	***
6	Price Underselling	Range	50-60	30-40

78. It is seen that the price underselling is positive and significant for both Resin and Compound from each of the subject countries.

79. The injury margin for cooperative producers/exporters are evaluated as under: -

S.N .	Particulars	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	(%)	(Range)
A	China PR					
		Resin				
1	Shangdong Gaoxin Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	40-60
2	Shangdong Pujie Rubber and Plastic Co Ltd	***	***	***	***	50-70
3	Shandong Xiansheng New Material Technology Co Ltd	***	***	***	***	40-60
4	Wei fang Sundow Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	40-60
5	Shangdong Xuye New Material Co Ltd	***	***	***	***	50-70
6	All others	***	***	***	***	40-60
		Compound				
1	Shangdong Gaoxin Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	0-20
2	Shangdong Pujie Rubber and Plastic Co Ltd	-	-	-	-	-
3	Shandong Xiansheng New Material Technology Co Ltd	-	-	-	-	-
4	Wei fang Sundow Chemical Co. Ltd	-	-	-	-	-
5	Shangdong Xuye New Material Co Ltd	***	***	***	***	20-40
6	All others	***	***	***	***	20-40
B	Korea RP					
		Resin				
1	All producers/exporters	***	1,431	***	***	40-60
		Compound				
1	All producers/exporters	***	2,061	***	***	20-40

IV. Economic parameters of the domestic industry

80. Annexure-II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin

of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of the performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

81. The Applicant is a new industry and has started its commercial production in April 2017. The economic parameters have been analyzed for the period of investigation and the trends have also been analyzed on quarterly basis.

a. Capacity, Capacity Utilization, Production and sale

82. The domestic industry has set up facilities to manufacture CPVC resin and CPVC compound. For calculating the capacity utilization of the plant, the Authority has converted production of compound into equivalent resin production which has been used for analysis of the performance of the domestic industry. The details are as shown in table below:

S.N.	Particulars	Capacity	Equivalent resin production	Trend	Capacity Utilization	Trend	Production (Resin and Compound)	Trend	Domestic Sales (Resin and Compound)	Trend
		MT	MT	Indexed	%	Indexed	MT	Indexed	MT	Indexed
1	2017-18 Q1	2,500	***	100	***	100	***	100	***	100
2	2017-18 Q2	2,500	***	150	***	140	***	161	***	1,175
3	2017-18 Q3	2,500	***	593	***	560	***	633	***	7,467
4	2017-18 Q4	2,500	***	699	***	660	***	746	***	8,233
5	2018-19 Q1	2,500	***	1,637	***	1,540	***	1,691	***	13,608
6	2018-19 Q2	2,500	***	1,625	***	1,540	***	1,698	***	18,150

83. It is seen that -

- The production and capacity utilization of the domestic industry have increased during the period of investigation. However, the same was natural on account of the commencement of the plant in the period of investigation.
- It is also noted that there is a significant idle capacity with the domestic industry considering the demand in India.
- On average basis, the capacity utilization of the domestic industry is 38%, which is quite low.

b. Market Share

84. The market share of the domestic industry on quarterly basis during the POI is as under:

S.N.	Particulars	Imports from Subject countries	Imports from Other Countries	Sales of DI	Demand	Share of DI	Share of subject countries	Share of Other countries
		MT	MT	MT	MT	Range	Range	Range
1	2017-18 Q1	7,582	23,356	***	***	0-10	20-30	70-80
2	2017-18 Q2	9,548	23,326	***	***	0-10	20-30	70-80
3	2017-18 Q3	12,274	19,406	***	***	0-10	30-40	60-70

4	2017-18 Q4	11,213	19,525	***	***	0-10	30-40	60-70
5	2018-19 Q1	12,347	26,571	***	***	0-10	30-40	60-70
6	2018-19 Q2	9,547	22,492	***	***	0-10	20-30	60-70

85. It is seen that-

- In the initial two quarters, the share of domestic industry was quite low. It increased thereafter. However, the share of the domestic industry remained insignificant.
- The share of the subject imports has been significant and increased from Q1 of 2017-18 to Q3 of 2017-18 and then declined.
- The share of the other countries has declined up to Q3 of 2017-18 and then increased.

c. Profits, PBIT, return on investment and cash flow

86. Analysis of the performance of the domestic industry with regard to actual profit/loss, cash profits, PBIT (Profits before Income and Tax) and return on investment are given in the table below. Since the plant is a new facility where production commenced only during the period of investigation and with the actual production of the domestic industry below its projection levels, the Authority has determined profit parameters after considering 100% capacity utilization during the period of investigation.

S.N.	Period	Cost of sales	Selling Price	Profit/ Loss	Profit/ (Loss)	Cash profits	PBIT	ROCE
		Indexed	Indexed	Indexed	Indexed	Indexed	Indexed	Range
		Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Lacs	Rs/Lacs	Rs/Lacs	%
1	2017-18 Q1	100	100	(100)	(100)	100	100	0-10
2	2017-18 Q2	97	88	(164)	(164)	(217)	(289)	(0-10)
3	2017-18 Q3	96	92	(126)	(126)	(27)	(55)	(0-10)
4	2017-18 Q4	97	92	(131)	(131)	(55)	(90)	(0-10)
5	2018-19 Q1	98	93	(142)	(142)	(119)	(284)	(0-10)
6	2018-19 Q2	99	95	(136)	(136)	(93)	(252)	(0-10)

87. It is seen that -

- The domestic industry has not been able to sell its product at prices above the cost of production and hence has been running into losses.
- Cash profit has also followed the same trend as that of PBIT. While the first quarter of the period of investigation recorded cash profits, the domestic industry has run into cash losses in all the other quarters of the period of investigation.
- Consequently, the domestic industry earned positive but minimal return on capital employed in the first quarter of period of investigation but has earned a negative return consistently thereafter.

d. Employment, Wages and Productivity

88. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as in the table given below.

Parameters	Unit	POI-A
No of Employees	Nos.	***
Wages	Rs. Lacs	***
Productivity per day	MT/Day	***
Productivity per Employee	MT/Nos	***

89. It can be inferred from the quarterly production data given above that the productivity per employee has improved.

e. Inventory

S.N.	Quarter	Average	
		MT	Indexed
1	2017-18 Q1	***	100
2	2017-18 Q2	***	113
3	2017-18 Q3	***	99
4	2017-18 Q4	***	69
5	2018-19 Q1	***	104
6	2018-19 Q2	***	132

90. It is seen that inventory has increased in the last quarter as compared to the first quarter.

f. Growth

91. The Authority notes that the Applicant has set up new capacities in the face of large existing and future demand but has not been able to reach optimum levels of production, sales and capacity utilization.

g. Magnitude of Dumping

92. The dumping margin determined in respect of the producers/exporters from the subject countries is significant for the period of investigation.

h. Factors Affecting Domestic Prices

93. Imports from subject countries are at a price materially below the cost of production and non-injurious price of the domestic industry. Since the only competition to the domestic industry is imports and the domestic industry is new producer in the country, it is the import price that is solely responsible for the prices offered by the domestic industry. The imports from other countries are at much higher prices.

i. Ability to raise capital investment

94. Despite fresh investments in India in the product and sufficient demand in the country, the performance of the domestic industry is adverse. The negative profitability, cash losses, negative return on capital employed indicates that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector is hampered due to the dumped imports from the subject countries.

V. Post POI Analysis

95. Other interested parties have argued that the Authority should also examine the post POI situation of the domestic industry as at the time of initiation of the investigation, the domestic industry had only 18 months of history and after that domestic industry has completed more than a year by now. Considering, the domestic industry as nascent industry at the time of initiation of the case, the Authority has examined the post POI imports, demand, market share and performance of the domestic industry. Post POI analysis has been considered from Oct. 18 to Sept. 19. The data as provided by DI has been considered for the analysis.

a. Imports volumes and share of the imports from subject countries

96. The table below shows import volume from subject countries and other countries during Post POI-

S.N.	Particulars	Unit	Post POI
A	Import Volume		
1	Subject Countries	MT	42,950
2	Other Countries	MT	91,781
3	Total import volume	MT	1,34,731
B	Market Share in Imports		
1	Subject Countries	%	32%
2	Other Countries	%	68%
3	Total Share in total import volume	%	100%

97. It is seen that the imports from subject countries have further increased in absolute terms in post POI.

b. Demand and Market Share

98. The table below shows demand and market share of domestic industry, subject countries and other countries during Post POI-

S.N.	Particulars	Units	POI (A)	Post POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***
2	Imports from Subject Countries	MT	41,673	42,950
3	Import from Other Countries	MT	89,784	91,781
4	Total Demand	MT	***	***
5	Share in Demand of			
a	Domestic Industry	%	0-10	0-10
b	Subject Countries	%	30-40	20-30
c	Other Countries	%	60-70	60-70
d	Total	%	100	100

99. It is seen that the demand has shown rising trend in Post POI. The share of the domestic industry has increased whereas share of the subject countries has declined marginally (less than 1%). The share of other countries has also declined.

c. Performance parameters of the domestic industry

100. The table below shows the relevant parameters of the domestic industry during post POI.

S.N.	Particulars	Unit	Post POI
1	Capacity	MT	10,000
2	Equivalent Production	MT	***
3	Capacity Utilization	%	***
4	Domestic Sales - Resin	MT	***
5	Domestic Sales - Compound	MT	***
6	Market Share	%	***
7	Profit/(loss)	Rs/MT	(***)
8	ROI	%	0-10
9	Cost of Sales	Rs/MT	***
10.	Selling Price	Rs/MT	***

101. It is seen that the production, sales and capacity utilization of the domestic industry has increased although lower than the optimum. The selling price of the domestic industry is still lower than the cost of sales during post POI and as a result, the domestic industry is incurring losses. The ROI of the domestic industry has become positive but is way below optimal level.

VI. Conclusions on Injury

102. The examination of the of the imports of the subject product and performance of domestic industry shows that: -

- The subject imports have increased in absolute and relative terms despite fresh investment in the country.
- There is negative price undercutting accompanied with loss suggesting that the domestic industry has been forced to sell at low prices to survive in the market.

- c. The imports have forced the domestic industry to sell at prices below the cost of the industry.
- d. The production and sales of the domestic industry despite increase over the period remains considerably low vis-à-vis domestic demand.
- e. The imports are at a price below cost of production and NIP of the domestic industry.
- f. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on investments. The performance of the domestic industry has suffered adversely during the period of its existence and its performance is far below the targeted/projected levels and its establishment is being materially retarded by dumping of the product from subject country.
- g. During post POI, there is an improvement in the performance of the domestic industry in terms of volume parameters whereas price parameters are still negative despite marginal improvement.

VII. Other known factors and causal link

103. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Anti-Dumping Rules.

a. Volume and prices of imports from third countries

104. While the imports from European Union, Japan, Thailand and United States of America are above the de-minimis level, there is a significant price difference in the imports from the subject countries and non-subject countries. The price of the imports from non-subject countries are significantly higher and appear to be fair priced. These imports do not appear to be affecting the performance of the domestic industry. The Authority holds that the domestic industry has not suffered injury as a result of imports from non-subject countries.

b. Contraction in demand

105. Since the demand for the product under consideration has increased over the injury period, the domestic industry has not suffered injury on this account.

c. Changes in the pattern of consumption

106. The Authority has not found any possible changes in pattern of consumption, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers.

107. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

108. The Authority notes that the investigation has not shown any change in technology for production of the product, which could have caused injury to the domestic industry.

f. Export performance

109. The Applicant has not exported the product under consideration. Hence, claimed injury to domestic industry cannot be attributed to exports.

g. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry:

110. The Applicant is a multiproduct company; however, the cost and financials data have been segregated and considered only for PUC and analyzed for the present investigation.

VIII. Conclusion on Causal link

111. The other factors have not caused any injury to the domestic industry. The Authority holds that the injury to the domestic industry has been caused only because of the dumped imports from the subject countries.

L. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS

112. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Most of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and addressed appropriately in the relevant parts(s) above of this Final Finding. Additional submissions have been analysed as under:

IX. Submissions made by the domestic industry

113. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement are as follows:-

- a. The primary production involved is in production of resin. Production process from resin to compound is a minor incremental process undertaken to make the product usable and it does not transform the essential characteristics of product.
- b. CPVC resin has no independent use and has to be compulsorily processed into compound.
- c. Level of investment in compounding is not significant. The major investment is in making resin. The compounding process is neither high-tech automated process nor highly skilled manpower process.
- d. Even in past investigations, Authority has considered the product and its prior or subsequent/ processed stage as one article.
- e. The tariff classification for the product under consideration has undergone change and the new classification is 3904 9010.
- f. The imports of CPVC compound from the countries like Sri Lanka and UAE, which do not have production facility for resin, should also be subject to antidumping duty in India if CPVC resin has been exported to that country from Korea or China.
- g. If anti-dumping duty is not charged on the resin component of the article imported from countries not manufacturing resin, the importers will start sourcing the imports from such sources.
- h. Barring the petitioners, no interested party has made any suggestion for appropriate market economy third country for determining normal value for China. Out of the available options of EU, Japan, Thailand and USA, Thailand is the most appropriate country for present purpose.
- i. M/s Hanwha Chemical Corporation has suppressed information in the response filed by it. Information of the research activities undertaken by the company has been hidden from the Authority. Hanwha was producing CPVC and did not have the technical expertise to manufacture the product. As per the website of the company, it has been awarded standards by the Korean Agency of Technology for its CPVC manufacturing technology. Thus, the respondent (exporter) must have incurred significant cost in the development of the technology and this cost should have been charged to the product.
- j. Hanwha produces caustic soda, chlorine, PVC suspension resin, hydrogen, steam and power captively and there is nothing in the response for valuation to demonstrate how the prices indicated in the response represent market price.
- k. Hanwha has an office in India through which it undertakes sales activities. This fact has been hidden from the response.
- l. The response filed by it does not meet the standards of the trade notice issued by DGTR and the AD Rules.
- m. The domestic selling price and the cost of production of Hanwha cannot be accepted since they are not in ordinary course of trade.
- n. As per Supreme Court order in case of Ministry of Commerce vs M/s. Haldor Topsoe, when information with regard to the prices prevailing in the subject country is available, Authority cannot choose other options for normal value.
- o. CESTAT in the matter of Universal Chemicals had held that verification should only be conducted when the exporter has cooperated to the best of its ability.
- p. It is a global practice to reject the response in case there is material change in the data.
- q. The Authority should propose ad-valorem form of duty as benchmark duty fails to serve the purpose. Exporters keep price of the product artificially high to avoid benchmark form of anti-dumping duty.
- r. There is no mechanism with the custom authorities nor is it practicable to verify the overpricing or ensure correctness of prices.
- s. There is a significant difference in the price and the cost of both the products, therefore fixed form of duty will lead to overprotection of resin and under protection for compound.

X. Submissions made by other interested parties

114. The submissions made by the other interested parties on the disclosure statement are as follows:-

- i. Usability of a product is an “essential characteristic” in itself. The fact that CPVC Resin is useless without compounding, and the product which has utility is CPVC Compound, means that the value addition in compounding is significant and leads to change in the usability characteristic.
- ii. For example- In the investigation concerning import of Ammonium Nitrate, Ammonium Nitrate Melt was not regarded as “like product”, even though the imported product- Ammonium Nitrate in granular form was necessarily required to be converted into Ammonium Nitrate Melt so that it had “usability” in its industrial application.
- iii. To consider the tariff code of the subject goods as an identifier of the “incremental” nature of “compounding” process is not correct. Further, merely falling under the same “tariff heading” does not mean that two products may be treated as having identical characteristics.
- iv. The Authority has stated that the end-use markets for the intermediate product, CPVC Resin, and the end-product, CPVC Compound, are essentially the same. This is not true as the buyers of resin and the buyers of compound are distinct, have different capacities and sell their product to different markets.
- v. The chemical structures being identical is not a criterion for treating two products as “identical” for the purpose of PUC / like article. In this regard, reliance is again placed on the Authority’s stance in the Ammonium Nitrate investigation.
- vi. The Authority has failed to consider that the ratio of CPVC Resin and CPVC Compound entering from China PR and Korea RP are distinct. It also failed to consider that two products (admittedly different products) cannot be combined and assumed to be one product for cumulative assessment.
- vii. The Authority has simply stated that it is “essential” for the producer to be a Resin manufacturer and not just a compound manufacturer for the purpose of scope of domestic industry and standing. This line of reasoning is circular. We request the Authority to clarify why it is “essential” for the producer to be a manufacturer of CPVC Resin regardless of whether or not they produce CPVC compound or not.
- viii. The Petitioner is a manufacturer of MPVC and therefore, it is unclear why the cost of importation is being incurred by the Petitioner. The Authority must examine and reveal how such importation over captive consumption impacts the costs of the Petitioner.
- ix. It is also relevant to examine why a manufacturer of MPVC imports the same from foreign sources and the nature of the transaction therein and the associated costs thereof.
- x. It is suspected that the reason for such importation is the execution of a technical license agreement between the Petitioner and Arkema, France which mandates the imports of MPVC from France. The Authority should examine the Petitioners’ import prices of MPVC. This exercise is mandatory in order to ensure that the cost (and even the NIP) is not unduly inflated.
- xi. The Authority’s preliminary finding failed to comply with the requirement of making a “ further determination” as under Section 9B(1)(b)(iii) it is provided that the Central Government shall not levy anti-dumping duty under 9A(2) unless a preliminary finding has been made of dumping and consequent injury to domestic industry and a further determination has been made that a duty is necessary to prevent injury being caused during the investigation
- xii. It is highly arbitrary to choose a data set simply because it shows a higher volume of imports, without even assessing the data. The Authority appears to believe that this is a rationale for choosing one data set over the other.
- xiii. After the Preliminary Finding, the Authority has realized that the data of DG Systems contained certain reportage which were duplicates of each other and merit exclusion anyway.
- xiv. Such a cumulation “hides” the significantly low volume of CPVC Compound imports from both the subject countries.
- xv. If at all the Authority recommends the imposition of anti-dumping duties in the present case, the Authority must recommend a benchmark-price based duty rather than a fixed duty which would be unduly burdensome to the users and importers of the subject goods;
- xvi. If at all the Authority recommends the imposition of anti-dumping duties in the present case, the Authority must ensure that the recommendation of duty is for a limited period of time such that the Petitioner may continue to receive some protection while also completing a reasonable amount of time

- with performance, enabling the Authority a fuller and better opportunity to realistically assess its market position and injury.
- xvii. Duty should be recommended in ad-valorem form as imposition of duty in benchmark form would not be proper as the price of PUC is volatile and not stable.
 - xviii. Imposition of benchmark form of duty would lead to increasing duty in the future and may even lead to duty being higher than the margin of dumping.
 - xix. In the original response, HCC provided the details of consumption quantity of PVC Suspension used for PUC production whereas in second supplementary response, HCC provided the production quantity of PVC Suspension as well as consumption quantity used to produce CPVC during the POI.
 - xx. The argument regarding the change in the production of PVC Suspension has been raised by DGTR at 'later stage'. The DGTR did not ask any clarification regarding the same during the whole investigation process
 - xxi. Though HCC did not provide complete cost items as prescribed by DGTR in the questionnaire in the original response submission, HCC provided the complete information of Appendix-7 in the 2nd supplemental response according to the instruction of 2nd deficiency letter.
 - xxii. HCC reported in the 2nd supplemental response its cost on the basis of the cost elements maintained by HCC's normal cost accounting system which are in accordance with the K-GAAP as well as DGTR's request in the 2nd deficiency letter. So, there is no ground for DGTR to determine that the HCC's reported cost is unreliable or deniable.
 - xxiii. In the second deficiency letter issued, DGTR has requested HCC to match Appendix-7 with Appendix-9. Therefore, to comply with the instructions of DGTR, HCC had to change Appendix-7 by applying the ratios of SG&A, non-operating income/expense and financial income/expense to sales value rather than COGS which was used in HCC's original response and 1st supplemental response. The change in the profit/(loss) company-wise or PUC wise is not what HCC intended.
 - xxiv. Though DGTR has sufficient chances of on-site verification on HCC for the time period between 2nd supplemental response dated on October 24, 2019 and the issuance of disclosure statement on January 29, 2020 (more than 3 months), DGTR itself neglected its duty to conduct the verification on the cooperating respondent, HCC and unduly deprived HCC of its right to defend HCC's position without proper notice by DGTR.
 - xxv. There is no ground or indication in the Disclosure Statement relating to HCC's export price which HCC's response in terms of export price should be rejected in the dumping margin calculations. In the final finding, the export price should be based on HCC's reported export price rather than import data.
 - xxvi. Certain errors which have crept into the calculation of "landed value" for Shandong Gaoxin Chemical Co., Ltd. and Shandong Pujie Rubber and Plastic Co. Ltd. These are to be rectified.
 - xxvii. Certain parties are not exporting CPVC Compound during the POI, and therefore, the Authority must expressly reserve their right to apply for New Shipper Review of these parties.
 - xxviii. The Authority has not revealed how it compared the level of development of the product and the country for the purpose of determining the appropriate market economy third country.
 - xxix. Further, the Authority, as per paragraph 7 of Annexure-I of the AD Rules, is required to consider not just the level of development of the product and country but also take "due account of any reliable information made available at the time of the selection".
 - xxx. The burden of selection of market economy third country, including the suggestion for the same, falls on the Authority and not upon the parties to the investigation.
 - xxxi. The Authority has shifted its investigative function to the interested parties, and then when the parties have failed to fulfil that unwarranted mandate, punitively chosen Thailand as a surrogate country out of the suggestions of the Petitioner.
 - xxxii. The Authority appears to assume that having comparable volume of sales to India shows a comparableness between products originating in two different countries.
 - xxxiii. Duty-free Thai goods have a significant 7.5% margin advantage as compared to the duty-paid goods from China PR. As such, it is natural that the Thai prices would be about 7.5% higher than the prices of the imports from China PR. This is an important reason why Thai prices are incomparable with Chinese prices making Thailand an inappropriate surrogate country.

- xxxiv. Thai import price reported to the customs Authorities would show a marked difference in related party transaction prices and unrelated party transaction prices. The Authority has not even examined whether the same is evidenced by the import data under consideration. Instead, the Authority has attempted to claim that a mere relationship between the related parties does not mean that a price is unreliable.
- xxxv. The Authority has considered the volume of sales and pricing for an unrelated and non-participating exporter in determination of ex-factory export price for the Shandong Gaoxin Chemical Co., Ltd. and Shandong Pujie Rubber and Plastic Co. Ltd. The same is also being incorporated in the determination of the dumping margin with respect to these producers.
- xxxvi. The Authority may clarify the rationale for such a consideration even though majority of the sales to India have been made via direct route, and not via unrelated exporters. The Authority should grant the level of adjustment.
- xxxvii. There was no adequate notice to the interested parties of consideration of Thailand as a surrogate third country market economy for China. The statement in the initiation notice was only a reproduction of the claims of the domestic industry.
- xxxviii. Para 7 of Annexure-I mandates Authority to inform interested parties about third country market economy post the selection of the country so that the interested parties can comment on the selection.
- xxxix. Other factors considered by the authority for selection of appropriate market economy third country are not relevant.
- xl. The Authority should have directed the related importer to file a response in order to establish that the transactions are at arm length's price.
- xli. Exports from Thailand to all the countries must be considered for determining the normal value as it would be more reflective price.
- xl.ii. The Authority appears to be concerned about the likelihood of imports of CPVC compound from the subject countries, in the future, in case of imposition of duties against CPVC Resin only. However, such a situation is commonplace in anti-dumping investigations and there is always a chance that imposition of duties against one good would lead to increased imports of an upstream or downstream product.
- xl.iii. This is simply a case where the Petitioner is suffering from high costs of production owing to its licensing agreement, delay in starting production, requirement under the licensing agreement to source PVC from Arkema France, etc.
- xliv. ROCE has been considered at 22% on average capital employed. However, ROCE for a nascent and unestablished industry cannot be at the same level as that for an established and fully functional industry. The Authority must consider a lower ROCE for the purposes of NIP.
- xl. The Designated Authority was required to examine whether M/S DCW Limited is established or not. The respondent has demonstrated that the M/S DCW Limited is an established industry.
- xlvi. The selection of 18-month period of investigation has led to inflated non-injurious price. The period of investigation includes period of setting of industry.
- xl. The Authority should consider period post the period of investigation to determine NIP.
- xl. The Authority should examine the post period of investigation performance of the industry to examine injury.
- xl. The domestic industry was affected by problems regarding start-up phase of the company. The downward trend in the profitability, PBIT, ROI and cash flow cannot be attributed to subject imports but due to start-up phase of the domestic industry.
- l. DA has treated production, sales, capacity utilization, inventory and closing stock as confidential whereas the indexed data was provided by the petitioner in the petition.
- li. Hanwha Chemical Corporation requested the Authority to disclose the computation of dumping margin for Korea RP.

XI. Examination by Authority

115. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by interested parties are repetitive in nature and have already been addressed earlier in the relevant paras of this finding. Further the Authority has examined submission made by interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere:

- i. As regard the contention that CPVC Resin is useless without compounding, and the product which has utility is CPVC Compound meaning thereby that the value addition in compounding is significant leading to change in usability, the Authority notes that CPVC resin has no independent application and it has to be essentially converted into compound to make it usable and thus both types are meant for same end use. It is further noted that the reliance placed on Ammonium nitrate investigation is misplaced since Ammonium Nitrate melt was not even kept within the scope of PUC by the applicants. Moreover, no import of Ammonium Nitrate melt was made during the relevant period. It was recorded in the final finding of the said investigation that all interested parties were in agreement that Ammonium Nitrate melt cannot be imported as it is, without any change in its form. Therefore, the parallel drawn between these two investigations is inappropriate.
- ii. As regards the submission that product scope includes both CPVC resin and compound and compound is a value added product and hence should be treated as separate product, the Authority notes that to make practical use, CPVC resin is converted into compound and is not used as separate product per se except for making compound for its further use
- iii. With regard to the contention that taking tariff code of the subject goods as an identifier of the “incremental” nature of “compounding” process is not correct. and that merely falling under the same “tariff heading” does not mean that two products may be treated as having identical characteristics, it is noted that though tariff code in itself may not be the sole criteria to define likeness of products, yet the very fact that two products have the same tariff code at the eight digit level is an indicator that the process involved in conversion of one into another (CPVC resin into CPVC compound) is incremental.
- iv. As regard the contention that resin and compound cater to different markets, it is noted that CPVC resin does not have any independent use except for making CPVC compound and therefore both resin and compound ultimately have same end use.
- v. As regard the contention that the chemical structures being identical is not a criterion for treating two products as “identical”, the Authority notes that chemical structure is also an important criterion for determination of likeness of products.
- vi. As regard the contention that the Authority has failed to consider that the ratio of CPVC Resin and CPVC Compound entering from China PR and Korea RP are distinct and cumulative assessment of the same is not appropriate, the Authority notes that ratio of CPVC resin and CPVC compound exported from China PR and Korea is not relevant for cumulative assessment once both these have been treated as one product in present investigation. The only requirement for cumulative assessment under the Rules is to ascertain whether or not imported PUC is competing with the like article produced by the applicants and that whether PUC imported from subject countries are competing with each other.
- vii. With respect to the argument regarding non-essentiality for the producer to be engaged in manufacturing of CPVC resin, it is noted that CPVC resin making is essentially the core manufacturing activity and compound making is only an incremental activity. Hence the domestic producer is required to be engaged in CPVC resin making in order to be eligible domestic industry.
- viii. Some interested parties have argued that inclusion of downstream product within the scope of PUC is unjustified since there is always a chance that imposition of duties against particular product would lead to increase in imports of upstream or downstream product. In this regard, the Authority notes that in case of non-inclusion of CPVC compound within the fold of PUC in the present case, the chances of circumvention of anti-dumping duty would be very high on account of the fact that (a) compound making from CPVC resin stage is only an incremental activity and (b) the use of CPVC resin is exclusively for making CPVC compound.
- ix. In regard to the contention regarding comparison of cost of captively produced/ consumed MPVC with that of MPVC imported from France , it is noted that the domestic industry is not manufacturing MPVC and is only importing the same from France, which is being used for production of CPVC resin. Thus, the question of different raw material cost on account of imported vis-a-vis captive consumption does not arise. The Authority has determined the cost of production of PUC after verification of data of domestic industry.
- x. As regards the contention that the Authority’s preliminary finding failed to comply with the requirement of making a “ further determination” as under Section 9B(1)(b)(iii) it is provided that the Central Government shall not levy anti-dumping duty under 9A(2) unless a preliminary finding has been made of dumping and consequent injury to domestic industry and a further determination has been made that a duty is necessary to prevent injury being caused during the investigation, the Authority notes that it has issued the preliminary finding in accordance with law to protect the domestic industry from further injury pending investigation.

- xi. As regards the contention that it is highly arbitrary to choose a data set simply because it shows a higher volume of imports, it is noted that after issuance of the Preliminary Finding, the discrepancies between import data from DGCI&S and DG Systems were examined in detail and it was then noted that DG Systems data contained certain reportage which amounted to duplication. It was noted that imports reported through bills of entry filed for warehousing and bills of entry filed for home consumption only ought to have been considered to avoid double counting and consequently import data from DGCI&S only was taken into account and the same has been categorically explained in the disclosure statement. It is reiterated that the Authority has relied upon DGCI&S transaction-wise data only in the final finding.
- xii. As regards the contention that Authority should recommend the imposition of anti-dumping duties in the present case for a limited period to protect the domestic industry, the Authority notes that the anti-dumping duty is normally recommended for a period of 5 years. In any case, the Rule 23(1A) provides for mid-term review and interested party are free to seek a mid-term review in terms of Rule 23(1A).
- xiii. As regards the contention of interested parties in respect of the appropriate form of duty, the Authority notes that some interested parties have requested for a benchmark-price based duty rather than fixed duty whereas some interested parties have pleaded for ad-valorem form of duty. It is noted that at the time of preliminary finding the Authority had recommended benchmark form of duty. It is further noted that after examining the fresh contentions of the interested parties, the Authority finds it appropriate to continue the benchmark form of duty.
- xiv. With regard to various contentions made by the interested parties in respect of selection of appropriate market economy third country, it is noted that the interested parties have contended that Thailand cannot be considered as appropriate market economy third country in view of level of development, relationship with importer in India, difference in customs duties due to FTA. It is reiterated that the Authority is required to consider the level of development of the product and the country for determining appropriate market economy third country based on available evidence on record. The Authority notes that as far as the level of economic development is concerned none of the producers/exporters/importers/users has suggested any appropriate market economy third country. On the other hand, the domestic industry had suggested Thailand, Japan and U.S.A as appropriate market economy third country. Considering the options available viz. Japan, US or Thailand, the Authority notes that China PR and Thailand are more comparable in terms of level of economic development based on various economic parameters. It is further noted that Thailand has been considered as an appropriate market economy third country for China by other prominent trade remedy user WTO member countries. Besides, the level of import of the subject goods from China PR and Thailand are almost same, which goes to suggest the similar level of product development in both these countries. It is further noted that the difference in customs duty has no relevance since export price from Thailand to India at ex-factory level has only been considered for computation of normal value.
- xv. With regard to the contention of other interested parties that the import price from Thailand is unreliable due to related party transaction, the Authority notes that it has examined the DGCI&S data and found that imports made by importers other than Lubrizol are priced approximately 6% higher than the average import price from Thailand and that there is no marked difference in price levels. It is further noted that had the Authority excluded the volume of import made by Lubrizol, which other interested parties seem to suggest, then the import price and consequently normal value would have been higher leading to higher dumping margin thereby defeating the very logic advanced by other interested parties.
- xvi. As regards the contention that exports from Thailand to all the countries must be considered for determining the normal value as it would be more reflective price, the Authority has analyzed the World Trade Atlas (WTA) data to ascertain the export price from Thailand to other countries. It is noted that the separate export prices of CPVC resin and CPVC compound data however were not available in the WTA data on account of both these items, CPVC resin and CPVC compound, having same tariff code.
- xvii. With regard to argument of certain non-consideration of landing charges and cess component in landed price, the Authority has examined the same and has taken corrective action by considering them in landed price.
- xviii. With regard to the contention that volume of sales and price for unrelated non-participating exporter margin should not be taken into account for determining dumping margin since majority of sales have been made directly, it is noted that a rational approach has been adopted by the Authority in determining the margin by taking weighted average of individual rate/ margin to the extent of participation and residual rate to the extent of non-participation.

- xix. As regards the contention that the Authority has rejected level of trade adjustment without assigning any reason, it is noted that the Authority has analysed the export prices in USD in both channels on monthly basis and has come to the conclusion that there is absence of any definite pattern or trend in the prices requiring level of trade adjustment.
- xx. As regards the contention that Authority has incorrectly rejected the response filed by Hanwha, it is noted that the prescribed questionnaire requires the producer/ exporter to provide complete details. Hanwha has admitted that its initial questionnaire response was grossly deficient/incomplete and substantial portion of new information was provided in first and second supplementary response. It is noted that significant information was modified in the first and thereafter in the second supplementary response. Even the overall profit of the company as well as profit in respect of production and sale of the product under consideration have been changed by the company at different stages of response. As far as the issue of on the spot verification is concerned, the Authority notes that verification visit are usually not undertaken when the questionnaire response itself is rejected.
- xxi. It was also pointed out to Hanwa that Appendix-7 of the questionnaire response did not match with Appendix-9. They were also asked to provide element-wise details of SGA expenses. However, in response to deficiency letter, Hanwa has changed SGA expenses as well as profit of the company and PUC.
- xxii. Hanwa was also asked to provide details of all the products produced along with relevant production quantity & value, sales quantity & value as well as complete details of sales to outside parties. However, Hanwa provided only selective data/information and that to varied in different responses submitted by him
- xxiii. As regards the contention about non-grant of adequate opportunity, it is noted that Hanwa was given sufficient opportunity through issuance of two deficiency letters. It is further noted that elaborate questionnaire has been prescribed by the authority indicating specific requirements and participating foreign producer/ exporter is required to provide the information in the form and manner prescribed in the questionnaire. Respondent producer(s)/ exporter(s) is not expected to modify the questionnaire itself and provide the information in the manner they deem fit. It is however noted that Hanwha has modified the questionnaire itself at several places and provided information selectively.
- xxiv. As regards rejection of export price, it is noted that Hanwha did modify information with regard to selling and distribution cost. Further, the manner in which Hanwha has modified its information in first supplementary response and thereafter in second supplementary response itself raises doubts with regard to credibility and reliability of the information.
- xxv. Regarding the request made by Hanwha Chemical Corporation, to disclose the dumping margin computations, it is noted that the basis for determination of Normal Value for Korea RP has been elaborated at Para 47 above which clearly illustrates that the methodology adopted for the said computations is based on prices indicated in the invoices regarding export sales of PUC from Japan to Korea RP. Since confidentiality has been claimed on the sales data by the domestic industry and accepted by the Authority, the normal value and consequently dumping margin computations cannot be disclosed.
- xxvi. As regards the request of M/s Hanwha Chemical Corporation for change of name from Hanwha Chemical Corporation to M/s Hanwha Solutions Corporation, it is noted that the request was placed in the Public file for interested parties to offer their comments. No comment has been made by any of the interested parties. It is further noted that M/s Hanwha Chemical Corporation has not been able to substantiate that this merely involves a change of name without any change in ownership or equity holding.
- xxvii. Some interested parties have stated that certain parties are not exporting CPVC Compound during the POI, and therefore, the Authority must expressly reserve their right to apply for New Shipper Review of these parties. In this regard, it is noted that new shipper review can be filed by only those who have not exported PUC during the POI and are not related to the entities who have been given individual duty rates/ margin. Since PUC comprises of both CPVC resin and compound, the request is untenable. It is further noted that request of this nature hints at the possibility of shift from export of CPVC resin to CPVC compound in case both these are not brought under the ambit of PUC.
- xxviii. Some interested parties have stated that the Applicant is suffering from high costs of production owing to requirement under the licensing agreement to source PVC from Arkema France, delay in starting production etc. It is noted that Applicant being a new producer having commenced commercial production in the injury period itself, the performance of the Domestic Industry could have been impacted by the start-up operations. However, in order to offset the adverse effect on account of start-

up operations, it was considered appropriate to evaluate the performance of the domestic industry during POI, on notional basis by considering 100% capacity utilization.

- xxix. As regards the contention that the Authority must consider a lower ROCE for the purposes of NIP for a nascent and unestablished industry rather than @ 22% on average capital employed, it is noted that it is the consistent practice of the Authority to consider ROCE at 22% of capital employed.
- xxx. With regard to argument that the selection of 18-month period of investigation has led to inflated non-injurious price, the Authority notes that it has determined NIP in terms of Annexure-III for the entire period of existence of the domestic industry. It is further noted that to offset the impact of start-up cost, the cost of production has been determined by considering capacity utilisation @100%.
- xxxi. As regards the contention that the Authority should consider period post the period of investigation to determine NIP, the Authority notes that as per the statute, NIP and injury margin is required to be determined for the period of investigation only.
- xxxii. Some interested parties have contended that the domestic industry was affected by problems regarding start-up phase of the company and ,therefore, the downward trend in the profitability, PBIT, ROI and cash flow cannot be attributed to subject imports but due to start-up phase of the domestic industry. In this regard, it is noted that the injury, if any, caused due to start up problem has been nullified by determining cost of production taking capacity utilisation at 100% level.

XII. Indian industry's interests and other issues.

- 116. As regards the submissions regarding impact on user industry, the Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of antidumping measures is not to restrict imports from the subject countries in any way, and, to affect the availability of the products to the consumers.
- 117. The Authority also holds that though in the event of imposition of anti-dumping duties the price level of product in India may be affected but fair competition in the Indian market will not be reduced by such anti-dumping measures. On the contrary, the anti-dumping measures may mitigate the unfair advantage gained by dumping practices and would help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

XIII. Conclusion

- 118. After examining the submissions made and issues raised, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
 - (a) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below normal value.
 - (b) Such dumped imports of the subject goods from the subject countries have caused material retardation to the establishment of the domestic industry.

XIV. Recommendation:

- 119. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Rules and having positive dumping margin as well as injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.
- 120. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, for a period of five years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col 7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 7. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S.No.	HS Code	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Specification	Amount in USD/MT
1	2	3	4		5	6	7
1	39042110 39042190 39042210 39042290 39041090 39049000 39049010	Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin (CPVC) - whether or not further processed into compound	China PR	Any country including China PR	Shandong Gaoxin Chemical Co Ltd	CPVC Resin	2,087
			China PR	Any country including China PR		CPVC Compound	2,717
2			China PR	Any country including China PR	Shandong Pujie rubber and plastic Co. ltd	CPVC Resin	2,053
			China PR	Any country including China PR		CPVC Compound	2,853
3			China PR	Any country including China PR	Shandong Xiangsheng New Materials Technology Co., Ltd.,	CPVC Resin	2,045
			China PR	Any country including China PR		CPVC Compound	2,853
4			China PR	Any country including China PR	Weifang Sundow Chemical Co. Ltd	CPVC Resin	2,025
			China PR	Any country including China PR		CPVC Compound	2,853
5			China PR	Any country including China PR	Shandong Xuye Materials Co. Ltd	CPVC Resin	2,057
			China PR	Any country including China PR		CPVC Compound	2,657
6			China PR	Any country including China PR	Any Producer other than mentioned above	CPVC Resin	2,161
						CPVC Compound	2,853
7				Any country other than China PR and Korea	China PR	Any	CPVC Resin

			RP			CPVC Compound	2,853
8			Korea RP	Any country including Korea PR	Any Producer	CPVC Resin	2,024
						CPVC Compound	2,853
9			Any country other than China PR and Korea RP	Korea RP	Any Producer	CPVC Resin	2,024
						CPVC Compound	2,853

XV. Further Procedure

121. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority